वार्षिक रिपोर्ट

1989-90

NIEPA DC
D09370

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

250 प्रतियां

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 1991

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016
DOC, No. D-9370
Date 5.12.96

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के लिए कार्यवाहक कुल सचिव, नीपा द्वारा प्रकाशित तथा शगुन कंपोजर्स 92-बी, कृष्णा नगर, सफदर जंग इन्कलेव, नई दिल्ली-29 में लेजर टाइप सेट होकर, प्रभात आफसेट प्रेस, कूचा चेलान, दरिया गंज, दिल्ली-2 में मुद्रित।

विषय सूची

अध्याय

1.	सिंहावलोकन	1
2.	प्रशिक्षण	10
3.	अनुसंधान	22
4.	परामर्शकारी और अन्य सेवाएं	36
5.	अन्य अकादमिक गतिविधियां	39
6.	प्रकाशन, पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं	41
7.	प्रशासन और वित्त	46
8.	सातवीं योजना की उपलब्धियाँ	54

अनुबंध

I.	तालिकाएं (सातवीं योजना)	77
II.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी/कार्यशिविर	80
III.	प्रशिक्षण सामग्रियों की सूची	89
IV.	संकाय का अकादमिक योगदान	92
V.	समूह प्रशिक्षण के तैयार किए गए माड्यूलों की सूची	104
VI.	सातवीं योजना (1985-90) के दौरान चालू किए गए अनुसंधान अध्ययनों की सूची	105
VII.	सातवीं योजना के दौरान निर्मित अनियमित पत्रों की सूची	108

परिशिष्ट

I.	नीपा परिषद के सदस्य	109
II.	कार्यकारी समिति के सदस्य	112
III.	वित्त समिति के सदस्य	114
IV.	कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य	115
V.	संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ	118
VI.	वार्षिक लेखा और लेखा और परीक्षा रिपोर्ट	123

1989-90

अध्याय 1

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान मई 1979 तक शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से जाना जाता था। यूनेस्को के साथ एक करार के अंतर्गत सन् 1962 में स्थापित एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान का अधिग्रहण करके भारत सरकार ने सन् 1970 में राष्ट्रीय स्टाफ कालेज की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में की थी।

अपने कार्यकाल के ढाई दशकों के दौरान एक शीर्षस्थ संस्थान के रूप में नीपा ने शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवा की है।

संस्थान के प्रमुख कार्यों में शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शकारी और सलाहकारी सेवाएं नवाचारों का प्रचार-प्रसार और विशेष रूप से एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग और समन्वय शामिल हैं। इस रिपोर्ट में अप्रैल 1989 से मार्च 1990 तक की संस्थान की गतिविधियों का विवरण दिया गया है। यह वर्ष सातवीं योजना का अंतिम वर्ष है। वर्ष 1989-90 में संस्थान की गतिविधियों के कुछ मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं :

1.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर/संगोष्ठी/डिप्लोमा

संस्थान ने वर्ष 1989-90 के दौरान 60 पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर/संगोष्ठी और डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किए।

1.1.1 भागीदारी

इस वर्ष के दौरान भागीदारों की कुल संख्या 1824 थी। इनमें राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 1544; भारत सरकार, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के 231 और अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा 22 देशों के 49 भागीदार थे। भागीदारों में विभिन्न स्तर के व्यक्ति शामिल थे।

सबसे अधिक क्षेत्रवार भागीदारी दक्षिणी क्षेत्र (498) की थी। इसके बाद क्रमशः उत्तरी क्षेत्र (425), पूर्वी क्षेत्र (318), पश्चिमी क्षेत्र (303)

राज्यवार भगीदारी में पहला स्थान तमिलनाडु (305) का था। इसके बाद क्रमशः मध्यप्रदेश (117), दिल्ली (113), गुजरात (99), आंध्रप्रदेश (87), उत्तर प्रदेश (86), महाराष्ट्र (81) और अरुणाचल प्रदेश (70) थे।

शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों से कुल 612 भागीदार आए। इनकी संख्या राज्यों/के. शा. प्र. की कुल संख्या की 40 प्रतिशत थी।

1.1.2 डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(अ) राष्ट्रीय डिप्लोमा

परियोजना रिपोर्ट कार्य से संबंधित नौवा डिप्लोमा का तीसरा चरण जुलाई, 1989 में पूरा हुआ। 15 सफल भागीदारों को प्रंमाण पत्र दिए गए। दसवां डिप्लोमा कार्यक्रम नवंबर, 1989 में शुरू हुआ। इसमें 15 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 26 अधिकारी शामिल हुए।

(ब) अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा

एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरु किया गया तथा वर्ष

1989-90

1988-89 में आरंभ किया गया डिप्लोमा पाठ्यक्रम संपन्न हुआ। इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 22 देशों के 48 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पहली बार मंगोलिया (एशिया महाद्वीप), सियरा लियोन (अफ्रीका) और सीशेल्स (हिंद महासागर) के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

1.13 प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम

इस वर्ष विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न विषयों पर 27 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें लगभग 100 शिक्षाकर्मी शामिल हुए। सात कार्यक्रम अगरतल्ला, नेहालिगं (अरुणाचल प्रदेश), ग्वालियर, मद्रास, पुणे, शिमला और सूरत में आयोजित किए गए।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से संस्थान ने पहली बार जिला और उप-जिला/प्रखंड स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा की योजना और प्रबंध में सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

पिछले कुछ वर्षों से संस्थान नियमित रुप से कार्यक्रमों की एक शृंखला का आयोजन करता आ रहा है। इस वर्ष के दौरान आयोजित कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

1. वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम,

2. कालेजों के प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों के लिए संस्थान ने तीन सप्ताह के दो प्रवेश स्तरीय कार्यक्रमों की एक नई शृंखला का आयोजन किया।

विद्यालय प्राचार्यों, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों और अन्य शिक्षा-कर्मियों के लिए भी संस्थान ने कार्यक्रम आयोजित किए। भा.प्र.से. के अधिकारियों के लिए भी शैक्षिक योजना पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

1.14 कार्यशिविर/संगोष्ठी/ सम्मेलन

संस्थान ने विभिन्न विषयों पर 30 कार्यशिविर/संगोष्ठी/सम्मेलन आयोजित किए इनके विषय थे – वंचित वर्ग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, विकास के चार दशक, प्रारंभिक स्तर पर सांस्थानिक योजना, सांस्थानिक मूल्यांकन, जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा के अर्थशास्त्र में समस्याएं और अनुसंधान की प्राथमिकताएं, प्रयोगशाला क्षेत्र अभिगम (जि.शि.प्र.सं.), प्रशिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं, संस्थाओं के प्रमुखों का कार्यविश्लेषण और जिला शिक्षा अधिकारियों का कार्य विश्लेषण इत्यादि।

1.15 विशेष कार्यक्रम

नवोदय विद्यालय समिति (2), केंन्द्रीय विद्यालय संगठन (1), जि.शै.प्र.सं. (4), रेलवे बोर्ड (1), वि.अ.आ. (3), क्वीन मैरी कालेज, मद्रास (1) कार्मिक विभाग (1), राज्य सरकार (5), अ.मु.वि (1) दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय (1), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2) और एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस. (1) के अनुरोध/सहयोग से संस्थान ने 23 विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया।

1.16 अंतर-विषयक अभिगम

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम- अंतर-विषयक अभिगम प्रकृति के थे। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याहारिक कार्य, सामूहिक कार्य, केस अध्ययन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, संगणक, फिल्म, वीडियो और फिल्म प्रशिक्षण के आवश्यक तत्व थे आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्रीय दौरे पर भी ले जाया गया।

1.17 मूल्यांकन

मूल्यांकन प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनिवार्य अंग होता है।

1989-90

लंबी अवधि के कार्यक्रम जैसे जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए छः माही डिप्लोमा कार्यक्रम और आई.डी.इ.पी.ए. में मूल्यांकन सतत् प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग होता है।

1.18 प्रशिक्षण सामग्री

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग करने और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए शैक्षिक योजना और प्रबन्ध पर अनेक माड्यूल, आलेख और सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किए गए।

1.2 अनुसंधान

इस वर्ष 5 अनुसंधान अध्ययन पूरे किये गये। 22 अध्ययन कार्य जारी हैं और 3 नये अध्ययन स्वीकृत किये गए हैं। इनमें 3 सहयोगी अध्ययन, 3 प्रायोजित अध्धयन और 6 नीपा सहायता योजना के अध्ययन थे।

सरकारी अनुदान और वित्तीय सहायता से अनुसंधानों पर कुल 26.78 लाख रुपये व्यय हुए। वर्ष 1988-89 में 14.50 लाख रुपये व्यय हुए थे।

नीपा सहायता योजना के अंतर्गत इस वर्ष 1.27 लाख रुपयों का अनुदान जारी किया गया। वर्ष 1988-89 में यह राशि 0.6 लाख रूपये थी।

पूरा किया गया अध्ययन (5)

1. महिला और विकास पर एट्लस
2. आन्ध्र प्रदेश में शिक्षा और विकास पर मोनोग्राफ
3. भारत में उच्च शिक्षा के चयनित क्षेत्रों में संसाधन निर्धारण की प्रणाली (आई.आई.ई.पी-वि.अ.आ.-नीपा) (सहयोगी अध्ययन)
4. महिला कार्यकारी अधिकारियों की पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा के बारे में एक जांच अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अन्तर्गत)
5. जिला शिक्षा अधिकारियों का कार्यविश्लेषण : एक राष्ट्रीय अध्ययन

चालू अध्ययन (22)

1. सन् 2000 ई० में शिक्षा -एक दीर्घावधि संप्रेक्ष्य' (दूसरा चरण)
2. भारत में साक्षरता – एक देश कालिक विश्लेषण (1901 से 1981)
3. हरियाणा के गुड़गावां जिले के पुनहाना प्रखंड में शैक्षिक योजना और प्रशिक्षण के क्षेत्र में रणनीतियों के क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान (प्रौढ़ और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण) (ए.आर.आई.एस.इ.) (तीसरा चरण)
4. कालेजों की प्रकार्यात्मक क्षमता और विकास : एक क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन (दूसरा चरण)
5. जनजाति और उप-योजना क्षेत्र के शैक्षिक विकास का एक अध्ययन
6. विद्यालय मानचित्रण पर एक परियोजना
7. द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण
8. लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध का एक अध्ययन – उसके निहितार्थ और भारत के लिए पाठ
9. कालेजों के विकास में कालेज विकास परिषदों की भूमिका का एक अध्ययन : चयनित कालेज विकास परिषदों का एक सघन अध्ययन
10. भारत में गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के बीच साक्षरता स्तर में असमानता का जिलेवार विश्लेषण
11. शैक्षिक संस्थानों में प्रबंध की स्वायत्तता : स्वायत कालेजों का एक अध्ययन
12. महाराष्ट्र की शिक्षा और प्रबंध पर मोनोग्राफ
13. बेसिक शिक्षा सेवा की गुणवत्ता (नीपा-आई. आई. ई. पी.) (सहयोगी अध्ययन)
14. हिला कालेजों के प्रशासकों के प्रशिक्षण संबंधी जरुरतों की शिनाख्त (नीपा-एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय) (सहयोगी अध्ययन)
15. संगणकीकृत योजना और प्रारम्भिक शिक्षा (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
16. जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए सं.सू.प्र. (एम.आई.एस.) (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
17. उच्च शिक्षा में वर्तमान सुविधाओं/संसाधनों के प्रभावी प्रयोग का अध्ययन (योजना आयोग द्वारा प्रायोजित)

18. भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रबंध (नीपा सहयाता योजना)
19. कक्षा स्तर के सापेक्ष दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों की लागत का एक अध्ययन (नीपा सहायता योजना)
20. भारत के वर्तमान पत्राचार अध्ययन संस्थानों में शिक्षण और अधिगम के प्रबंध के लिए अपनाई गई प्रणालियों का एक अलोचनात्मक मूल्यांकन (नीपा सहायता योजना)
21. तमिलनाडु में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबंध (नीपा सहायता योजना)
22. औपचारिक विश्वविद्यालयी ढांचे में दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के सांगठनिक और विभागीय ढांचे का एक अध्ययन (नीपा सहायता योजना)

स्वीकृत अध्ययन (3)

1. भारत में कृषि स्नातकों के रोजगार के अवसर : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर का एक लाभकारी लागत अध्ययन (नीपा सहायता योजना)

2. भारत के शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय असमानताएं – सामाजिक संदर्भ में आधारभूत स्तर पर शैक्षिक असमानताएं संबंधी जांच

3. शिक्षा में संसाधनों के प्रभावी उपयोग –एक केस अध्ययन

1.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चुने हुए पक्षों पर संस्थान ने 30 कार्यक्रम आयोजित किए।

शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के कार्यक्रम निम्न विषयों से संबंधित थे – व्यष्टि स्तरीय योजना और विद्यालय मानचित्रण, सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जि.शि.प्र.सं. की योजना और प्रबंध, नवोदय विद्यालय, सुविधा वंचित वर्ग, प्रयोगशाला क्षेत्र अभिगम, अकादमिक स्टाफ कालेज और स्वायत्त कालेज इत्यादि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के संदर्भ में अनेक अनुसंधान अध्ययन शुरू किए गए।

केब (सी.ए.बी.ई.) समिति के समक्ष रखे गए मुद्दे (1) अध्यापकों का स्थानांतरण, (2) अध्यापिकाओं के लिए आवासीय सुविधाएं और (3) शिक्षा का प्रबंध, के लिए संस्थान ने अपनी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की।

1.4 परामर्शकारी और अन्य सेवाएं

आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण में संस्थान ने कार्यदल को निम्न बिंदुओं पर वृत्तिक सेवाएं प्रदान किए – (1) सांख्यिकीय, संचारेक्षण और मूल्यांक्न; (2) पूर्व प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा पर कार्यदल की स्थानीय योजना और प्रबंध के लिए गठित उप-दल और (3) शिशु और प्रारंभिक शिक्षा के लिए गठित उप-दल।

अनेक अकादमिक और वृत्तिक निकायों के प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों में संस्थान के संकायों ने अकादमिक और औपचारिक समितियों के सदस्यों तथा अपने-अपने विशेष क्षेत्रों में प्रकाशित अनुसंधान -आंकड़े और पुस्तकों के माध्यम से अकादमिक योगदान दिए।

संस्थान का एक अकादमिक सदस्य ने यूनेस्कों के तत्वाधान में श्रीलंका को परामर्शकारी सेवा प्रदान की।

1.5 नीपा विचार मंच

संस्थान में इस वर्ष विभिन्न विषयों पर विचार मंच आयोजित किए गए। ये विषय थे – राष्ट्रीय संप्रेक्ष्य योजना, उच्च शिक्षा के प्रबंध की प्रवृत्तियां और सन् 2000 ई० में सभी के लिए शिक्षा।

1.6 शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों का राष्ट्रीय रजिस्टर

शैक्षिक योजना और प्रबंध, शिक्षा नीति और योजना, शैक्षिक वित्त, विद्यालय शिक्षा का प्रबंध, उच्च शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा,

1989-90

अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, ग्राम विकास, महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और शिक्षा का अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों का अभ्यास के तौर पर एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जा रहा है।

1.7 प्रकाशन

1.7.1 प्रकाशित

1. विद्यालय मानचित्रण : मार्गदर्शिका (हिंदी रूपांतरण)
2. शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा के अंतर-क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट
3. अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध –परियोजना अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शिका
4. सन् 2000 ई. तक सभी के लिए शिक्षा –भारतीय परिप्रेक्ष्य

1.7.2 प्रेस में

1. विद्यालय और ग्राम परिवर्तन – मूनिस रज़ा और एच. रामचंद्रन (समूल्य)
2. शिक्षा मंत्रालय का संगठनात्मक इतिहास –ए. मैथ्यू (समूल्य)
3. भारत में विद्यालय शिक्षा : क्षेत्रीय आयाम – मूनिस रज़ा, ए. अहमद और एस.सी.नूना
4. महिला और विकास पर एटलस –एस.सी. नूना

1.7.3 जर्नल

शैक्षिक योजना और प्रशासन जर्नल के दो अंक –(i) दूरवर्ती शिक्षा विशेषांक और (ii) शैक्षिक योजना विशेषांक (हिंदी रुपांतरण) प्रकाशित हुए।

प्रेस में

(1) दूरवर्ती शिक्षा विशेषांक (हिंदी रूपांतरण) और (2) तीसरी दुनियां में शैक्षिक योजना और प्रबंध विशेषांक

1.7.4 मिमियोग्राफ प्रकाशन

संस्थान ने अनुसंधान अध्ययनों, सामाजिक आलेखों और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्टों के रूप में मिमियोग्राफ प्रकाशित किए।

1.7.5 अनियत पत्र

इस वर्ष निम्न अनियत आलेख निकाले गए :

1. दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, आंध्रप्रदेश का एक केस अध्ययन –के सुजाता
2. आश्रम विद्यालयों में शिक्षा-आंध्रप्रदेश का एक केस अध्ययन –के सुजाता

1.8 पुस्तकालय

संस्थान के पुस्तकालय में पूरे वर्ष निर्बाध रूप से शोधार्थियों, छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों को पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं प्रदान की गईं। अवकाश के दिन भी पुस्तकालय सेवाएं दी गयीं। वर्तमान में पुस्तकालय में लगभग 44 हजार पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों के संकलन भी हैं। पुस्तकालय में नियमित रूप से325 पत्र-पत्रिकाएं आती हैं।

राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र में राज्य और जिला स्तर की शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित 9500 प्रलेखों का संग्रह है।

1.9 काडर योजना

संस्थान की काडर योजना नीति का लक्ष्य वृत्तिक अकादमिक क्षमताओं को मजबूत बनाना और प्रशासनिक काडरों को पूर्णतया न्यूनतम पर लाना है। संस्थान में 31 मार्च 1991 तक सभी काडरों की कुल संख्या 176 थी और परियोजना स्टाफ की संख्या 51 थी।

1989-90

1.10 विशेष लेखा समीक्षा

सी.ए.जी. ने संस्थान में वर्ष 1981-89 के दौरान किए गए अनुसंधानों और वर्ष 1984-89 की अकादमिक गतिविधियों का पुनरीक्षण किया।

1.11 विशेषज्ञ समीक्षा समिति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समीक्षा समिति ने सितंबर 1989 में शिक्षा सचिव को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नीपा की भावी भूमिका, इसके प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन तथा प्रशिक्षण अनुसंधान और प्रकाशनों की गुणवत्ता के बारे में समिति ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

1.12 सेवा विनियम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा गठित विनियम समिति ने जून 1989 में सेवा विनियम के प्रारुप के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सेवा विनियम दिनांक 5.1.90 से लागू हो गया है। संस्थान के क्रियाकलाप में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इसमें अनेक प्रावधान रखे गए हैं।

1.13 सेवारत प्रशिक्षण

विदेश में स्टाक होम विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, आई.आई.इ.पी. पेरिस तथा देश के अनेक संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संस्थान के अकादमिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों ने भाग लिया।

1.14 परिसर विकास

दिल्ली अग्निशमक सेवा की सलाह पर नीपा के अतिथिगृह और परिषद् में अग्निशमक सुविधाओं में नवीनीकरण किया गया।

टाइप IV के आठ क्वार्टर निर्माणाधीन हैं।

1.15 वित्त

इस वर्ष सरकारी अनुदान सें कुल रु० 144 लाख (योजना और योजनेतर) व्यय हुआ। वर्ष 1988-89 के दौरान यह राशि 132.36 रुपए थी। वित्तीय सहायता निधि के अंतर्गत किए गए कार्यक्रमों और अध्ययनों में 18.95 लाख रुपए व्यय हुए। इस वर्ष सरकारी अनुदान और वित्तीय सहायता निधि से कुल 162.09 लाख रुपए व्यय हुए।

सातवीं योजना (1985-1990): प्रमुख उपलब्धियां

1.16 प्रशिक्षण गतिविधियां

सातवीं योजना के दौरान आयोजित 306 कार्यक्रमों में 8000 शिक्षाकर्मी भाग लिए जिनमें 48 देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों, जैसे – यूनेस्को, यूनीसेफ और विश्व बैंक के 308 भागीदार भी शामिल थे।

शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों से कुल लगभग 3000 भागीदार थे। इनकी संख्या कुल भागीदारों की संख्या की लगभग 42% थी।

सात राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में 25 राज्यों /के.शा.प्र. से 144 अधिकारी शामिल हुए।

पांच अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में 33 देशों से कुल 102 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए।

सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों तथा अनेक केस अध्ययनों, अनुसंधान अध्ययनों, सांख्यकीय आंकड़े से संबंधित 32 माड्यूल तथा शिक्षा पर अन्य प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गईं।

सातवीं योजना के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी संबंधी कुछ विशेष विवरण अनुबंध –I में दिए गए हैं।

1989-90

1.17 अनुसंधान गतिविधियां

संस्थान ने अपने कार्यों में सबसे अधिक बल अनुसंधान के क्षेत्र में दिया। जून 1987 में संस्थान में अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता के लिए सहायता योजना आरंभ की गयी। सरकारी अनुदानों और वितीय सहायता निधि से अनुसंधान पर क्रमशः रु० 29.08 लाख और रु० 30.43 व्यय हुए। सरकारी अनुदानों और वित्तीय सहायता निधि दोनों से अनुसंधान पर कुल 59.51 लाख रुपए व्यय हुए। इनका विस्तृत विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। सातवीं योजना के अंतर्गत 55 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए। 31 मार्च 1990 तक 3 नए अध्ययन स्वीकृत किए गए और 22 अध्ययन जारी हैं। इनमें 9 प्रायोजित अध्ययन, 4 सहयोगी अध्ययन और नीपा सहयाता योजना के 9 अध्ययन हैं।

1.18 परामर्शकारी, सलाहकारी और समर्थनकारी सेवाएं

(अ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कार्यवाही योजना और कार्यान्वयन नीति के निर्माण के दौरान संस्थान को इन कार्यों से संबद्ध राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात विशेषज्ञों और अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श करने का एक अनोखा अवसर मिला।

एक दस्तावेज 'स्थिति रिपोर्ट और नीति संबंधी मुद्दे' तैयार किया गया। मंत्रालय के दस्तावेज –'शिक्षा की चुनौती' के निर्माण में संस्थान द्वारा किए गए अभ्यास कार्यों को आंशिक उपयोग किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दी गई अनुशंसाओं को कार्यरूप देने के लिए संस्थान ने 4 क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किए। लगभग 7 हजार प्रश्नों /दस्तावेजों/प्रेस कतरनों/अन्य रिपोर्टों के वस्तुगत विश्लेषण और नागरिकों के सुझावों से संबंधित 16 दस्तावेज़, भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामाजिक अंकेक्षण, भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन, शिक्षा के स्वैच्छिक और व्यावसायिक निकाय, नई शिक्षा नीति पर प्रेस की टिप्पणियां और राज्यों के दृष्टिकोण संबंधी आधारभूत सामग्री तैयार की गईं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में इनका आधार सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन रणनीतियां' विषय पर जून 1986 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। योजना आयोग और विश्व बैंक की मदद से अगस्त 1986 में एक दूसरी संगोष्ठी आयोजित की गयी थी।

राज्य शिक्षा सलाहकार परिषदों, जिला शिक्षा परिषदों, ग्राम शिक्षा समितियों, राज्य शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थानों जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों और नवोदय विद्यालयों के लिए संस्थान ने मार्गदर्शिकाएं तैयार किए। संस्थान द्वारा व्यष्टि स्तरीय योजना, विद्यालय मानचित्रण और ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय परिसर पर भी मार्गदर्शिकाएं तैयार की गईं।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य, जिला और प्रखंड स्तर के शिक्षाकर्मियों के लिए एक सामूहिक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राज्य और के.शा.प्र. के निवेदन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यवाही योजना की तैयारी में संस्थान ने राज्यों को वृत्तिक सेवाएं प्रदान किए। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) योजना आयोग, केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद, वि.अ.आ. और विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए कार्यों में संस्थान ने अपनी वृत्तिक सेवाएंन प्रदान किए।

संस्थान ने शिक्षकों के स्थानांतरण, महिला शिक्षिकाओं के आवासीय सुविधाओं और शिक्षा के प्रबंध से संबंधित मसलों के लिए गठित केब समितियों को भी संस्थान ने अपनी सेवाएं प्रदान किए।

1989-90

(ब) अन्य परामर्शकारी, सलाहकारी और समर्थन सेवाएं

अरुणाचल प्रदेश, असम, दादरा और नागर हवेली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, तथा लक्षद्वीप को अपने शिक्षा विभागों के पुनर्गठन में संस्थान ने अपनी वृत्तिक सेवाएं प्रदान किए।
संस्थान ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्य दल और वार्षिक योजना के विचार-विमर्श में अपनी सेवाएं अर्पित की।

अरुणाचल प्रदेश की 20 वर्षीय संप्रेक्ष्य योजना के निर्माण में संकाय ने एजु.सी.इ.एल. को अपनी परामर्शकारी सेवाएं दिए। सुमालिया, मालदीव, यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक को संकाय ने परामर्शकारी सेवाएं दिए और शैक्षिक योजनाकारों के लिए एक पुस्तिका का विकास किया।

1.19 अन्य अकादमिक गतिविधियां

(अ) नवाचारों का प्रचार-प्रसार

चयनित कालेजों के प्राचार्यों द्वारा स्वायत्त कालेजों के दो अध्ययन दौरे आयोजित किए गए। पहला दौरा फरवरी 1986 में और दूसरा फरवरी 1988 सें गांधी ग्राम विश्वविद्यालय का था।

(ब) शैक्षिक मुद्दों पर सुनियोजित परिचर्चाएं

(स) शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का निर्माण

1.20 प्रशिक्षण, अनुसंधान, सलाहकारी और अन्य गतिविधियों का सम्मिश्रण

संस्थान के प्रशिक्षण, अनुसंधान और अन्य गतिविधियों की उपलब्धियों में संतुलन बना रहा। सातवीं योजना के पहले वर्ष सरकारी अनुदान से प्रशिक्षण और अनुसंधान पर कुल व्यय का अनुपात क्रमश: 78% और 22% था। इसके अंतिम वर्ष में यह अनुपात 53% और 47%रहा।

1.21 प्रकाशन

इस दौरान 6 समूल्य और 11 मूल्यरहित प्रकाशन निकाले गए। 5 प्रकाशन प्रेस में थे और 5 सामग्रियां प्रकाशन के लिए स्वीकृत की गईं। इसके अलावा संस्थान के कार्यक्रमों के लिए मिमियोग्राफ के रूप में अनेक रिपोर्टें निकाली गयी। संस्थान ने त्रैमासिक इ.पी.ए. बुलेटिन के स्थान पर नए रूप में शैक्षिक योजना और प्रशासन त्रैमासिक जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ किया।

विभिन्न विषयों पर 10 अनियत पत्र निकाले गए।

1.22 कार्मिक

संस्थान में 1 अप्रैल 1985 तक काडर संख्या 161 थी जो 31 मार्च 1990 तक 176 हो गयी। इसके अलावा 31 मार्च 1990 तक 50 परियोजना स्टाफ भी थे।

मार्च 1986 सें संस्थान में सामूहिक बचत बीमा योजना शुरु की गयी जिससे अनेक परिवार लाभान्वित हुए। नीपा का सेवा विनियम 5 जनवरी 1990 से लागू किया गया।

1.23 परिसर

टाइप II और III, के आठ-आठ क्वाटर बन कर तैयार हुए और टाइप IV के आठ क्वार्टर निर्माणाधीन थे। संकाय अतिथि गृह, वार्डेन आवास और अतिथि गृह के अतिरिक्त खण्डों के निर्माण के लिए निर्णय लिया गया।

1.24 अनुदान व्यय

सातवीं योजना में योजना और योजनेतर कार्यक्रमों के अतंर्गत सरकारी अनुदान से रु० 586.02 लाख की राशि व्यय हुई। यह राशि छठीं योजना की राशि रु०299.35 लाख से काफी अधिक है।

सातवीं योजना के दौरान प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों पर कुल व्यय राशि रु० 92.65 लाख थी। यह छठीं योजना की राशि रु 42.19 लाख के दुगने से भी अधिक थी ।

1989-90

125 समीक्षा

संस्थान की वर्ष 1980-81 से आगामी सात वर्ष की गतिविधियों की आंतरिक समीक्षा की गयी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा गठित विशेषज्ञ समीक्षा समिति द्वारा संस्थान के कार्यों की समीक्षा की गयी तथा नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा भी संस्थान का विशेष लेखा अंकेक्षण किया गया।

1989-90

अध्याय 2

प्रशिक्षण

वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के प्रशिक्षण की जरूरत के अनुरूप शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाओं को मददेनज़र रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्थापित नए संस्थानों जैसे–जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों तथा विश्वविद्यालयों के संगणक केन्द्रों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण, आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, संयुक्त और राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग देने पर विशेष बल दिया गया ताकि नवोदित संस्थाएं वतंत्र रूप से अपने कार्यक्रम आयोजित करने में समर्थ हो सकें और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य संभव हो सके।

तालिका 2.1

कार्यक्रमों का वर्गीकरण

कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि दिन	भागीदारों की संख्या	कार्यक्रम व्यक्ति दिन
1	2	3	4	5
डिप्लोमा कार्यक्रम				
(क) राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम	1*	185	45**	4572
(ख) अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम	1*	175	48**	4459
उप-योग	2*	360 50%	93**	9031 46%
अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम				
(अ) स्तर विशेष				
(क) विद्यालय शिक्षा	8	97	200	2819
(ख) उच्च शिक्षा	6	50	397	2132
(ग) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा	4	48	115	1678

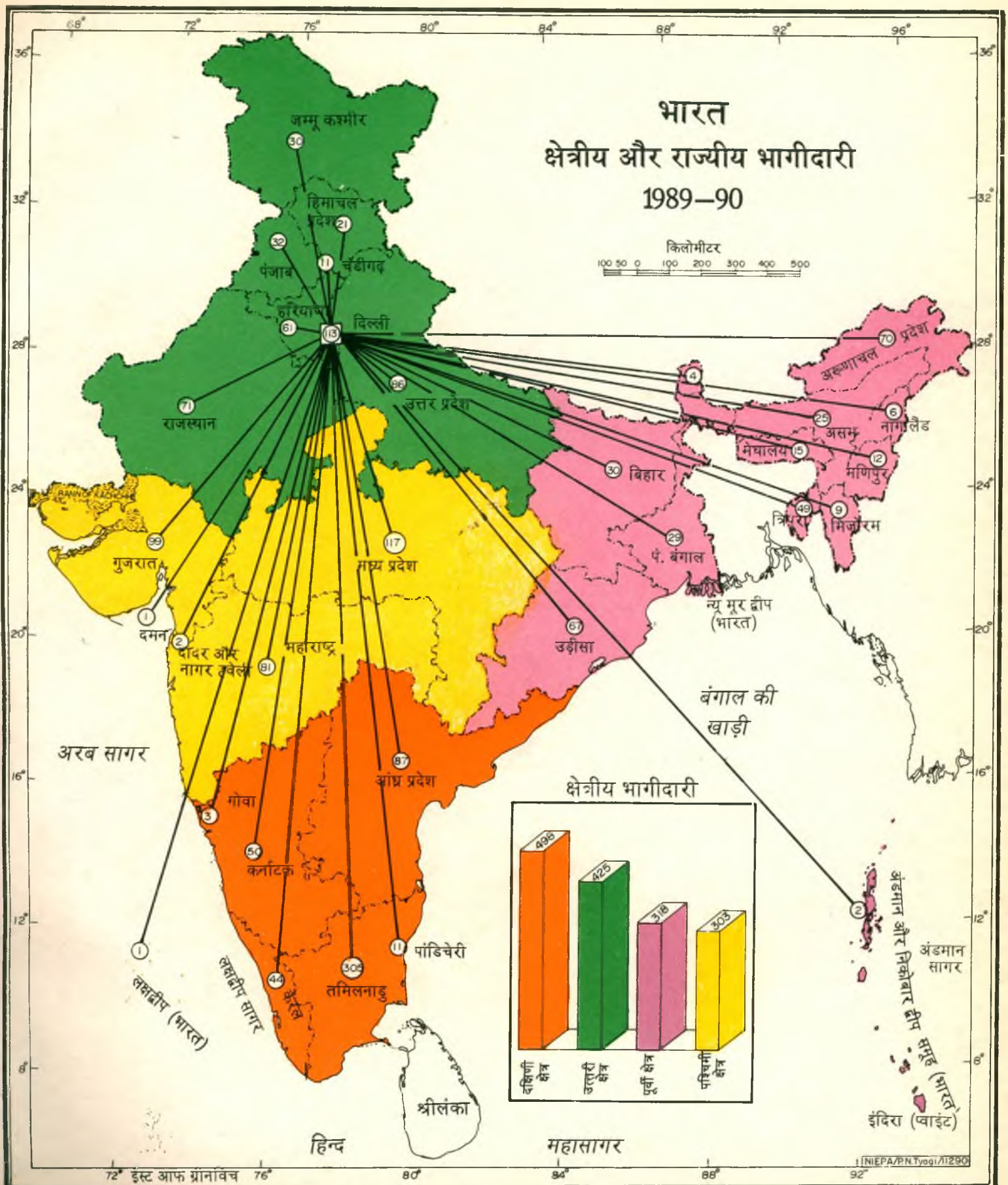

भारत
क्षेत्रीय और राज्यीय भागीदारी
1989–90
किलोमीटर
100 50 0 100 200 300 400 500
जम्मू कश्मीर 30
हिमाचल प्रदेश 21
पंजाब 32
चंडीगढ़ 11
हरियाणा 61
दिल्ली 113
राजस्थान 71
उत्तर प्रदेश 86
गुजरात 99
दमन 1
दादर और नागर हवेली 2
मध्य प्रदेश 117
महाराष्ट्र 81
गोवा 3
कर्नाटक 50
केरल 44
तमिलनाडु 305
आंध्र प्रदेश 87
पांडिचेरी 11
लक्षद्वीप (भारत) 1
बिहार 30
पं. बंगाल 29
उड़ीसा 67
अरुणाचल प्रदेश 70
सिक्किम 4
असम 25
नागालैंड 6
मेघालय 15
मणिपुर 12
त्रिपुरा 49
मिज़ोरम 9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भारत) 2
न्यू मूर द्वीप (भारत)
अरब सागर
लक्षद्वीप सागर
बंगाल की खाड़ी
अंडमान सागर
हिन्द महासागर
श्रीलंका
इंदिरा (प्वाइंट)
क्षेत्रीय भागीदारी
498 दक्षिणी क्षेत्र
425 उत्तरी क्षेत्र
318 पूर्वी क्षेत्र
303 पश्चिमी क्षेत्र
72° ईस्ट आफ ग्रीनविच 76° 80° 84° 88° 92°
NIEPA/P.N.Tyagi/11290

1989-90

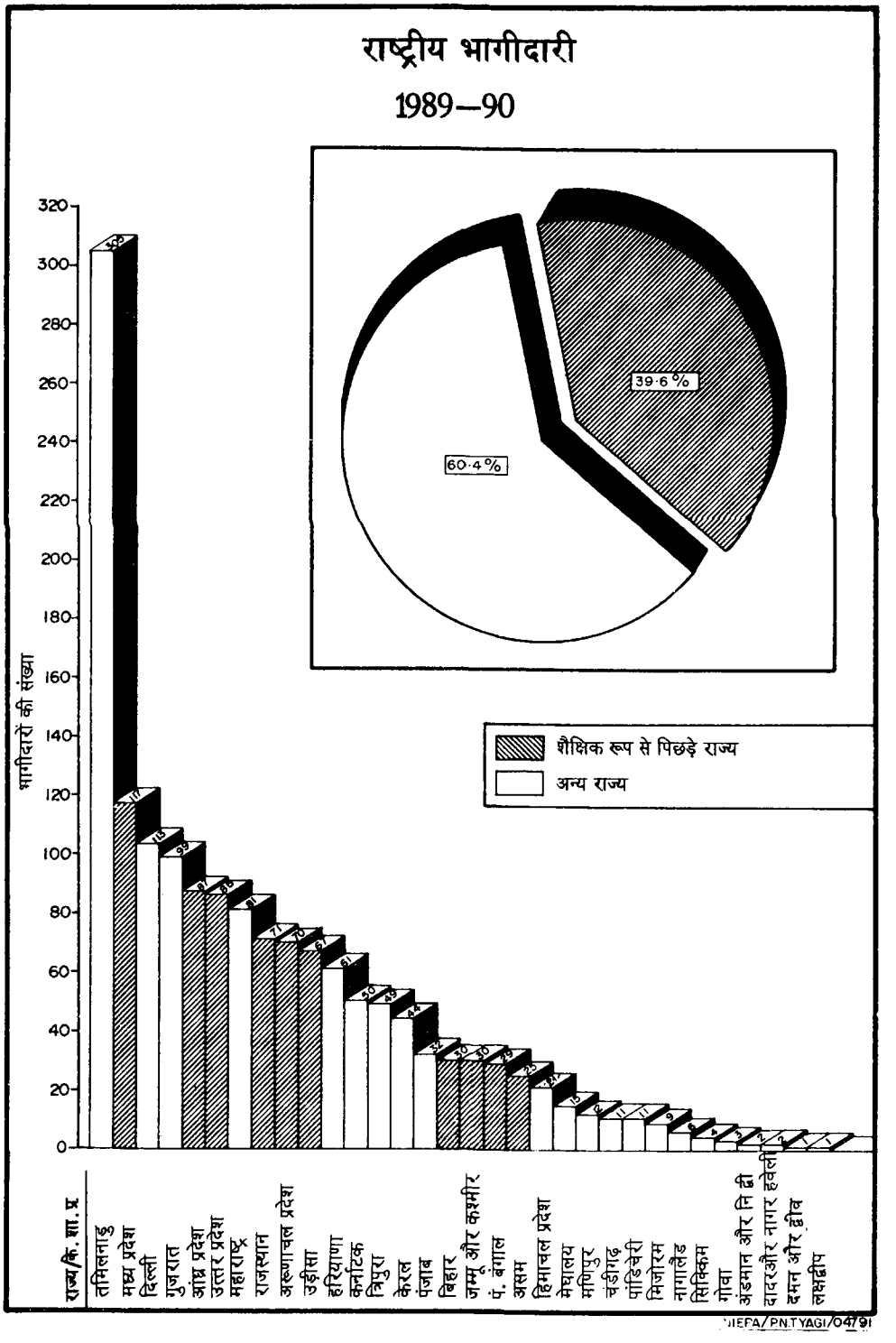
राष्ट्रीय भागीदारी
1989–90
39·6 %
60·4 %
शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य
अन्य राज्य
भागीदारों की संख्या
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
राज्य/कें. शा. प्र.
तमिलनाडु
मध्य प्रदेश
दिल्ली
गुजरात
आंध्र प्रदेश
उत्तर प्रदेश
महाराष्ट्र
राजस्थान
अरुणाचल प्रदेश
उड़ीसा
हरियाणा
कर्नाटक
त्रिपुरा
केरल
पंजाब
बिहार
जम्मू और कश्मीर
पं. बंगाल
असम
हिमाचल प्रदेश
मेघालय
मणिपुर
चंडीगढ़
पांडिचेरी
मिजोरम
नागालैंड
सिक्किम
गोवा
अंडमान और नि द्वी
दादरऔर नागर हवेली
दमन और द्वीव
लक्षद्वीप
NIEPA/PN.TYAGI/0479

1989-90

(ब) विषय/क्षेत्र/विशेष					
(क) शैक्षिक योजना और प्रबंध-में संगणक उपयोग तथा अनुप्रयोग	3	20		56	385
(ख) शैक्षिक योजना के लिए परिमाणात्मक तकनीक	1	12		37	444
(ग) विस्तृत शैक्षिक योजना	1	6		29	174
(घ) व्यष्टि स्तरीय योजना	2	6		75	220
(च) वंचित वर्ग	1	5		20	100
(छ) नीति क्रियान्वयन	1	5		39	195
उप-योग	27	249	35%	968	8147 41%
(स) कार्यशिविर/संगोष्ठी/सम्मेलन					
(क) शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणक उपयोग तथा अनुप्रयोग	3	12		62	276
(ख) वंछित वर्ग	4	15		61	210
(ग) विद्यालय माचित्रण	3	15		59	383
(घ) शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण	2	7		24	92
(च) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	3	7		88	220
(छ) शैक्षिक प्रौद्योगिकी और दूवर्ती शिक्षा	2	5		44	113
(ज) अन्य	14	45		425	1254
उप-योग	31	106	15%	763	2548 13%
कुल योग	60*	715		1824**	19726

*इसमें पहले से चालू दो डिप्लोमा कार्यक्रम–एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय शामिल नहीं हैं।

**इसमें चालू डिप्लोमा के भागीदारों को शामिल किया गया है।

2.2 भागीदारी

अ. राष्ट्रीय

तालिका 2.2, 2.3, और 2.4 में राज्यवार, स्तरवार और क्षेत्रवार भागीदारी संबंधी विवरण हैं। यह देखा जा सकता है कि संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में देश के सभी राज्यों और के.शा. प्रदेशों के भागीदार शामिल हुए। सबसे अधिक भागीदारी तमिलनाडु (305) की थी। इसके बाद मध्यप्रदेश (117), दिल्ली (113), गुजरात (99), आंध्रप्रदेश (87), उत्तर प्रदेश (86), महाराष्ट्र (81) और राजस्थान (71) और अरुणाचल प्रदेश (70) थे।

1989-90

शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों–आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल से कुल 609 प्रतिनिधि शामिल हुए। यह सभी राज्यों/के.शा.प्र. की कुल भागीदारी का लगभग 39.45% है।

क्षेत्रवार भागीदारी में पहला स्थान दक्षिणी क्षेत्र का (498) था। इसके बाद उत्तरी क्षेत्र (425), पूर्वी क्षेत्र (318) और पश्चिमी क्षेत्र (303) थे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अलावा भारत सरकार और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों , जैसे एन.सी.ई.आर.टी., योजना आयोग, वि.अ.आ., विश्वविद्यालयों और प्रौढ़शिक्षा निदेशालयों इत्यादि सें 231 अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए।

तालिका 2.2

राष्ट्रीय भागीदारी

क्रम सं.	राज्य/कें.शा.प्र./अन्य संगठन	भागीदार
1.	आंध्र प्रदेश*	87
2.	अरुणाचल प्रदेश*	70
3.	असम*	25
4.	बिहार*	30
5.	गुजरात	99
6.	गोवा	3
7.	हरियाणा	61
8.	हिमाचल प्रदेश	21
9.	जम्मू और कश्मीर*	30
10.	कर्नाटक	50
11.	केरल	44
12.	मध्य प्रदेश*	117
13.	महाराष्ट्र	81
14.	मणिपुर	12
15.	मेघालय	15
16.	मिज़ोरम	9
17.	नागालैंड	6
18.	उड़ीसा*	67
19.	पंजाब	32
20.	राजस्थान*	71
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	305

1989-90

क्रम सं.	राज्य/कें.शा.प्र./अन्य संगठन	भागीदार
23.	त्रिपुरा	49
24.	उत्तर प्रदेश*	86
25.	प० बंगाल*	29
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2
27.	चंडीगढ़	11
28.	दादरा और नागर हवेली	2
29.	दमन और दिव	1
30.	दिल्ली	113
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	11
	योग	1544
	भारत सरकार और अन्य संगठन	231
	कुल योग	1775

*शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य

तालिका 23

क्षेत्रवार भागीदारी

उत्तरी क्षेत्र	425
पश्चिमी क्षेत्र	303
पूर्वी क्षेत्र	318
दक्षिणी क्षेत्र	498
योग	1544

1989-90

तालिका 2.4

स्तरवार भागीदारी

स्तर	भागीदार
विद्यालय प्राचार्य	68
जिला शिक्षा अधिकारी	68
अन्य विद्यालय कार्मिक	523
प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	76
कालेज प्राचार्य	190
अन्य विश्वविद्यालों कार्मिक	463
विदेशी	49
अन्य	387
योग	1824

ब. अंतर्राष्ट्रीय

संस्थान के कार्यक्रमों में 23 देशों से 49 भागीदार शामिल हुए। इनमें पांचवें और छठें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा के 48 भागीदार सन्मिलित हैं। एक भागीदार सोमालिया का था, जो जून 1989 में संगणक अुनप्रयोग पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था।

2.3 डिप्लोमा पाठ्यक्रम

इस वर्ष दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

2.3.1 जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय डिप्लोमा

जि.शि.अ. के लिए जुलाई 1983 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरु किया गया। नौवां डिप्लोमा पाठ्यक्रम नवंबर 1989 में आरंभ हुआ और अप्रैल 1989 में सम्पन्न हुआ। दसवां डिप्लोमा पाठ्यक्रम नवंबर 1989 में शुरू हुआ। तीन महीने के सघन पाठ्यचर्या का पहला चरण जनवरी 1990 में पूरा हुआ। दूसरा चरण प्रगति पर है। देश के सभी क्षेत्रों के 20 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जिला स्तर के 45 अधिकारी डिप्लोमा पाठ्क्रम में शामिल हुए। इनमें 13 भागीदार शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों– आंध्रप्रदेश (4), असम (3), मध्यप्रदेश (2), राजस्थान (2), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बंगाल (1) के थे। नौवें डिप्लोमा में 11 राज्यों के 19 भागीदार शामिल थे। जबकि दसवें डिप्लोमा में 16 राज्यों से 26 भागीदार शामिल हुए। डिप्लोमा पाठ्क्रमों में राज्यवार भागीदारी संबंधी विवरण तालिका 2.5 में दिया गया है:

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 1989–90

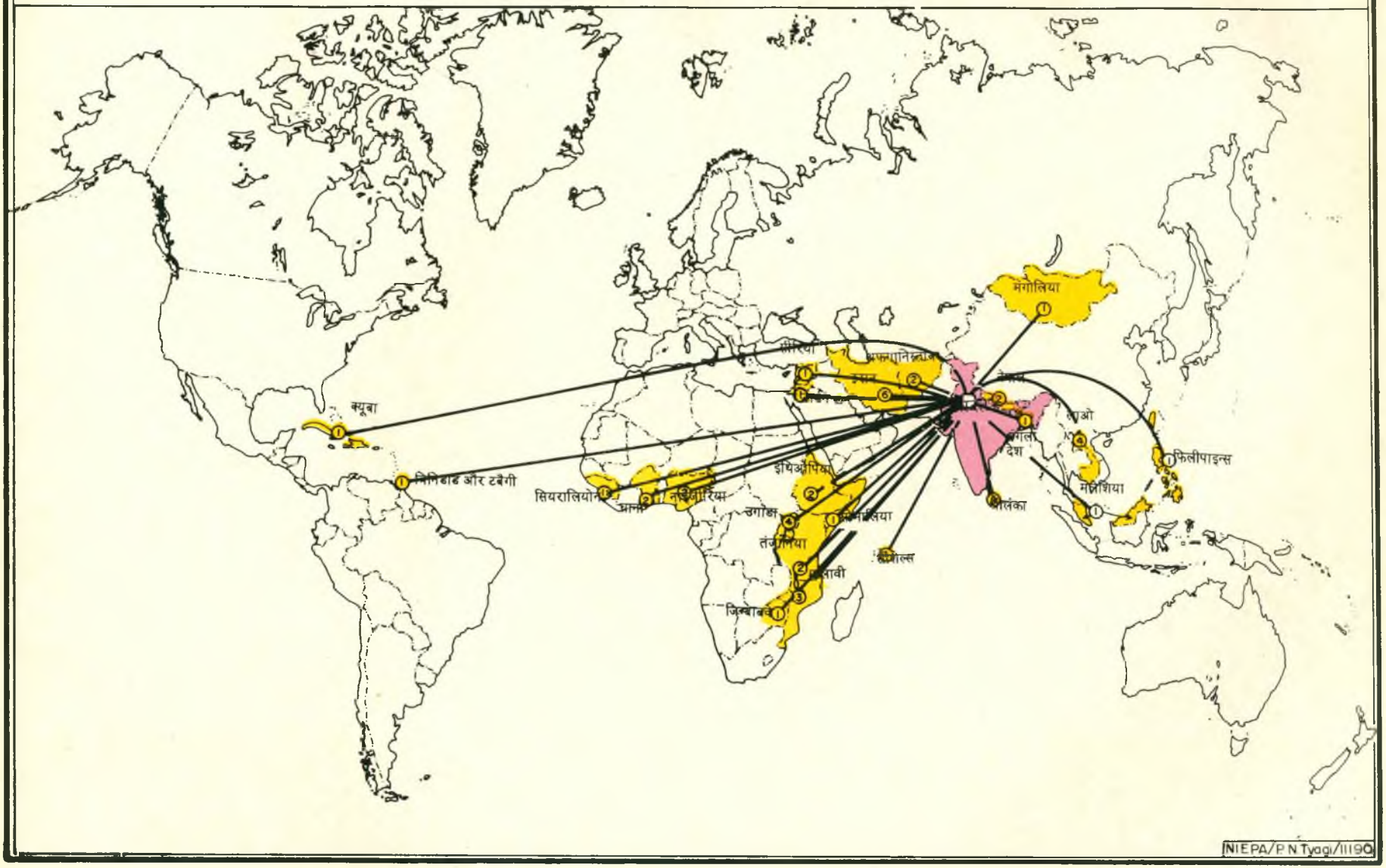

1989-90

तालिका 25

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्यवार भागीदारी

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	नौवां डिप्लोमा	दसवां डिप्लोमा	योग
आंध्रप्रदेश	-	4	4
असम	-	3	3
दिल्ली	-	3	3
गुजरात	2	-	2
हिमाचल प्रदेश	-	1	1
कर्नाटक	1	2	3
केरल	3	2	5
मध्य प्रदेश	1	1	2
महाराष्ट्र	2	1	3
मणिपुर	-	2	2
मेघालय	-	1	1
नागालैंड	1	1	2
पंजाब	1	1	2
पांडिचेरी	4	-	4
राजस्थान	1	1	2
सिक्किम	1	-	1
तमिलनाडु	-	1	1
त्रिपुरा	2	-	2
उत्तरप्रदेश	-	1	1
पश्चिम बंगाल	–	1	1
योग	19	26	45

डिप्लोमा तीन चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला चरण तीन महीने का होता है। इसमें पाठ्चर्या का सघन अध्ययन कराया जाता है. इसका श्रेयांक 15 है। दूसरे चरण में प्रशिक्षणार्थी अपने जिले में तीन महीने तक सर्वेक्षण परियोजना कार्य करता है। इसी आधार पर संस्थान में मूल्यांकन के लिए वह एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करता है। तीसरा चरण 4-6 दिन का होता है जिसमें परियोजना रिपोर्ट पर मौखिक-प्रश्न पूछे जाते है।

पहले के प्रशिक्षित प्रतिभागियों के पुनर्निवेशन और बदलते परिवेश के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषय-वस्तु की पुनर्रचना की गई। प्रबंधकीय कौशल, परियोजना की तैयारी,

1989-90

और शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की कार्यवाही योजना के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल क्षमता को उच्च स्तर तक उठाने पर विशेष बल दिया गया। डिप्लोमा कार्यक्रमों में सांस्थानिक योजना, विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय परिसर, परिमाणात्मक तकनीक, गुणवत्ता सुधार, सांस्थानिक मूल्यांकन, नेतृत्वकारी गुणवत्ता, समस्याओं का समाधान, सामुदायिक भागीदारी इत्यादि विषयों को सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यान-परिचर्चा, सामूहिक परिचर्चा, केस अध्ययन, सामूहिक विधि, सतत् अभ्यास, नेतृत्व भूमिका, टोकरी विधि (इन बास्केट विधि) और सामूहिक परिचर्चा इत्यादि विधियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषयवस्तु के अध्यापन के लिए उपयोग में लाया गया। व्यावहारिक अभ्यासों, पुस्तकालय पर आधारित कार्यों और कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानों के दौरे के लिए पर्याप्त समय दिया गया।

सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र, तिलोनिया तथा क्षेत्रीय महाविद्यालय अजमेर के चार दिन के दौरे का आयोजन किया गया ताकि प्रशिक्षणार्थियों को इन केंद्रों में चल रहे क्षेत्र आधारित क्रियात्मक अनुसंधानों से साक्षात् दर्शन कराया जा सके और उन्हें इनका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके।

डिप्लोमा के भागीदारों के रोजमर्रा के कार्यों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की उपयोगिता का एक मूल्यांकन अध्ययन कार्य संस्थान ने मई 1989 में आरंभ किया। यह अध्यन डिप्लोमा पाठ्क्रम की प्रासंगिकता और वृत्तिक गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम की पुनर्रचना, विषय वस्तु और आयोजन प्रणाली से संबंधित है।

मूल्यांकन अध्ययन के साथ-साथ प्रशिक्षण की प्रासंगिकता के मूल्यांकन के लिए 5 जिला शिक्षा अधिकारियों का सघन केस अध्ययन आरंभ किया गया और प्रशिक्षण की प्रासंगिकता के प्रति जिला शिक्षा अधिकारियों के दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए विशेष रूप स तैयार की गई एक प्रश्नावली की पुनर्रचना की गई।

2.3.2 शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतराष्ट्रीय डिप्लोमा

अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा जनवरी 1985 में आरम्भ किया गया। पांचवां अंर्ताष्ट्रीय डिप्लोमा जनवरी 1989 में शुरु हुआ और जुलाई 1989 में पूरा हुआ। छठां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा जनवरी, 1990 में शुरु हुआ। इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अधिक संख्या में नामांकन पत्र आए। फलस्वरूप संस्थान को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। पांचवें डिप्लोमा में 16 देशों के 31 भागीदारों की अपेक्षा छठें डिप्लोमा कार्यक्रम में 9 देशों से 17 भागीदार ही शामिल किए गए। छठें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पहली बार मंगोलिया (एशिया महाद्वीप), सियरा-लियोन (अफ्रीका) और शीसेल्स (हिंद महासागर) के प्रतिनिधि भाग लिए। पांचवें और छठें अंतर्राट्रीय डिप्लोमा पाठ्क्रमों में देशवार भागीदार संबंधी विवरण तालिका 2.6 में दिया गया है :

तालिका 2.6

अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी

देश का नाम	भागीदारों की संख्या		
	अं.डि. पांचवां	अं.डि. छठां	कुल
लोकतांत्रिक गणराज्य			
अफगानिस्तान	2	-	2
बंगला देश	1	-	1

1989-90

देश का नाम	भागीदारों की संख्या		
	अं.डि. पांचवां	अं.डि. छठा	कुल
लोकतांत्रिक गणराज्य क्यूवा	1	-	1
इथोपिया	2	-	2
घाना	2	-	2
गणराज्य इरान	-	6	6
जार्डन	1	-	1
जन लोकतांत्रिक गणराज्य लाओ	2	2	4
मलेशिया	-	1	1
मलावी	3	-	3
मंगोलिया गणतंत्र	-	1	1
शाही सरकार नेपाल	1	1	2
नाईजीरिया	2	-	2
फिलीपाइंस	1	-	1
श्रीलंका	8	-	8
लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सियरा लियोन	-	1	1
शीसेल्स	-	1	1
सीरिया	1	-	1
तंजानिया	-	2	2
त्रिनिडाड और तबैको	1	-	1
उगांडा	2	2	4
जिम्बाबवे	1	-	1
योग	31	17	48

अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम दो चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में तीन महीने का सघन पाठ्यचर्या अध्ययन कार्यक्रम और दूसरे चरण में अपने देश में तीन महीने का पर्यवीक्षण परियोजना कार्य होता है। पाठ्यचर्या को दो पाठ्यक्रमों– (1) केंद्रिक पाठ्यक्रम (2) विशेष पाठ्यक्रम में बांटा गया है। केंद्रिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक योजना और प्रशासन सें संबंधित मूल अवधारणाओं की जानकारी दी जाती है। विशेष पाठ्यक्रम भागीदारों द्वारा चयनित क्षेत्र में उच्च अध्ययन सें संबंधित होता है। इस पाठ्क्रम में सम्मिलित विषय हैं–तीसरी दुनिया में शैक्षिक योजना और प्रबंध, शैक्षिक योजना, परिमाणात्मक

1989-90

योजना, संगठनात्मक प्रचलन, कार्मिक और वित्तीय प्रबंध, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, और दूरवर्ती शिक्षा की आधारभूत संकल्पनाएं तथा प्रशिक्षण में संगणक और उसके अनुप्रयोग इत्यादि।

पांचवें डिप्लोमा कार्यक्रम के दौरान संस्थान ने निम्न स्थानों के दौरे का कार्यक्रम आयोजित किया- इंदिरागांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारतीय प्रबंध संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प. पुणे, भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक और अनुसंधान ब्यूरो, पुणे और औरंगाबाद तथा पिछड़ी और घुमंड जातियों के लिए आरक्षित कश्मीर का एक छात्रावास. छठें डिप्लोमा कार्यक्रम के भागीदारों ने आधारभूत स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रबंध के पर्यवेक्षण और रिपोर्ट के लिए दिल्ली, मद्रास, तिरुअनंतपुरम् इरणाकुलम, बंबई, और कलकत्ता के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे के संस्थान थे-केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, एस.सी.ई.आर.टी. दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र श्री अरबिंद आश्रम पांडिचेरी, शांति आश्रम कोयंबूर, एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, बंबई और विश्वभारती विश्वविद्यालय कलकत्ता।

संस्थान के इस डिप्लोमा कार्यक्रम का अनेक वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं ने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से पुनर्निवेशन किया। इनके परिणाम सकारात्मक थे। भारतीय सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति ने कार्यक्रम की प्रशंसा की।

2.4 प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम

विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनेक विषयों पर 27 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लगभग 1000 शिक्षाकर्मियों ने भाग लिया। इनमें 5 कार्यक्रम रा.शै.अ.प्र.प., प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किए गए। 7 कार्यक्रम अगरतल्ला, नेहारली गांव (अरुणाचल प्रदेश), ग्वालियर, मद्रास, पुणे, शिमला और सूरत में हुए।

विद्यालय शिक्षा

विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में 8 अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न स्तरों के 200 शिक्षाकर्मियों ने भाग लिया। इनमें नवोदय विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षा प्रशासकों के 2 कार्यक्रम और एक कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्यों के लिए था। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के लिए 3 कार्यक्रम, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ शिक्षा प्रशासकों के लिए एक कार्यक्रम तथा रेलवे बोर्ड के विद्यालयों के लिए एक कार्यक्रम भी इनमें शामिल हैं।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के अंतर्गत 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें लगभग 400 शिक्षाकर्मियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में अकादमिक स्टाफ कालेजों के लिए 2 कार्यक्रम, स्वायत्त कालेजों के लिए 2 कार्यक्रम और कालेजों के प्राचार्यों और कालेजों की योजना और प्रबंध से संबद्ध संसाधन व्यक्तियों के लिए एक-एक कार्यक्रम शामिल हैं।।

प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में अनौपचारिक, प्रौढ़, सतत् और विस्तार शिक्षा पर दिए गए प्रमुख बल को ध्यान मे रखते हुए संस्थान ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से जिला और उप-जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा की योजना और प्रबंध पर 6 सप्ताह का एक सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

संस्थान में ही पाठ्यचर्या कार्य किया गया जिसमें निम्न विधियां अपनाई गईः व्याख्यान-परिचर्चा, समूह परिचर्चा, केस अध्ययन, सामूहिक कार्य, सतत् अभ्यास और सामूहिक परिचर्चा।

एक सप्ताह का एक क्षेत्र संबंध कार्यक्रम का आयोजन भी किया;

गया। ये चार विभिन्न क्षेत्र थे- एस. आर. सी. लखनऊ, जयपुर, भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे, और गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद।

प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में 3 और कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर 3 कार्यशिविर भी आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम थे– राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध विषय पर 2 अभिविन्यास कार्यक्रम और आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत सामग्रियों और उपकरणों के उत्पादन, प्राप्ति और वितरण पर एक कार्यशिविर।

उपर्युक्त कार्यक्रमों में 200 शिक्षाकर्मियों ने भाग लिया।

संगणक अनुप्रयोग

शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणक के अनुप्रयोग और कालेजों में संगणकों के उपयोग पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 56 भागीदार शामिल हुए।

व्यष्टि स्तरीय योजना और विद्यालय मानचित्रण

मध्यप्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना और विद्यालय मानचित्रण पर 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए विद्यालय मानचित्रण पर एक कार्यशिविर और विद्यालय मानचित्रण परियोजना के अंतर्गत 2 तकनीकी कार्यशिविर भी आयोजित किए गए।
उपर्युक्त कार्यक्रमों में 134 शिक्षाकर्मियों ने भाग लिया।

अन्य कार्यक्रम

शैक्षिक योजना और प्रबंध के लिए परिमाणात्मक तकनीक, भा.प्र.से. के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, सुविधा वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और त्रिपुरा के शिक्षा अधिकारियों के लिए कार्यान्यन नीति पर संस्थान द्वारा एक-एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

25 कार्यशिविर/संगोष्ठी/सम्मेलन

इस वर्ष विभिन्न विषयों पर 30 कार्यशिविर/संगोष्ठी/ सम्मेलना आयोजित किए गए। इनमें 400 शिक्षा कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के विषय इस प्रकार थे:

सुविधावंचित वर्ग

सुविधावंछित वर्गों से संबंधित 4 कार्यशिविर/संगोष्ठी आयोजित किए गए। इनके विषय थे–अ.जा. और अ.ज.जा. की शिक्षा की योजना और प्रबंध, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित सांस्थानिक योजना और प्रबंध, मुस्लिम संचालित संस्थाओं के प्राचार्यों और प्रबंधक और जनजातीय शिक्षा के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी। इन कार्यशिविरों/संगोष्ठियों में 61 शिक्षाकर्मी शामिल हुए।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

शैक्षिक प्रौद्योगिकी और दूवर्ती शिक्षा पर दो कार्यशिविर आयोजित किए गए। इनमें 400 भागीदार शामिल हुए।

विकास के चार दशक : एक समीक्षा सम्मेलन

शिक्षा और शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों की उपलब्धियों, क्षमता और कमजोरी तथा भावी कार्यवाही योजना की आलोचनात्मक समीक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से एक तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों, शिक्षाविदों और प्रमुख व्यक्तियों समेत कुल 95 भागीदार शामिल हुए।

प्रारंभिक स्तर की सांस्थानिक योजना पर श्री जे.पी. नायक स्मृति संगोष्ठी समेत कार्यशिविर भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे के सहयोग से संस्थान ने श्री जे.पी. नायक स्मृति संगोष्ठी कार्यशिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित थे-सांस्थानिक योजना के संकल्पनात्मक ढांचे को कार्यरूप देना, अवयवों की पहचान करना, तकनीकों का विकास करना और

1989-90

कार्यान्वयन रणनीति संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना। इस संगोष्ठी में 49 प्रतिभागी शामिल हुए।

अन्य संगोष्ठी और कार्यशिविर

विभिन्न विषयों पर अनेक संगोष्ठियां और कार्यशिविर आयोजित किए गए। ये विषय थे–सांस्थानिक मूल्यांकन, जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा के अर्थशास्त्र में समस्याएं और अनुसंधान की प्राथमिकताएं, प्रयोगशाला क्षेत्र अभिगम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रबंध, शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएं, संस्थानों के प्रमुखों का कार्यविश्लेषण, जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए कार्य विश्लेषण, शैक्षिक आंकड़ों का प्रदर्शन और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों की स्थिति तथा उनकी भूमिका।

2.6 प्रशिक्षण सामग्री

राज्य/जिला और प्रखंड स्तर के शिक्षाकर्मियों के सामूहिक प्रशिक्षण के लिए 32 माड्यूल पहले ही तैयार किए गये थे। शैक्षिक योजना और प्रबंध पर अनेक दूसरे माड्यूल, आलेख, संख्यिकीय आंकड़े भी तैयार किए गए ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इनका व्यापक उपयोग किया जा सके। इस वर्ष तैयार किए गए माड्यूलों की सूची और दसवें राष्ट्रीय और छठें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा के प्रतिभागियों के परियोजना रिपोर्टों की सूची अनुबंध III में दी गई है।

1989-90

अध्याय 3

अनुसंधान

संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है–अनुसंधान। भारत और विश्व के अन्य दूसरे देशों में योजना की तकनीकें और प्रशासन प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन सहित शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान करना, अनुदान की व्यवस्था करना और अनुसंधान कार्य का संचालन करना संस्थान के मुख्य ध्येय हैं।

शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के संभावित समाधान और नीतिगत मसलों के लिए आवश्यक जानकारी, प्रासंगिक आंकड़े प्रतिपादिन करने के उद्देश्य से व्यष्टि और समष्टि स्तरों पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में संस्थान की अनुसंधान संबंधी गतिविधियां शोध और व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर निर्देशित की जाती हैं। अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी सतत् उपयोग किया जाता है।

इस वर्ष अनुसंधान पर कुल रु० 26.78 लाख व्यय हुआ। (इसमें रु० 12.33 लाख सरकारी अनुदान और 14.45 लाख वित्तीय सहायता अनुदान से) पिछले वर्ष 14.50 लाख रु० अनुसंधान पर व्यय हुआ था। (सरकारी अनुदान से 5.24 लाख रुपए और वित्तीय सहायता अनुदान से 9.26 लाख रुपए) नीपा सहायता योजना के अंतर्गत इस वर्ष रु० 1.27 लाख स्वीकृत किया गया जबकि वर्ष 1988-89 के दौरान यह राशि सिर्फ 0.61 लाख रु० थी।

इस वर्ष 5 अनुसंधान अध्ययन का कार्य पूरा हुआ; 22 अध्ययन चालू हैं और 3 नए अध्ययन स्वीकृत किए गए है।

3.1 पूरा किया गया अध्ययन (5)

3.1.1 महिला और विकास एटलस

इस परियोजना के अनुसंधान दल के सदस्य थे– परियोजना निदेशक, डा. एस.सी. नूना, परियोजना मानचित्रकार, श्री जमालुद्दीन फारुक़ी और परियोजना सहायक सुश्री मधुमिता बंदोपाध्याय । इसके लिए 66200 रु. की राशि स्वीकृत की गयी थी।

संपूर्ण मानव सभ्यता के विकास में महिलाओं के योगदान और उनकी क्षमता की दृष्टि से समसामयिक परिस्थिति में महिला विकास संबंधी प्रश्न एक अहम मसला है। फिर भी देश में महिला विकास संबंधी विभिन्न पक्षों का अध्ययन उपेक्षित है। अतः इस पक्ष से पूरी तरह वाक़िफ होने के कारण इस अध्ययन को महत्त्वपूर्ण समझा गया। इसमें जिला स्तर के आंकड़ों का उपयोग करके देश के समस्त भाग में महिला विकास की स्थिति का विश्लेषण किया है। इसके निष्कर्ष 'महिला और विकास' प्रकाशन में दिए गए हैं

'महिला और विकास' को निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित करके विश्लेषित किया गया है: शिक्षा, जन सांख्यिकी विवाह और प्रजनन, स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधियां, महिलाओं पर अत्याचार, पीने के लिए शुद्ध जल की सुविधाएं और राजनीतिक भागीदारी।

इसके तीन खंड है। पहले खंड में महिला विकास और उसके अंतर-संबंधों के निदान का विश्लेषण किया गया है। दूसरे खंड में महिला विकास से संबंधित विभिन्न पक्षों पर माचचित्र और आरेख दिए गए हैं। तीसरे खंड में प्रतिपादित आंकड़े हैं।

इस अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसमें सभी जिलों समेत भारत में महिलाओं के सामाजिक स्तर को 26 संकेतकों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

1989-90

इस अध्ययन से संकेत मिलता है कि महिला विकास के विविध पक्ष आंतरिक रूप से अंतर-निर्भता प्रणाली से संबद्ध हैं। इससे स्पष्ट है कि महिला विकास के लिए समेकित आपूर्ति· प्रणाली विकसति करने की जरूरत है।

3.12 आंध्र प्रदेश में शिक्षा और विकास पर मोनोग्राफ

इस अध्ययन के परियोजना दल के सदस्य निम्न थे– परियोजना निदेशक, डॉ. एस.सी. नूना; परियोजना मानचित्रकार, श्री जलालुद्दीन फारुकी; परियोजना सहायक, मु. यूनुस,।

परियोजना के लिए 23,800 रुपए की राशि स्वीकृत थी।

आंध्रप्रदेश सरकार के अनुरोध पर संस्थान ने यह अध्ययन अपने हाथ में लिया था। इसमें जिला स्तर के आंकड़ों का उपयोग करके आंध्रप्रदेश में शिक्षा से संबंधित निम्न पक्षों–जनसांख्यिकी, विवाह और प्रजनन, स्वरूप, आर्थिक गतिविधियां और पीने के लिए साफ पानी की सुविधाओं का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन की रिपोर्ट में 3 खंड हैं। पहले खंड सें शिक्षा और विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच के अंतर-संबंधों की प्रकृति से संबंधित एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी दी गई है। दूसरे खंड में शिक्षा और विकास के देश-काल संबंधी प्रतिमान प्रदर्शित करने वाले मानचित्र और आरेख दिए गह हैं। तीसरे खंड में प्रतिपादित आंकड़ों के साथ-साथ चयनित संकेतकों के लिए जिलों के क्रम प्रस्तुत हैं।

अध्ययन सें स्पष्ट है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के साथ शैक्षिक विकास का महत्त्वपूर्ण संबंध है। इसका संबंध लड़कियों के विवाह की आयु, शिशु मृत्यु दर, पारिवारिक रीति रिवाज, कृषि उत्पादकता इत्यादि से हैं। इससे स्पष्ट है कि विकास की तीव्र प्रक्रिया में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

3.13 भारत में उच्च शिक्षा के विशेष चयनित क्षेत्रों में संसाधन निर्धारण की प्रणाली (आई.आई.ई.पी.-वि.अ.आ.-नीपा)

इस अध्ययन दल के सदस्य निम्न थे –परियोजना प्रमुख, डॉ० माधुरी शाह, उप-प्रमुख, प्रो. अनिता वनर्जी, सदस्य डॉ० विकास सत्पाल, श्री आ.के. छाबड़ा, सदस्य और तकनीकी संयोजक, डॉ० जी.डी. शर्मा, परियोजना सहायक, श्री एस मोहंती और डॉ० गुलाब झा ।

इसके लिए आई. आई. ई. पी, पेरिस ने 4000 अमरीकी डालर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए।

विकासशील देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को विकसित देशों के साथ तुलना करने पर पता चलता है कि इस क्षेत्र में विकासशील देश काफी हद तक पिछड़े हुए हैं। विकासशील देशों में भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निवेश सं.रा.अ. के .23 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.00 प्रतिशत हो गया है। यह दर सचमुच ही महत्वपूर्ण है।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे–(अ) नीतिगत प्रणाली के विकास में उच्च शिक्षा के संस्थानों की भूमिका की पहचान करना, जैसे कि कितने सांस्थानिक उत्तरदायित्व बनाए गए हैं और मौलिक नीति के सुझावों पर अमल करने के लिए वास्तविक रूप मे किस सीमा तक संसाधनों का निर्धारण किया गया है; (ब) संसाधन निर्धारण की प्रणाली पर पर अंतर और बाह्य प्रभावों की अंतर-भूमिका और राष्ट्रीय विकास मे उच्च शिक्षा की भूमिका की परीक्षा करना; और (स) राष्ट्रीय विकास सें उच्च शिक्षा को प्रभावी भूमिका अदा करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य सें योजना और रणनीतियों के क्रियान्वयन संबंधी नवाचार का प्रतिपादन करना।

इसके निष्कर्ष के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:

- क्या अनुसंधान तथा विकास के लिए संसाधन निर्धारण से संबंधित तथा अन्य देशों के विकास के साथ-साथ मौलिक प्रौद्योगिकी का विकास हुआ?
- क्या प्रौद्योगिकी आयात के तकनीकी और आर्थिक मसलों की आलोचनात्मक परीक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कोई प्रणाली है? शायद ऐसे निर्णयों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है।

1989-90

• मौलिक प्रौद्योगिकी के विकास सें केवल वास्तविक प्रौद्योगिकी की खाई की पहचान ही नहीं होती बल्कि इससे प्रौद्योगिकी के आधार और उद्योग में आत्मनिर्भता का विकास होता है। इसके साथ ही अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यक संसाधनों में भी आत्मनिर्भरता हासिल होती है। यह प्रक्रिया स्वयं ही प्रौद्योगिकी और अन्य समस्याओं के समाधान से पैदा ही सकती है।

यह अनुसंधान अध्ययन अपने आप में एक अलग किस्म का अध्ययन हैं। उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय विकास सें उसके योगदान के माध्यम सें विकास के जरूरतमंद विशेष क्षेत्रों के विभिन्न पक्षों को इस अनुसंधान सें स्पष्ट किया गया है।

3.1.4 महिला कार्यकारी अधिकारियों की पृष्ठभूमि और स्थिति पर एक जांच अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन का संचालन सुश्री मैरी जोसफीन, प्रोफेसर और अध्ययक्ष, शिक्षा विभाग, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय ने किया।

इसके लिए 10 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी।

इसके उद्देश्य निम्न थे–यदि बालावस्था के अनुभवों और वर्तमान के बीच कोई संबंध हो तो उसका पता लगाना, वर्तमान अवस्था में शिक्षा का योगदान, वर्तमान अवस्था पर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव, उनके कार्यशक्ति में योग देने वाले महत्वपूर्ण पक्षों की पहचान करना, शिक्षा प्रमाली में प्रशिक्षण की जरूरत, महिलाओं का उनके वृत्तिक परिवेश में मूल्यांकन करना, शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रमों का विकास करना जिससे महिलाओं को उदार बनाया जा सके और उनके नेतृत्वकारी गुणवत्ता में संवृद्धि की जा सके, परा स्नातक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के शर्तों के बारे में विचार करना, कार्यकारी पदों के लिए अधिकतर महिलाओं को प्रोत्साहित करना और उपरोक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों का पता लगाना।

अध्ययनों के व्यापक निष्कर्षों से स्पष्ट है कि कार्यकारी पदों के लिए महिलाओं को योग्य बनाने में शिक्षा का अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। विकास के क्षेत्रों में अच्छा वातावरण बनाने की जरूरत है ताकि महिला प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया जा सके। महिलाएं किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम प्रतिभावान नहीं हैं।

शिक्षा के माध्यम से ही महिला के विकास के मार्ग सें खड़ी की गई बाधाएं दूर हो सकती हैं। कम से कम अगली पीढ़ी के लिए विद्यालय स्तर पर समुचित शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती हैं। महिला और पुरुष के बीच समानता या उनके बीच परस्पर निर्भरता का भाव प्रत्येक के अंदर होना चाहिए। इससे दोनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। अन्यथा सुधार में लंबा समय लग सकता है। अच्छी शिक्षा सें ही प्रत्येक की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है। अनुसंधानकर्त्ता ने और सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक कार्यक्रम और प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप संबंधी कई सुझाव दिए हैं।

3.1.5 जिला शिक्षा अधिकारियों का कार्य विश्लेषण : राष्ट्रीय अध्ययन

डॉ. के. प्रेमी, डॉ. (श्रीमती) जया इंदिरेसन और श्रीमती नलिनि जुनेजा परियोजना दल के सदस्य थे।

इस अध्ययन के लिए 35000 रुपए स्वीकृत किए गए थे।

सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन की वर्तमान स्थिति में जि.शि.अ. की भूमिकाएं और क्रिया कलाप को समझने के लिए कार्य विश्लेषण का अध्ययन हाथ में लिया गया था। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जि.शि.अ. के प्रशिक्षण क्षेत्रों की शिनाख्त करना था। इसके विशिष्ट इद्देश्य निम्न थे : जि.शि.अ. द्वारा निष्पादित सभी कार्यों की पहचान करना, कार्यों की प्राथमिकता और समयानुसार उसे क्रम में रखना और उन कार्यों की शिनाख्त करना जिनको वे ठीक से नहीं कर पाते तथा जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

जि.शि.अ. की भूमिकाओं और क्रिया कलाप की गहरी समझ के लिए विभिन्न 5 जिलों–गुटुर (आंध्रप्रदेश), भावनगर (गुजरात), इंदौर (मध्यप्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र) और उदयपुर (राजस्थान) का केस अध्ययन किया गया।

1989-90

इस अध्ययन से प्रशिक्षण के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य क्षेत्र उभरकर सामने आए हैं :

(अ) अकादमिक प्रबंध : विद्यालय खोलना और कक्षा स्तर बढ़ाना; निरीक्षण और पर्यवेक्षण; परीक्षाओं का संचालन विद्यालय संघटनों का प्रबंध; एन.सी.ई.आर.टी. और एस.सी.ई.आर.टी. के कार्यक्रमों का आयोजन, जिला योजना का निर्माण।

(ब) समन्वय और संपर्क : निजी प्रबंध और शिक्षक संगठनों के बीच काम करना; विभिन्न विभागों के साथ संपर्क बनाना; राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच प्रबंध : समुदाय का योगदान।

(स) सामान्य प्रशासन : शक्ति/अधिकार के हस्तगन का विकेंद्रीकरण; आंकड़ा संग्रह; सूचना संकलन और आपूर्ति; शैक्षिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन; जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के साथ सहयोग और समन्वय का मजबूतीकरण।

(द) वित्तीय प्रबंध : वेतन और पेंशन निर्धारण; वार्षिक वजट का निर्माण; लेखा अंकेक्षण; योजना और योजनेत्रर योजनाओं का पुनलेक्षण।

(य) कार्मिक प्रबंध : जांच कार्य का संचालन न्यायिक मामलों की पैरवी तथा कानूनी विवादों को निपटाने वाले कर्मचारी/अध्यापिका की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण।

इसमें वर्तमान स्थिति के आधार पर विश्लेषण किया गया हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता और विशेष रूप से जि.शि.अ. की अपेक्षित भूमिका के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव पर ध्यान दिया गया है।

3.2 चालू अध्ययन (22)

3.2.1 सन् 2000 में शिक्षा: एक विस्तार संप्रेक्ष्य' विषय पर परियोजना

परियोजना का पुनर्गठित चरण जून, 1989 में शुरू हुआ।

इस परियोजना दल के सदस्य हैं–श्री प्रकाश, परियोजना निदेशक, सुश्री टी. बुड़ागोहाइन, सुश्री सुमिला चौधरी और सुश्री आभा अग्रवाल, परियोजना सहायक।

इस परियोजना के लिए 4.08 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। पुनर्गठित परियोजना के मुख्य बिंदु हैं : (अ) शैक्षिक व्यय का विश्लेषण; (ब) विद्यालय शिक्षा पूरा करने में लगा औसत वर्ष; (स) शिक्षा के विकास के लिए दीर्घावधि का संप्रेक्ष्य और (द) मध्यम अवधि के प्रक्षेपण।

पुर्नगर्ठित चरण संतोषजनक रूप से चालू हैं। इस वर्ष निम्न लिखित 13 अध्ययन पूरे हुए:

(1) भारत में शैक्षिक व्ययः एक प्रवृत्तिमूलक विश्लेषण
(2) भारत में शैक्षिक व्यय के निर्धारकः परीक्षित वैकल्पिक परिकल्पना
(3) भारत में शिक्षा की इकाई लागतः परीक्षित वैकल्पित परिकल्पना
(4) प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण:एक सामान्य समतुल्यता के प्रकार का नीतिगत प्रतिरूप
(5) शिक्षा की निजी मांग : एक संभावित अधिगम
(6) एक अंतर उद्योग मॉडल : शिक्षा का आर्थिक प्रभाव
(7) भारतमें शैक्षिक संस्थानों के त्रिविमीय प्रतिमान : त्रिविमिय और वास्तविक प्रतिमानों के बीच विचलन
(8) शिक्षा और अर्थव्यवस्था के संतुलित अधिकतम विकास का एक मॉडल
(9) जनांकिकी दबाव और प्रवसन : मेघालय का एक केस अध्ययन
(10) घटकों में उपघटन के विकास का एक मॉडल
(11) आर्थिक विकास और साक्षरता : अंतर्राष्ट्रीय अनुभव
(12) भारत में साक्षरता के विकास के निर्धारक :

1989-90

संभावित ढांचे में देशकालिक सापेक्ष आयाम
(13) विद्यालय में संक्रमण, विद्यालय छोड़ने वाले और विद्यालय का औसत वर्ष

3.2.2 भारत में साक्षरता : एक देश कालिक विश्लेषण (1901-1981)

परियोजना दल के सदस्य निम्न हैं : डॉ.एस.सी. नूना, परियोजना निदेशक,श्री ओ.डी. त्यागी/श्री जमालुद्दीन फारुकी, परियोजना मानचित्रकार और श्री राजपति राम और सुश्री हरजिंदर कौर परियोजना सहायक।

इस परियोजना के लिए रु० 1,89,000 स्वीकृत है।

बहुमुखी विकास में साक्षरता के महत्त्व को मद्देनजर रखते हुए साक्षरता के प्रचार प्रसार के लिए सभी तरह के प्रयास फिर किए जा रहे हैं। यद्यपि इस शताब्दी के आरंभ में साक्षरता की जो स्थिति थी उसको देखते हुए आज की स्थिति कुछ हद तक सही मानी जा सकती है। फिर भी इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देश की आबादी की 64 प्रतिशत आबादी अभी भी निरक्षर है। इस अध्ययन में जिला स्तर के आंकड़ों की मदद से भारत में साक्षरता के विस्तार का विश्लेषण किया गया है ताकि उसके निर्धारकों की पहचान हो सके और कार्यान्वयन रणनीति में उसी आधार पर परिवर्तन किया जा सके।

इस अध्ययन के तीन घटक हैं : सन् 1901 से साक्षरता प्रतिमान का विश्लेषण और जिला स्तर पर इसके विस्तार की प्रवृत्ति; द्वितीयक आंकड़े के प्रयोग से भारत में साक्षरता के निर्धारक और आधारभूत स्तर पर साक्षरता को प्रभावित करने वाले घटक।
यह अध्ययन जल्दी ही पूरा होने वाला है।

3.2.3 गुड़गांवा जिले के पुनहाना प्रखंड में शैक्षिक योजना और प्रशासन में कार्यान्वयन रणनीतियों के अध्ययन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान (प्रौढ़ समेत प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण) (ए.आर.आई.एस.इ.) (तीसरा चरण)

परियोजना दल के सदस्य निम्न हैं : परियोजना निदेशक, प्रो. सत्यभूषण, परियोजना प्रभारी डॉ० आर. गोविंदा, परियोजना सहयोगी, डॉ. प्रमिला मेनन और परियोजना सहायक सतपाल खटाना।

इस परियोजना के लिए 3,46,700 रुपए स्वीकृत किए गए हैं

अनुशिक्षकों और स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं के लिए जून तथा सितम्बर 1989 में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले चरण में अध्ययन के लिए चुने गए तीन गांवों–छड़ोदा (नाह), पटुका और सराय में परियोजना के तहत नवसाक्षर व्यक्तियों को दिनांक 2 अक्टूबर, 1989 को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रमाणपत्र वितरण समारोह के अवसर पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जामिया मिलिया इस्लामिया एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., दो स्वयं सेवी अभिकरण, प्रखंड शिक्षा अधिकारीगण, 8 पड़ौसी गांवों के सरपंच और जिला स्तर के प्राधिकारी उपस्थित थे।

प्रौढ़ नव साक्षरों का मूल्यांकन प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मानदंड के अनुसार किया गया। साक्षरता मिशन को और अधिक कारगर बनाने के लिए कई क्षेत्रीय दौरे भी किए गए थे।

दो स्वयंसेवी संगठन–मेवात समाज और शिक्षा विकास सोसायटी (बिसरू) और मेवात शैक्षिक सोसायटी छरोड़ा (नूह) ने अपने क्षेत्र के पांच गांवों में पूर्ण निरक्षरता उन्मूलन का आंदोलन आरंभ किया। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय और राज्य संसाधन केंद्र जामिया मिलिया में प्रशिक्षण और अधिगम के लिए तैयार की गई सामग्रियां नीपा द्वारा प्रदान की गईं।

3.2.4 कालेजों के प्रभावी कार्य और विकास : एक क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन (दूसरा चरण)

अनुसंधान दल के सदस्य हैं– परियोजना निदेशक डॉ० जी.डी. शर्मा, परियोजना सहअध्येता डॉ० एम.एम. रहमान, परियोजना सहायक डॉ० (श्रीमती) कौसर विजारत/श्री जेम्स जोस और सुश्री दीपा सहाय।

इस अध्ययन के लिए 3,29,400 रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

1989-90

कुछ कालेजों की गतिविधियों के सभी पक्षों–अकादमिक, प्रशासनिक और समुदाय के साथ इनके संबंध जैसे, समुदाय विकास के संसाधन के रूप में कालेज को समझने के लिए इस परियोजना को आरंभ किया गया था।

नीपा के परियोजना स्टाफ ने कालेजों के शिक्षकों के साथ सामान्य योजना के अभ्यास के एक अंश के रूप में एक सांस्थानिक योजना का मॉडल विकसित किया।

इस वर्ष के दौरान परियोजना से संबंधित निम्न लिखित रिपोर्ट तैयार किए गए हैं :

(1) कालेजों की प्रभावी गतिविधियां और विकास : एक क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना (एक प्राथमिक रिपोर्ट-द्रोणाचार्य राजकीय कालेज गुड़गांव)

(2) कालेजों की प्रभावी गतिविधियां और विकास : एक क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना (एन.बी.जी.एस.एम. कालेज, सोहना पर रिपोर्ट का एक प्रारूप)

(3) समुदाय विकास के लिए कालेज एक संसाधन केंद्र के रूप में: कार्यान्वयन का संकल्पनात्मक ढांचा और प्रक्रिया

(4) हडसारू गांव की सामाजिक-आर्थिक दशा

(5) हडसारू गांव की शैक्षिक दशा

(6) ग्रामीण समुदाय के विकास में विज्ञान का अनुप्रयोग : मृदा विश्लेषण की एक रिपोर्ट

3.2.5 जनजाति प्रदेश में शैक्षिक विकास का एक अध्ययन

डॉ० के. सुजाता, परियोजना निदेशक और परियोजना सहायक श्री वी.पी. एस. राजू इस परियोजना दल के सदस्य हैं।

इसके लिए रु० 1,15,000 स्वीकृत किया गया है।

इस अध्ययन के उद्देश्य हैं–विद्यालय प्रवाह क्षेत्र समेत परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्षों को मद्देनजर रखते हुए शैक्षिक सुविधाओ के वितरण के वर्तमान मानदंड के संबंध में प्रादेशिक क्षेत्र का अध्ययन करना, यहां गुणवत्ता शिक्षा-छात्र अनुपात, शिक्षक और योग्यता और विद्यालय स्तर पर अधिरचनात्मक सुविधाओं से आंकी गयी हैं; शिक्षकों की सामाजिक-भाषायी पृष्ठभूमि और जनजातियों और छात्रों के प्रति उनकी मनोवृत्तियों का अध्ययन करना; नामांकन के विस्तार, विद्यालय छोड़ने की दर और सफलतापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति का अध्ययन करना; मदवार शिक्षा की इकाई लागत का पुनरीक्षण करना और अंतर-विभागीय समन्वय की प्रकृति का पता लगाना यानि कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि विभागों के साथ शिक्षा विभाग के समन्वय की प्रकृति का शिनाख्त करना; प्रतिदर्श इलाकों में जन जातियों की शैक्षिक प्रगति में समन्वयित अभिगम को शिक्षा के संदर्भ के साथ समझना और जन जातियों के शैक्षिक विकास के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना के रूप सें एक-कार्रवाई योजना तैयार करना। इस अध्ययन में उद्देश्यात्मक प्रतिदर्श की स्तरण विधि का उपयोग किया गया है। इसके लिए उपयोजना क्षेत्र में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता के दो जिलों का चयन किया गया। (इस्ट गोदावरी और वारांगल)

साक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्नावली के माध्यम से परिवारों, शिक्षकों और विद्यालयों से संबंधित प्राथमिक आंकड़े एकत्र कर लिए गए हैं। आई.टी.डी.ए. और जिला तथा राज्य स्तर के शिक्षा विभागों से भी द्वितीय आंकड़े एकत्र कर लिये गए हैं। परिवारों और शिक्षकों से संबंधित आंकड़ों का संगणक में संसाधन कर लिया गया है। तालिकाएं भी तैयार हैं। अब रिपोर्ट लिखी जा रही है।

3.2.6 विद्यालय मानचित्रण पर परियोजना

इस परियोजना दल के सदस्य हैं–श्री एम.एम. कपूर, परियोजना निदेशक, प्रो.डी.एन. एब्रोल, परियोजना अध्येता, श्री आर.के सोलंकी, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता और सुश्री अनिता नूना परियोजक सहायक।

इसके लिए रु० 8.05 लाख स्वीकृत किया गया है।

परियोजना के प्रथम चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को

1989-90

विद्यालय मानचित्रण के लिए तकनीकी सहायता दी गई। 19 राज्यों और के.शा.प्र.के. लगभग 50 अधिकारियों के लिए राष्टयीय स्तर के तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विद्यालय मानचित्रण की तकनीक में उनका अभिविन्यास किया गया । इसके अतिरिक्त राज्य स्तर के आठ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, विहार, मध्यप्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा से लगभग 280 भागीदार शामिल हुए। इनके साथ ही अगस्त, 1989 में परियोजना कार्य का पहला चरण पूरा हुआ।

परियोजना कार्य का दूसरा चरण सितंबर, 1989 में शुरू हुआ। इसके अंतर्गत विद्यालय मानचित्रण पर क्रियात्मक अध्ययन शुरू किया गया।

दिसंबर 1989 में पहला तकनीकी कार्यशिविर आयोजित किया गया जिसमें 6 राज्यों के परियोजना अधिकारी भाग लिए। इस कार्य शिविर में आंकड़ा संग्रह के उपकरण, प्रतिदर्श प्रारूप, समेतिक योजनाएं, रिपोर्ट के प्रारूप और विषय आलेख तैयार किया गया। राजस्थान के चुरु जिले में उपकरणों का क्षेत्र परीक्षण किया गया तथा उनमें आवश्यक संशोधन भी किए गए। मार्च 1990 में दूसरा तकनीकी कार्यशिविर आयोजित किया गया जिसमें 4 राज्यों के परियोजना अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशिविर में उपकरणों के संशोधित प्रारूप पर विचार-विमर्श किया गया।

इस परियोजना के एक भाग के रूप में विदिशा जिले (म.प्र.) में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना और विद्यालय मानचित्रण पर चालू परियोजना में मध्यप्रदेश सरकार को अकादमिक सहायता दी गई। फनके अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया; उपकरण विकसित किए गए और कार्यान्वयन रणनीतियां बनाई गईं।

इस परियोजना में पहले 10 राज्यों को ही शामिल किया गया था। बाद में अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसमें शामिल होने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने अनुरोध किया था। कार्यक्रम सलाहकार समिति के सलाह पर दिल्ली को शामिल किया गया ताकि नगरीय क्षेत्रों में विद्यालय माचित्रण की समस्याओं का अध्ययन किया जा सके।

3.2.7 शैक्षिक प्रशासन का दूसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण

इस परियोजना दल के सदस्य निम्न हैं : श्री एम. एम. कपूर, परियोजना निदेशक; डॉ. जे.सी. गोयल, परियोजना अध्येता; श्री आर.एस. त्यागी, परियोजना सह-अध्येता; श्री.वी.एन. आलोक और श्री ए.के. सिन्हा, परियोजना सहायक और श्री भारत भूषण, परियोजना मानचित्रकार।

इस परियोजना के लिए रु. 17.04 लाख स्वीकृत किया गया है।

नामांकन और वित्तीय प्रावधानः सभी राज्यों/कें.शा.प्र. में सर्वेक्षण कार्य के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य के शिक्षा सचिव से राज्य स्तर के परियोजना निदेशक–संपर्क अधिकारी नामित करने के लिए अनुरोध किया गया। सर्वेक्षण के संचालन के लिए राज्यों/के.शा.प्र. को वित्तीय राशि दी गई।

सर्वेक्षण उपकरणः व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को छोड़कर शैक्षिक प्रशासन के सभी क्षेत्रों और स्तरों को समाहित करने वाले राज्य स्तर, क्षेत्र स्तर और सांस्थानिक स्तर की तीन प्रश्नावलियों के प्रारूप तैयार किए गए।

राष्ट्रीय कार्य शिविर : नीपा में 12-15 दिसंबर, 1989 और 26-27 फरवरी, 1990 को राज्य स्तर के परियोजना निदेशकों के दो राष्ट्रीय तकनीकी कार्यशिविर आयोजित किए गए। इन कार्यशिविरों में सर्वेक्षण के लिए तैयार किए प्रतिदर्श की रूपरेखा, सर्वेक्षण उपकरणों के प्रारूप और राज्य स्तर की क्रियात्मक योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इन कर्यशिविरों में 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परियोजना निदेशक-संपर्क अधिकारी भाग लिए।

राष्ट्रीय सलाहकार समिति : राष्ट्रीय सलाहकार समिति की पहली बैठक 20 फरवरी, 1990 को हुई। इस बैठक में 22 विशेषज्ञ/अधिकारी भाग लिए। परियोजना की रूपरेखा, क्षेत्र

1989-90

विस्तार, सर्वेक्षण उपकरण, कार्य प्रणाली और परियोजना की वर्तमान स्थिति पर समिति ने विस्तृत रूप से चर्चा की। सर्वेक्षण के संचालन के लिए तैयार किए गए सर्वेक्षण प्रश्नावलियों और क्रियात्मक रणनीतियों के प्रारूपों में कुछ संशोधन करके समिति ने अपनी स्वीकृति दे दी।

सर्वेक्षण उपकरणों का मुद्रण : राष्ट्रीय सलाहकार समिति की संस्तुतियों के आधार पर सर्वेक्षण उपकरणों को अंतिम रूप दिया गया और मुद्रण के लिए भेज दिया गया।

संदर्भ सूची का निर्माण : परियोजना दल ने शैक्षिक प्रशासन से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुसंधान कार्यों और राज्यों/के.शा.प्र. के दस्तावेजों के संक्षिप्त विवरण सहित संदर्भ सूची करण और संबंधित साहित्यों का पुनरीक्षण कार्य आरंभ किया।

3.2.8 लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध का एक अध्ययन: भारत के लिए पाठ और उनके निहितार्थ

डा. अंजना मंगलागिरि, परियोजना निदेशक और श्री जी. गुणशेखरन, परियोजना सहायक इस परियोजना दल के सदस्य हैं।

इस अध्ययन के लिए रु० 1,46,200 स्वीकृत किया गया है।

परियोजना के प्रथम चरण में लैटिन अमरीका के दो प्रदेशों–इक्वाडोर और कोलंबिया में शैक्षिक विकास से संबंधित उपलब्ध सूचनाएं एकत्र करने का प्रयास किया गया। इसी के अनुसार एक संदर्भसूची तैयार की गई। इन प्रदेशों के शैक्षिक विकास से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र किए गए और उन्हें संकलित किया गया। फिर भी विश्व में इन प्रदेशों में अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित सूचनाएं बहुत ही अपर्याप्त थीं।

अतः संयुक्त राज्य अमरीका, नीदरलैंड और फ्रांस के विश्वविद्यालयों के विभागों से संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों से इस प्रकार की सामग्रियों के लिए पत्राचार आरंभ किया गया। लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा पर उक्त देशों के विद्वान निम्न संगठनों में कार्य कर रहे हैं–फ्लोरिडा स्टेट विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सांस्कृतिक विकास शिक्षा कार्यक्रम, थर्ड वर्ड सेंटर, नीजमेगन और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस। अतः इन देशों का चयन इसी को ध्यान में रखकर किया गया। थर्ड वर्ड सेंटर नीजमेगन, नीदरलैंड के प्रो. गेरिट हूजर ने लैटिन अमरीका पर गहन अध्ययन किया है। वे जब जनवरी, 1990 में भारत आए तो उनसे एक बैठक की गई थी।

3.2.9 कालेजों के विकास में कालेज विकास परिषदों की भूमिका का एक अध्ययन : 10 चयनित कालेज विकास परिषदों का एक सघन अध्ययन

इस परियोजना दल के सदस्य हैं– डॉ. जया इंदिरेसन, परियोजना निदेशक; सुश्री तुलसी और श्री कल्याणी बिरादर परियोजना सहायक।

इस अध्ययन के लिए रु. 1,26,800 स्वीकृत किया गया है।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं –कालेजों के विकास परिषदों के योगदान कार्य के दौरान क्रियात्मक दबाव और सुगम्यता के पक्षों की पहचान करना और कालेजों के विकास में का.वि.प. की भूमिकाओं को मजबूत बनाने के लिए यदि आवश्यकता हो तो कोई सलाह देना।

इसको ध्यान में रखकर देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को कायम करते हुए 10 का.वि.प. का चयन किया गया। अध्ययन के लिए कालेज विकास परिषदों के निदेशकों, विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों और अन्य अधिकारियों से विशेष रूप में पूर्वनियोजित साक्षात्कार कार्यक्रम के आधार पर बातचीत की गई। का.वि.प. के क्रियाकलापों पर कालेजों के प्राचार्यों की राय जानने के लिए उनसे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बात-चीत की गई। इसके अलावा 20 कालेज विकास परिषदों से उनकी गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित दस्तावेज और रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

1989-90

का.वि.प. की चार प्रमुख भूमिकाओं –अकादमिक नेतृत्व की भूमिका, संचारेक्षण और कार्यान्वयन भूमिका, समन्वयकारी भूमिका और योजनाकारी भूमिका की पहचान की गई है। का.वि.प.–की अपनी प्रभावी भूमिकाएं निभाने में पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा हैं।

3.2.10 भारत के अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों के साक्षरता स्तर के बीच की विषमताओं का जिलेवार विश्लेषण

इस परियोजना दल के सदस्य हैं–डॉ० वाई.पी. अग्रवाल, परियोजना निदेशक और सुश्री सारिका सिबू और अशोक कुमार, परियोजना सहायक।

इस अध्ययन के लिए रु० 1,44,396.30 स्वीकृत हैं।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं–अनुसूचित जातियों और अन्य के बीच विषमताओं को स्थिर बनाने वाले कारकों की उत्पत्ति का पता लगाना, अनुसूचित जाति की आबादी के विभिन्न स्तरों पर साक्षरता के प्रसार के स्थानिक प्रतिमानों की शिनाख्त करना, गैर अनुसूचित जाति की आबादी में समानताओं और असमानताओं का परीक्षण करना, साक्षरता स्तरों के बीच के रिक्त स्थान को मापने के लिए समुचित प्रणाली का विकास करना, साक्षरता दरों की असमानता के सूचकों और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के बीच के संबंध की प्रकृति की परीक्षा करना और शिक्षा प्रणाली में असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्र-विशेष नीतियों का विकास करना।

इस अध्ययन में जनगणना और चौथा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण 1978 के आंकड़े उपयोग में लाए जाएंगे। अनुसंधान अध्ययनों का साहित्य सर्वेक्षण शुरु किया गया है। जिलेवार आंकड़ों का संगणक संसाधन करने के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3.2.11 शैक्षिक संस्थाओं में स्वायत्तता का प्रबंध

परियोजना दल के सदस्य हैं–डॉ० (श्रीमती) के. सुधा राव, परियोजना निदेशक, श्री जार्ज मैथ्यू और सुधीर सामंत्रे, परियोजना सहायक ।

इसके लिए रु. 1,52,100 स्वीकृत किया गया है।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: यह अध्ययन करना कि संस्थानों में किस प्रकार से और कैसी स्वायत्तता प्रयोग में लायी जाती है और कौन सी स्वायत्तता स्वीकृत की गई है, कालेज स्वायत्तता की संरचना और कार्यात्मक मसलों का विश्लेषण करना, छात्रों और शिक्षकों के स्वायत्तता संबंधी दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना, गुणवत्ता संबंधी दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना; गुणवत्ता निष्पादन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कार्यों की पहचान करना, शिक्षा के गुणवत्ता सुधार में स्वायत्तता के सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने में स्वायत्तता का प्रयोग करने में स्वायत्त कालेजों के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना और अंत में उच्च अधिगम के संस्थानों में स्वायत्तता के प्रभावशाली प्रयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक प्रबंधकीय सहयोग की शिनाख्त करना।

सोद्देश्यात्मक प्रतिदर्श विधि के माध्यम के अनुसार इस अध्ययन के लिए आंकड़ा एकत्र करने की योजनाएं बनाई गईं हैं। इसके लिए सभी प्रकार के स्वायत्त संस्थानों से दस्तावेज विश्लेषण तकनीकों के माध्यम, प्रबंध-विशेषज्ञों, उच्च शिक्षा के निदेशकों, उप-कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों स्वायत्त और गैर स्वायत्त कालेजों के शिक्षकों और छात्रों से विचार-विमर्श करके जानकारी हासिल करने की योजना है। इसके अलावा प्रश्नावली विश्लेषण के माध्यम से स्वायत्तता के विभिन्न पक्षों के विस्तृत अध्ययन की भी योजना बनाई गई है।
परियोजना से संबंधित साहित्य की समीक्षा की जा रही है और आंकड़ा एकत्र करने के लिए प्रश्नावलियों का विकास किया जा रहा है।

3.2.12 महाराष्ट्र की शिक्षा और विकास पर मोनोग्राफ

परियोजना दल में शामिल हैं–डॉ. एस.सी. नूना, परियोजना निदेशक; श्री जमालुद्दीन फारुकी, परियोजना मानचित्रकार; सुश्री मधुमिता बंदोपाध्याय, श्री मु. युनूस परियोजना सहायक। इस परियोजना के लिए रु. 36,520 स्वीकृत है।

1989-90

जैसा कि आम धारणा है, विकास की धारा को तीव्र बनाने में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वस्तुतः यह धारणा व्यावहारिक परख का एक मुद्दा हैं। प्रस्तुत अध्ययन इस दिशा में एक कदम है। महाराष्ट्र के जिला स्तर के आंकडों का उपयोग करके शिक्षा और अन्य विकास परिक्षेत्रों के बीच के संबंध को खोजने का एक प्रयास किया जा रहा है। उसमें मानचित्र, आरेख और वर्णप्रतीकी की मदद ली जा रही है। आंकड़ा-संसाधन किया जा चुका है। मानचित्रकारी का कार्य चालू हैं। इस अध्ययन में निम्न पक्ष शामिल हैं : शिक्षा, जनांकिकी, विवाह-प्रजनन, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियां।

3.2.13 बेसिक शिक्षा सेवा की गुणवत्ता (नीपा-आई.आई.ई.पी. सह-अध्ययन)

परियोजना दल के सदस्य हैं–डॉ. आर. गोविन्द, परियोजना निदेशक; डॉ. आर.पी. कथूरिया, परियोजना संयोजक (क्षेत्रीय कार्य); डॉ. जी.पी. सिंह और डॉ. कैलाश परियोजना सह-अध्येता, डॉ. श्री एम.के. शर्मा और श्री राजेन्दरपाल, परियोजना सहायक।

इस परियोजना के लिए रु. 6,64,900 स्वीकृत है। परियोजना का सामन्य उद्देश्य है– इन संस्थानों की गुणवत्ता सुधार की पर्याप्त रणनीतियों की कारगर बनाने के लिए बेसिक शिक्षा के संस्थानों में दी जा रही शिक्षा और उसके परिणामों का विश्लेषण करना।

यह परियोजना मध्यप्रदेश के 5 विभिन्न क्षेत्रों में चालू किया जा रहा है। इन क्षेत्रों से संबंधित प्रासंगिक सूचनाएं एकत्र की गई हैं और क्षेत्र विवरण का प्रारूप तैयार किया गया है। विद्यालयों के कार्यों की गुणवत्ता के अध्ययन के लिए सात प्रश्नावलियों/साक्षात्कार कार्यक्रमों का एक सेट तैयार किया गया और प्रत्येक क्षेत्र के 12 चयनित विद्यालयों में वितरित किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

चयनित विद्यालयों के कक्षा 4 और 5 स्तर के छात्रों की भाषा (हिन्दी) और अंकगणित के क्षमता स्तर का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण प्रपत्र विकसित किए गए हैं। अंतिम रूप से तैयार किए गए परीक्षण पत्र मुद्रित कराए गए और मार्च, 1990 के तीसरे सप्ताह में परीक्षण कार्य शुरु किया गया। मांडा के आदिवासी इलाके में मार्च, 1990 के अंत तक परीक्षण कार्य पूरा हो गया। अन्य स्थानों पर मार्च के बाद भी परीक्षण कार्य जारी रहा। परियोजना अधिकारी परीक्षण कार्य का सतत निरीक्षण करते रहे। परीक्षण पत्रों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

3.2.14 महिला कालेजों के प्रशासकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान (एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय के सहयोग से)

परियोजना दल के सदस्य हैं–डॉ. जया इंदिरेसन, परियोजना निदेशक, डॉ. जी.डी. शर्मा, के सुधा राव, श्रीमती राजश्री परियोजना सहायक (नीपा) और डॉ. लीना डी सुजा और डॉ. उषा टक्कर (एस.एन.डी.टी. विशविद्यालय, बंबई)

इस परियोजना के लिए रु० 10,000 स्वीकृत है।

देश में लगभग 700 महिला कालेज हैं। इन कालेजों के क्रिया कलापों को प्रभावी और सुगम बनाने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि इनके वरिष्ठ प्रशासकों के लिए कालेजों की योजना और प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुगम्य और प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान के लिए यह अध्ययन शुरू किया गया है।

निम्नांकित पक्षों से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली की रुपरेखा बनाई गई है :

(1) सभी कालेजों के प्रशासन से संबंधित सामान्य योजना और प्रबंध के समान मुद्दे,
(2) महिला छात्राओं की शिक्षा के विशेष संदर्भ में कुछ मुद्दे,
(3) प्रशासकों के रूप में महिलाओं से संबंधित कुछ नाजुक मसलें,
(4) महिला प्रशासकों के व्यक्तिगत आंकड़े।

लगभग 100 कालेजों से जवाब आ गए हैं। आंकड़ा-विश्लेषण कार्य जारी है।

3.2.15 प्रारंभिक शिक्षा की संगणक संसाधित योजना (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)

परियोजना दल के सदस्य निम्न हैं : श्री संजय दासगुप्ता, संयोजक, श्रीमती अनिता चोपड़ा, मु. अहमद अंसारी और श्री अनूप बनर्जी।

इस परियोजना के लिए 31 मार्च, 1990 तक के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने रु० 10,22,534 स्वीकृत किया है।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के विकास का निर्णय किया गया जिसे कोप की संज्ञा दी गयी। यानि शिक्षा की संगणक संसाधित योजना (कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग फार एजुकेशन) (अतः आगे इसे कोप/डी.एस.एस. से ही जाना जाए)

सभी सात पायलट जिलों–ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, भींड, गुना, दतिया और अलीगढ़ को प्रणाली परीक्षण के लिए चुना गया।
इन जिलों में निम्न कार्य पूरे किए गए :

इनमें से व्यापक सूचनाएं एकत्र करने के लिए इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया ताकि 'उपयोग में आ सकने वाले' सूचनाओं से 'उपयोग में आने वाले' सूचनाओं को ही रखा जाए।

आंकड़ा प्रपत्र का विकास किया गया ताकि विद्यालय के प्राचार्य और जिला स्तर के आंकड़ा संग्रह संचालक को आंकड़ा संग्रह करने में कठिनाई न हो। वर्ष में एक बार भराजाने वाला एक 7 पृष्ठीय प्रपत्र भी विकसित किया गया। आंकड़ा संग्रह का प्रशिक्षण विद्यमान संप्रेषण चैनल के माध्यम से दिया गया। प्रपत्र मे लोक प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। स्थानीय भाषा के सरल शब्द प्रयोग में लाए गए।

तीन सदस्यों का एक कार्यदल ने साफ्टवेअर का विकास किया। इसमें पायलट जिलों में कार्यरत दो क्षेत्र अधिकारियों ने विशेष रूप से सहयोग दिया।

अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साफ्टवेअर का विकास कार्य चालू है। मध्यप्रदेश के 54 शैक्षिक जिलों और राजस्थान तथा विहार के तीन-तीन जिलों में कोप/डी.एस.एस. प्रणाली का क्रियान्वयन का कार्य आरंभ किया गया है।

3.2.16 जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए संचारेक्षण सूचना प्रणाली (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)

परियोजना दल के सदस्य हैं– श्री संजय दासगुप्ता, परियोजना संयोजक, सुश्री सुषमा पोपली, रविंदर अरोड़ा, रघूराम राव और सुश्री दंदपानी। मानव संसाधन विकस मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने इस परियोजना के लिए 31 मार्च, 1990 तक के लिए रु. 7,23,300 स्वीकृत किया है।

आधारभूत स्तर के उप्रयोगकर्त्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी साफ्टवेअरों का विकास किया गया है। ये साफ्टवेयर हैं–(अ) अनौप.शि.के. विश्लेषण, (ब) अनुदेशक विश्लेषण, (द) शिक्षार्थी दाखिला विश्लेषण, (य) शिक्षार्थी उपस्थिति विश्लेषण (र) अनौप.शि.के. आंकड़ा आधार (व) अपवाद चयन की सूची, (श) वित्तीय लेखा। ये साफटवेअर अब हिन्दी में भी उपलब्ध हैं।

'न्यूजलेटर' का पहला अंक प्रकाशित हुआ है और दूसरा अंक प्रेस में है।

उपयोगकर्त्ताओं के लिए संदर्शिका भी अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित हो रही है

इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि कोप/अनौप.शि. साफ्ट्वेअर मध्य प्रदेश में तीन चरणों में क्रियान्वयित किया जाए। इसके पहले दो चरण पूरे हो गए हैं। भोपाल में प्रस्तावित

1989-90

क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के साथ ही इसका तीसरा चरण आरंभ किया जाएगा।

3.2.17 उच्च शिक्षा में विद्यमान सुविधाओं/संसाधनों के प्रभावी उपयोग का एक अध्ययन (योजना आयोग द्वारा प्रायोजित)

परियोजना दल के सदस्य हैं–डॉ० जी.डी. शर्मा, परियोजना निदेशक, डॉ. एफ. क़मार, परियोजना अध्येता और सुश्री नीलम कगद्याल।

इस अध्ययन के लिए रु० 56,000 स्वीकृत है।

यह अध्ययन भारत के कालेजों और विश्वविद्यालयों में संसाधनों के उपयोग पर प्रकाश डालता हैं और विद्यमान सुविधाओं /संसाधनों के और अधिक प्रभावी उपयोग के तरीकों और माध्यमों का सुझाव देता है। इस अध्ययन में संसाधन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखा गया है। अतः इसमें सभी प्रकार के संसाधन जैसे वित्तीय, भौतिक, मानव और समय सब कुछ शामिल हैं।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं–रणनीतिक घटकों की संपूरकता की कमी, समुचित योजना संचारेक्षण और समन्वय प्रणाली और निरंतर दबाव की कमी का अध्ययन करना।

संसाधन के प्रभावी या अप्रभावी उपयोग के कारकों के पुनरीक्षण में अनेक संकेतों की मदद से समस्याओं के विश्लेषण का प्रयास किया गया है। पुनरीक्षण में प्रयुक्त संकेत हैं– उच्च शिक्षा के संस्थानों का आकार और आर्थिक क्षमता कार्य दिवसों की सूची, मानव संसाधनों के उपयोग की सूची, प्रशासन की क्षमता, पुस्तकालय और प्रयोगशाला स्टाफ, भौतिक व अधिरचनात्मक सुविधाओं के उपयोग की सूची, निर्धारित क्षमता और वित्तीय प्रशासन की क्षमता।

कालेज और विश्वविद्यालय के लिए अलग-अलग संरचनात्मक प्रश्नावलियां और आंकड़े कार्यक्रम के दो सेट तैयार किए गए। जब अनुसंधान की रूपरेखा तैयार की जा रही थी तभी प्रतिदर्श चुनाव का कार्य भी आरंभ किया गया। इसके बाद एन.सी.टी.-II के लिए एकत्र आंकड़े संग्रहित किए गए। अन्य स्रोतों से भी कुछ आंकड़े एकत्र किए गए।

एकत्र आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया और एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई जिसे फरवरी, 1990 में योजना आयोग को भेज दिया गया।

3.2.18 भारतीय विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंध (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए दिसंबर 1988 में रु० 48000 स्वीकृत किया गया था। इस अध्ययन का कार्यभार भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलौर की मालती सोमैया ने लिया है।

मैसूर विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ से विचार विमर्श के पश्चात अध्ययन के उपकरण तैयार किए गए। साहित्यक पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो गया है तथा प्रश्नावली भी तैयार कर दी गई है। आंकड़ा संसाधन और रिपोर्ट लेखन कार्य साथ-साथ चल रहे हैं।

3.2.19 कक्षा स्तर के सापेक्ष दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों की लागत का अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए फरवरी 1989 में रु. 59,600 स्वीकृत किया गया। प्रो. रुद्रदत्त, प्राचार्य, पत्राचार अध्ययन विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय यह अध्ययन कर रहे हैं।

विस्तृत अध्ययन के लिए सभी 33 दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों में से यादृच्छिक रूप से 9 संस्थानों को प्रतिदर्श के लिए चुना गया हैं। संस्थानों के चयन में दाखिले को मुढय आधार बनाया गया।

परियोजना के उपकरणों को अंतिम रूप दे दिया गया है और आंकड़ा संग्रह कार्य भी पूरा हो गया है। अब सारणीकरण, विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन कार्य चल रहे हैं।

1989-90

3.2.20 भारत के वर्तमान पत्राचार संस्थानों में शिक्षण और अधिगम की प्रणालियों का एक गहन मूल्यांकन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए जुलाई, 1989 में रु० 72,300 स्वीकृत किया गया है। यह अध्ययन डॉ० एच.सी.एस. राठौर, प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कर रहे हैं। इस अध्ययन के उद्देश्य हैं–(अ) निम्न के संदर्भ में शिक्षण और अधिगम के प्रबंध के लिए अपनाई गई वर्तमान विधियों का अध्ययन करना : (1) अधिगम सामग्रियों का विकास, (2) अधिगम सामग्रियों का वितरण, (3) परीक्षाएं और छात्र मूल्यांकन; (ब) प्रत्येक उद्देश्य के अंतर्गत अध्ययन के पक्षों का गहन मूल्यांकन।

क्षेत्रीय कार्य पूरा हो गया है और अध्ययन के उपकरण भी तैयार कर लिए गए हैं। लगभग 30% आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं और बाकी 70% आंकड़े गरमी की छुट्टी के बाद अगस्त 1990 तक एकत्र कर लिए जाएंगे।

3.2.21 तमिलनाडु में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबंध (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए अगस्त 1989 में रु. 63,000/- स्वीकृत किया गया है। यह अध्ययन डॉ० सी. सुब्रमण्य पिलई, प्रोफेसर और अध्ययक्ष, शिक्षा विभाग, कामराज विशविद्यालय, मदुरई कर रहे हैं।

इस अध्ययन के उद्देश्य हैं–तमिलनाडु में शिक्षा के स्तर पर हार्डवेअर और साफ्टवेअर, जैसे–रेडियो, टी.वी. और वीडियो प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में हो रही प्रगति की समीक्षा करना, यह पता लगाना कि इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग कहां तक संभव हैं और संकाय के सदस्य इनका किस हद तक उपयोग करते हैं और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रबंध की कमियां प्रकाश में लाना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन के प्रभावशाली प्रबंध के लिए समुचित सुझाव देना।

इस अध्ययन से संबंधित पुस्तकालय कार्य और सूचना संग्रह कार्य पूरे कर लिए गए हैं। प्रश्नावलियां तैयार कर ली गई हैं और चुने हुए संस्थानों में उनका वितरण कार्य जारी है।

3.2.22 दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के कार्यों की और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से औपचारिक विश्वविद्यालयी ढांचे के अंतर्गत इसके संगठनात्मक और संकाय की संचरना में समुचित और पर्याप्त परिवर्तन के लिए दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के संगठनात्मक और अकादमिक संरचना का एक अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए अगस्त, 1989 में रु०63,600 की राशि स्वीकृत की गई है। यह अध्ययन डॉ० किशोर बालिचा, निदेशक दूरवर्ती शिक्षा, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई कर रहे हैं।

पहला सवाल यह है कि इस अध्ययन में उस प्रश्न के जबाव को ढूंढ़ने का प्रयास किया जाएगा कि क्या निम्न शैक्षिक कार्यक्रमों के तहत सांगठनिक ढांचा विकसित किया जा सकता है: (1) औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी विभिन्नता (2) सामान्य अनौपचारिक शिक्षा, (3) विशेष अनौपचारिक शिक्षा, (4) कार्य अनुभव और (5) शैक्षिक प्रौद्योगिकी।

कालीकट, केरल, अन्नामलाई, मद्रास, श्रीवेंकेटेश्वर तिरुपति, ओस्मानिया, उत्कल, भुवनेश्वर और मदुराई कामराज विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर ली गई हैं। आंकड़ा संग्रह और विश्लेषण कार्य जारी है।

3.3 स्वीकृत किया गया अध्ययन

3.3.1 भारत में कृषि स्नातकों के रोजगार के अवसर : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर का एक लाभ लागत अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के लिए रु० 61,200 स्वीकृत किया गया है। यह अध्ययन डॉ० बी.सी. मेहता, प्रोफेसर अर्थशास्त्र, सुखाड़िया

विश्वविद्यालय, उदयपुर करेंगे। (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं–राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि स्नातकों के रोजगार के अवसर का विस्तृत मात्रात्मक विश्लेषण करना ताकि कृषि शिक्षा नीति के सुधार के संबंध में सुझाव दिया जा सके, कृषि शिक्षा की मांग और आपूर्ति पक्षों का अध्ययन करना, कृषि शिक्षा की लागत प्रभाविता का अध्ययन करना, कृषि शिक्षा के वित्तीय और उत्पादन के पक्षों का अध्ययन करना, कृषि स्नातकों के उर्ध्व और क्षैतिज गतिकी का अध्ययन करना, चालू सत्र के कृषि स्नातकों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करा ताकि प्रवेश नीति और भारत में आर्थिक विकास के सामाजिक लक्ष्यों की उपलब्धि के निहितार्थों का मूल्यांकन किया जा सके और यह पता लगाना कि क्या कृषि शिक्षा के पुनर्निर्वेशन से सामाजिक उत्पादन में वृद्धि लायी जा सकती है।

3.3.2 भारत में शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएं: आधारभूत स्तर पर सामजिक परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक विषमताओं का पुनरीक्षण

इस अध्ययन के लिए रु. 3,48,840 स्वीकृत किया गया है। यह अध्ययन डा. एस.सी. नूना अध्येता, प्रादेशिक प्रणाली एकक ने अपने हाथ में लिया है।

अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं : विद्यालय स्तर पर शैक्षिक विकास में विषमताओं का विश्लेषण करना और विषमताएं दूर कर करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में दिशा निर्देश देने की दृष्टि से एक व्याख्यात्मक प्रणाली का विकास करना, शिक्षा और अन्य विकास के बीच के अंतर-संबंधों का विश्लेषण करना और आधारभूत स्तरों पर सम्बन्धित योजना के ढांचे का विकास करने के लिए विकास की वर्तमान प्रणाली का मूल्यांकन करना।

3.3.3 भारत में संसाधनों का प्रभावी उपयोग : एक केस अध्ययन

डॉ. जे.बी.जी. तिलक, परियोजना निदेशक के विदेश सेवा पर चले जाने के बाद इस अध्ययन को निलंबित कर दिया गया था। उनके वापस आने पर इसे पुनः शुरू किया गया है। अब इसके लिए संशोधित लागत रु० 1,81,100 स्वीकृत किया गया है।

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं : एक तरफ शिक्षा की सांस्थानिक लागत और दूसरी तरफ संस्थान के निर्गत के आधार पर शिक्षा की लागत प्रभाविता का एक विष्लेषण करना, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विद्यालयों में शिक्षा के संसाधनों के निर्धारण और उनके उपयोग के मानदंड का विश्लेषण करना और निर्धारण/उपयोग के विभिन्न प्रतिमानों को स्पष्ट करने वाले कारकों की परीक्षा करना।

यह अध्ययन प्राथमिक प्रतिदर्श आंकड़े पर आधारित है और इसके लिए जिलों से आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016
DOC, No D-9370
......5-12-96......

1989-90

अध्याय 4

परामर्शकारी और अन्य सेवाएं

शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में भारत सरकार, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्शकारी, सलाहकारी और समर्थन सेवाएं प्रदान करना संस्थान के प्रमुख कार्यों में से एक है। इससे संबंधित इस वर्ष की कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्न हैं :

4.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन

4.1.1 कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चुने हुए पक्षों पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 30 कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम थे–त्रिपुरा के शिक्षा अधिकारियों के लिए नीति के कार्यान्वयन पर एक कार्यक्रम; अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और मध्यप्रदेश में व्यष्टि स्तरीय योजना और विद्यालय मानचित्रण पर एक-एक कार्यक्रम; सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन पर दो कार्यक्रम प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा पर चार कार्यक्रम; राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर 3 कार्यक्रम; जि. शि. प्र. सं. के प्राचार्यों और कार्मिकों के लिए चार कार्यक्रम; नवोदय विद्यालय समिति के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए दो कार्यक्रम; वंचित वर्गों के लिए 5 कार्यक्रम; अकादमिक स्टाफ कालेजों और स्वायत्त कालेजों के लिए एक-एक कार्यक्रम और प्रयोगशाला क्षेत्र अभिगम पर एक कार्यक्रमः (विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अनुबंध -II की कार्यक्रम सूची में क्रम सं. 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20 देखें)

4.12 अनुसंधान अध्ययन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित निम्नांकित अध्ययन शुरू किए गए :

(1) सन् 2000 ई० में शिक्षाः एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य
(2) भारत में साक्षरताः एक देश कालिक विश्लेषण (1901-1981)
(3) गुड़गांवा जिले (हरियाणा) के पुनहाना प्रखंड में शैक्षिक योजना और प्रशासन की कार्यान्वयन रणनीतियों का क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन
(4) कालेजों के प्रभावी प्रकार्य और विकासः एक क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन
(5) जनजातीय और उप-योजना क्षेत्र के शैक्षिक विकास का एक अध्ययन
(6) विद्यालय मानचित्रण पर परियोजना
(7) द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण
(8) भारत में अनु.ज. और गैर अ.ज. की आबादी के बीच की विषमताओं का जिलेवार विश्लेषण
(9) शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता का प्रबंध : स्वायत्त कालेजों का एक अध्ययन
(10) प्रारंभिक शिक्षा का संगणकीकृत योजना (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
(11) जिला शिषा अधिकारियों के लिए संचारेक्षण सूचना प्रणाली (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
(12) उच्च शिक्षा में विद्यमान सुविधाओं/संसाधनों के और अधिक प्रभावी उपयोग का एक अध्ययन (योजना आयोग द्वारा प्रायोजित)
(13) भारत के शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएंः आधारभूत स्तर समाज में शैक्षिक विषमताओं का पुनरीक्षण

1989-90

4.13 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् की समितियां (केब)

संस्थान ने निम्नांकित केब समितियों को अपनी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की हैं :

(1) शिक्षकों के स्थानांतरण पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित केब समिति में नीपा के निदेशक सदस्य-सचिव
(2) महिला शिक्षकों की आवासीय सुविधाओं पर राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में गठित केब समिति
(3) शिक्षा के प्रबंध पर मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति में नीपा के निदेशक सदस्य-सचिव

4.2 विशेष आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम

राज्यों/के.श.प्र. और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के निवेदन/सहयोग से विशेष जरूरतों के मुताबिक 23 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर और संगोष्ठी आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम थे– नवोदय विद्यालय समिति के लिए दो कार्यक्रम, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए एक कार्यक्रम, जि.शि.प्र.सं. के लिए चार कार्यक्रम, रेलवे बोर्ड के विद्यालयों के लिए एक कार्यक्रम, क्वीन मेरी कालेज मद्रास में स्वायत्त कालेजों के संकायों के लिए एक कार्यक्रम, अकादमिक स्टाफ कालेजों के लिए दो कार्यक्रम और वि.अ.आ. के अनुरोध पर स्वायत्त कालेजों के लिए एक कार्यक्रम, कार्मिक विभाग के अनुरोध पर भा.प्र.से. के अधिकारियों के लिए एक कार्यक्रम, अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और त्रिपुरा के सरकारों के अनुरोध पर एक-एक कार्यक्रम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सहयोग से मुस्लिम प्रबंध के संस्थानों के प्राचार्यों और प्रबंधकों के लिए एक संगोष्ठी, साउथ गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर एक कार्यक्रम, शिक्षा विभाग के अनुरोध और सहयोग से आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सामग्रियों और उपकरणों के उत्पादन और वितरण पर एक कार्यशिविर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध और सहयोग से 'विकास के चार दशक' विषय पर एक संगोष्ठी और एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस के सहयोग से उच्च शिक्षा के संस्थानों में वैज्ञानिक योजना और प्रबंध पर एक संगोष्ठी।

(विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संलग्न अनुबंध II में क्रम सं. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 3.4, 3.6, 3.8, 3.14, 3.15, 3.18 और 3.26 देखें।)

4.3 आठवीं योजना कार्यदल

संस्थान ने आठवीं योजना के निम्नांकित कार्यदलों को वृत्तिक सेवाएं प्रदान की :

(1) सांख्यिकी, संचारेक्षण और मूल्यांकन, पर कार्यदल,
(2) पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा पर गठित कार्यदल की स्थानीय योजना और प्रबंध पर उप-कार्य दल,
(3) शिशु और प्रारंभिक शिक्षा पर उप-कार्यदल।

4.4 वार्षिक योजना पर परिचर्चा

योजना आयोग में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न राज्यों और के.श.प्र. के शिक्षा पर गठित कार्यदलों में संस्थान के प्रतिनिधि शामिल थे।

4.5 अरुणाचल प्रदेश में शैक्षिक विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना

अरुणाचल प्रदेश में 20 वर्ष की शैक्षिक विकास योजना के निर्माण में संस्थान ने एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को परामर्शकारी सेवाएं प्रदान की।

4.6 अध्ययन/परियोजना

संस्थान ने निम्नांकित सहयोगी/प्रायोजित अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाएं शुरू किए:

4.6.1 सहयोगी/प्रायोजित अध्ययन परियोजना

(1) संसाधन निर्धारण प्रणाली : उच्च शिक्षा में चुने गए क्षेत्र (आई.आई.ई.पी-वि.अ.आ.-नीपा) (सहयोगी अध्ययन)
(2) बेसिक शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता (नीपा-आई.आई.इ.पी.) (सहयोगी अध्ययन)
(3) महिला कालेजों के प्रशासकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान (नीपा-एस.एन.डी.टी. विश्विद्यालय) (सहयोगी अध्ययन)
(4) प्रारंभिक शिक्षा का संगणकीकृत योजना (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
(5) जि. शि. अ. के लिए संचारेक्षण सूचना प्रणाली (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
(6) उच्च शिक्षा में विद्यमान सुविधाओं/संसाधनों के और अधिक प्रभावी उपयोग का एक अध्ययन (योजना आयोग द्वारा प्रायोजित)

4.6.2 राज्यों के अनुरोध पर अध्ययन/परियोजना

आंध्रप्रदेश सरकार के अनुरोध पर संस्थान ने आंध्रप्रदेश में शिक्षा और विकास पर एक मोनोग्राफ तैयार किया गया। महाराष्ट्र सरकार के निवेदन पर संस्था ने महाराष्ट्र में शिक्षा और विकास पर एक मोनोग्राफ तैयार करने का कार्य अपने हाथ में लिया है।

4.7 विशेष मसलों पर व्यावसायिक सहयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के लिए विद्यालयों पर्यावरण शिक्षा पर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के संचारेक्षण और मूल्यांकन के लिए संस्थान ने एक योजना का निर्माण किया। संस्थान के संकाय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को वैज्ञानिकों की भर्ती की प्रणाली के पुर्नगठन में व्यावसायिक सेवा प्रदान की। रा.शै.अ.प्र.प., नागालैंड को भी राष्ट्रीय शिक्षानीति और कार्यवाही योजना के क्रियान्वयन पर पाठ्यचर्या तैयार करने में संस्थान की सेवाएं प्रदान की गईं।

4.8 परामर्शकारी सेवा

यूनेस्को की विदेश नियुक्ति के अंतर्गत डॉ. ब्रह्मप्रकाश, वरिष्ठ अध्येता और अध्ययक्ष, शैक्षिक योजना एकक, नीपा ने श्रीलंका को परामर्श कारी सेवाएं प्रदान की।

4.9. विशेष क्षेत्रों में संस्थान का अकादमिक योगदान

व्यावसायिक निकायों सहित शैक्षिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों के प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यों में संस्थान के संकायों ने अकादमिक और अधिकारिक समितियों की सदस्यता अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में प्रकाशित लेखों, अनुसंधान पत्रों आदि के माध्यम से अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान किए।

राज्य और केंद्रीय सरकारों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, देश के विभिन्न भागों के विद्यालयों, विभिन्न विद्यालय शिक्षा परिषदों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद., राज्य लोक प्रशासन संस्थानों, शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थानों, रा.शै.अ.प्र.प., वि.आ.आ., के.वि.स., न.वि.स., भा.वि.सं., आ.त.शि.स., वि.औ.अ.प., योजना आयोग अकादमिक स्टाफ कालेजों और राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में संस्थान ने अकादमिक सेवाएं प्रदान किए।

संस्थान के संकायों के ऐसे अकादमिक योगदान का संक्षिप्त विवरण अनुबंध IVमें दिया गया है।

1989-90

अध्याय 5

अन्य अकादमिक गतिविधियां

शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शकारी और सलाहकारी सेवाएं संस्थान की प्रमुख गतिविधियां हैं। इसके अलावा संस्थान की दूसरी महत्त्वपूर्ण अकादमिक गतिविधियां निम्न हैं:

(अ) शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारों का प्रसार,
(ब) शिक्षा नीति के आधारभूत मसलों और लक्ष्यों पर विचार-विमर्श की पहल,
(स) शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का निर्माण,
(द) अतिथियों और शिष्टमंडलों का आतिथ्य।

इस वर्ष के दौरान किए गए ऐसे अकादमिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है :

5.1 नवाचारों का प्रचार

शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में गहन नवाचारी प्रयोग और शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के बीच अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे आयोजित करता है। इससे शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफल प्रयोगों और नवाचारों के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों से नवाचारी अनुभवों का गहन अध्ययन में उपयोग किया जाता है। दौरों के दौरान परस्पर विचार-विमर्श के बाद शिक्षा संबंधी नीतियों को परखने की नई दृष्टि मिलती है। इससे अन्य दूसरे राज्यों में सफल प्रयोगों और नवाचारों का समान रूप से प्रचार-प्रसार होता है।

5.2 नीपा विचार मंच

नीपा विचार मंच संस्थान का एक व्यावसायिक मंच है। इसमें शिक्षा और विकास के महत्वपूर्ण मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है। इससे संकाय को शैक्षिक नीति के मसलों और लक्ष्यों के बारे में अपनी संकल्पनाओं को तीव्र करने, सैद्धांतिक आधार को मजबूत बनाने और अपने विचार स्पष्ट करने में मदद मिलती है। संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और विषय में रुचि लेने वाले अन्य व्यक्तियों को विचार मंच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।

इस वर्ष विभिन्न विषयों पर निम्नांकित विचार मंच आयोजित किए गए :

दिनांक	विषय	वक्ता
21 जुलाई, 1989	उच्च शिक्षा के प्रबंध की कुछ प्रवृत्तियां : एक अंतराष्ट्रीय संप्रेक्ष्य	डा.एन.वी. वर्गीस अध्येता, नीपा
22 अगस्त, 1989	अगले दशक के लिए भारतीय विकास	डॉ.वी.जी. भाटिया, सलाहकार,नीति, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, योजना आयोग

1989-90

दिनांक	विषय	वक्ता
		डॉ. एस.आर. हुसैन, निदेशक, संप्रेक्ष्य योजना विभाग, योजना आयोग, प्रो. डी.बी. गुप्ता, विजिटिंग प्रोफेसर, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान
2 नवंबर 1989	एशिया में शैक्षिक विकास : लागत और वित्तीय मसलों पर केंद्रित एक तुलनात्मक अध्ययन	सुश्री जी. पांगतान, वरिष्ठ शिक्षा अर्थशास्त्री, विश्व बैंक, एशिया क्षेत्र
14 मार्च,1990	सन् 2000 तक सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मलेन	डॉ० गैब्रियल कैरन, वरिष्ठ संकाय सदस्य, आई.आई.ई.पी. पेरिस
15 मार्च,1990	मैक्सिको में उच्च शिक्षा : उपनिवेदशी और इतर उपनिवेशी प्रवृत्तियां	प्रो० (सुश्री) इवा एलगज़ेंडर उचमनी, नेशनल आटोनोमस यूनिवर्सिटी मेक्सिको

5.3 शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों का राष्ट्रीय रजिस्टर

संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रबंध, शिक्षा नीति और योजना, शैक्षिक वित्त, विद्यालय शिक्षा का प्रबंध, उच्च शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, ग्राम विकास, महिला शिक्षा, अनु.ज. और अनु.ज.जा. की शिक्षा तथा शिक्षा का अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों के एक रजिस्टर के निर्माण का कार्य एक अभ्यास के रूप में शुरु किया है। विशेषज्ञ समिति की सलाह पर राष्ट्रीय रजिस्टर के निर्माण के लिए सूचनाएं एकत्र करने के उद्देश्य से एक प्रपत्र विकसित किया गया। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों, यूनिवर्सिटी न्यूज, नीपा द्वारा प्रकाशित शैक्षिक योजना और प्रशासन जर्नल तथा अन्य व्यावसायिक जर्नलों में इसकी अधिसूचना जारी की गयी। राष्ट्रीय रजिस्टर के निर्माण के मानदंड भी अंतिम रूप से तैयार कर लिए गए हैं।

अधिसूचना जारी होने पर इसके प्रपत्र के लिए 1000 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए। सभी उपकुलपतियों, शिक्षा सचिवों, राज्यों के डी.पी.आई., एन.सी.ई.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी., यू.जी.सी., आई.सी.एस.एस.आर., आई.आई.पी.ए., शिक्षा विभाग के ब्यूरो प्रमुखों इत्यादि को खाली प्रपत्र भेजे गए। उन 450 संसाधन व्यक्तियों को भी खाली प्रपत्र भेजे गए जिन्हें पहले शैक्षिक योजना और प्रबंध की विशेषज्ञ सूची में रखा गया था। अधिक संख्या में भरे हुए प्रपत्र प्राप्त हो रहे हैं और उन्हें संगणक में संग्रहित किया जा रहा है।

5.4 प्रतिनिधि और अतिथि

संस्थान में देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधि आए। संस्थान में आने वाले अतिथियों में उच्च पदाधिकारी जैसे–मंत्री, उपकुलपति और अन्य ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्, शैक्षिक प्रशासक और योजनाकार थे।

1989-90

अध्याय 6

प्रकाशन, पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

संस्थान के प्रकाशन, पुस्तकालय और प्रलेखन सेवा विभाग, विकास और बहुमुखी कार्यक्रम अनुसंधान और अन्य अकादमिक गतिविधियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारी अनुभवों तथा नए विषय क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के प्रसार में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

संस्थान की कुछ प्रमुख गतिविधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

6.1 प्रकाशन

6.1.1 प्रकाशित

6.1.1.1 विद्यालय मानचित्रण : मार्गदर्शिका (हिंदी रूपांतर)

योजनाकारों और प्रशासकों के विधिवत अभ्यास के लिए विद्यालय मानचित्रण की मार्गदर्शिका तैयार कर ली गई है। मार्गदर्शिका तैयार करते समय संस्थान ने एक ओर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान के यूनेस्को (पेरिस) अध्ययनों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को लिया है तो दूसरी ओर देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय अनुभव को लिया है।

इस प्रलेख को चार अध्यायों में बाटा गया है :

अध्याय-I विद्यालय मानचित्रण : संकलपना और प्रणाली; अध्याय-II : शैक्षिक सुवधाओं के प्रावधान का मानदंड; अध्याय III : योजना प्रस्तावों के विकास के लिए सर्वेक्षण सुविधा तथा मार्गदर्शिका और अध्याय IV : संगठनात्मक आवश्यकता तथा क्रियान्वयन रणनीतियां।

6.1.1.2 शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रिपोर्ट (यूनेस्को-यू.एन.ई.पी. पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अंर्तगत)

1975 में यूनेस्को-यू.एन.ई.पी. में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (अं.प.शि.का.) से संबंधित अपनी गतिविधियां शुरू की थीं। यूनेस्को- यू.एनं.ई.पी. के अंर्तराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की गतिविधियों के संदर्भ में 13-18 फरवरी 1989 में संस्थान ने शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर एक सप्ताह का अंतरक्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया।

यह प्रकाशन छः अनुभागों में बांटा गया है : अनुभाग I : प्रस्तावना; अनुभाग II : पाठ्यक्रम की मुख्य गतिविधियां; अनुभाग III : यूनेस्को-यू.एन.ई.पी. अंर्तराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम; अनुभाग IVदेश की रिपोर्ट का समेकित सारांश; अनुभाग V : पर्यावरण शिक्षा और शैक्षिक योजना अनुभाग VI : निष्कर्ष।

6.1.1.3 अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध पर परियोजना अधिकारियों के लिए एक (मैनुअल) संदर्शिका (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, उड़िया, असमिया, बंगाली और तेलुगू-रूपांतर)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अनौपचारिक शिक्षा के निम्नांकित विस्तृत और विधिवत् कार्यक्रमों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है : ऐसे इलाके जहां पर विद्यालय नहीं है, और विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे, कार्यरत लड़के-लड़कियां जिन्हें औपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

1989-90

नीपा और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अपनी प्रशिक्षण रणनीति तय कर ली है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, अनुशिक्षक, अनुदेशक, पर्यवेक्षक अधिकारियों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते थे जबकि नीपा अनौपचारिक शिक्षा के जिला स्तरीय कार्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती थी। कार्यक्रम के सहयोगात्मक आगत के रूप में परियोजना अधिकारियों के लिए नीपा ने यह संदर्शिका तैयार की है जिसमें क्षेत्र स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध पर ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा परियोजना अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में इस संदर्शिका का विस्तृत प्रयोग किया गया।

6.1.14 सन् 2000 में सभी के लिए शिक्षा-भारतीय परिप्रेक्ष्य

'सन् 2000 पर सभी के लिए शिक्षा' एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन है। यह अध्ययन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, भारतीय परिस्थिति में बेसिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों तथा सम्भावित दिशाओं पर किया गया है। यह अध्ययन बेसिक शिक्षा की आवश्यकताओं का समीक्षात्मक रूप प्रस्तुत करते हुए इसे देश की एक मूलभूत आवश्यकता मानता है। यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर किया गया अध्ययन है तथा इसमें दबे हुए तबके जैसे-महिला, अनु. जा. और अनु. जन.जाति की विशेष आवश्यकताओं पर भी धयान दिया गया है।

मार्च 1990 के दौरान बैंकाक में '' सन् 2000 तक सभी के लिए शिक्षा'' नामक विषय पर हुए विश्व सम्मेलन के संदर्भ में निकाले गये प्रकाशन को 13 अध्यायों में बांटा गया है: (i) परिवेश (ii) सभी के लिए शिक्षा: प्रतिष्ठा पुनरीक्षण (iii) लक्ष्य (iv) अभिगम और समता; (v) महिला; (vi) शिशु देख-भाल और शिक्षा (vii) अनौपचारिक शिक्षा ;(viii)प्रौढ़ शिक्षा (ix) शिक्षा प्रक्रिया और संदर्भ; (x) मूल्यांकन; (xi)अध्यापक शिक्षा; (xii)प्रबंध में परिवर्तन और (xiii)शिक्षा के लिए संसाधन

6.12 प्रेस में

(i) स्कूलिंग एंड रूरल ट्रांसफार्मेशन-मूनिस रज और एच. रामचंद्रन (समूल्य)
(ii) ओरगनाइसेशनल हिस्ट्री आफ मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन–ए. मैथ्यू
(iii) स्कूल एजुकेशन इन इंडिया : दी रीजियनल डाइमेंसन–मूनिस रजा, ए. अहमद और एस. सी. नूना
(iv) एट्लस आन वुमन एंड डेवलपमेंट– एस.सी. नूना

6.13 शैक्षिक योजना और प्रशासन जर्नल

निम्नांकित विषयों पर जर्नल के विशेषांक निकाले गए:

(i) दूरवर्ती शिक्षा (एम. मुखोपाध्याय द्वारा संपादित)
(ii) शैक्षिक योजना (हिंदी रूपांतर-ब्रह्मप्रकाश द्वारा संपादित)

प्रेस में

(i) दूरवर्ती शिक्षा (हिन्दी रूपान्तर-मुखोपाध्याय द्वारा संपादित)
(ii) तीसरी दुनिया में शिक्षा की योजना और प्रबंध (के.जी. विरमानी और एस.सी. नूना)द्वारा सम्पादित

6.14 मिमियोग्राफ प्रकाशन

संस्थान ने अनुसंधान अध्ययन, अनियत पत्र और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्ट का मिमियोग्राफ प्रकाशन निकाला है।

6.15 अनयित पत्र

वर्ष के दौरान निकाले गए अनियत पत्रों में निम्नांकित शामिल हैं :

1989-90

6.15.1 विलगाव वाले क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण: अरुणाचल प्रदेश पर एक केस अध्ययन अनियत पत्र सं. 17 नीपा -के. सुजाता

यह अनियत पत्र देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश के जैसे विलगाव वाले पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के विकास पर विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। इस अनियत पत्र में भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर भी ध्यान दिया गया है। इस अनियत पत्र में राज्य की शैक्षिक सुविधाएं, नामांकन, अध्यापक छात्र अनुपात तथा विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों की पद्धति पर भी चर्चा की गई है।

प्रथम भाग में अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक सांकृतिक जीवन को लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है। इसमें शिक्षा के विकास के लिए सरकारी प्रयास तथा प्रदेश के प्रशासन में होने वाले कार्य परिवर्तनों पर भी ध्यान दिया गया है। इसका दूसरा भाग शैक्षिक सुविधाओं के विकास, अभिगम तथा अंतर-जिला असमानताओं पर एक ब्यौरा प्रस्तुत करता है। इस भाग में अध्यापक छात्र अनुपात की भी चर्चा की गई है। अनुभाग III में एक निश्चित अवधि तक हुए नामांकन तथा विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों की पद्धति पर भी चर्चा की गई है। चौथे भाग में प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से संसाधन विनिदान और व्यय सें संबंधित विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। अंतिम भाग में अत्यंत दूरी पर स्थित विलगाववादी क्षेत्रों में शैक्षिक विकास के क्षेत्र में आने वाली अड़चनों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई है तथा उसके वैकल्पिक उपाय भी सुझाए गए हैं।

6.15.2 आश्रम विद्यालयों में शिक्षा- आंध्रप्रदेश पर एक केस अध्ययन अनियत पत्र सं. 18 नीपा- के सुजाता

पिछड़े तथा छिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से आश्रम विद्यालयों को एक प्रभावी संस्थान माना गया है। ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय खोला जाना संभव नहीं है। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए वहां के नामांकित छात्रों को पूर्ण अवसर प्रदान करने और एक अच्छा वातावरण बनाने के उद्देश्य से ही आश्रम विद्यालयों की स्थापना की गई है आश्रम विद्यालय आवासीय विद्यालय है और यहां के छात्रों को मुफ्त में खाना, पीना, आवास तथा अन्य सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जाता है। आश्रम विद्यालयों के प्रमुख कार्यों में सामान्य शिक्षा के अलावा शिल्प तथा अन्य कार्यों में प्रशिक्षित करना शामिल है। देश के अधिकतर आश्रम विद्यालय निम्न छः राज्यों में स्थित हैं : आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान। देश का सबसे बड़ा आश्रम विद्यालय आंध्रप्रदेश, में स्थित है (437)। इनमें छात्र नामांकन की संख्या 41,768 है। जिस उद्देश्य से आश्रम विद्यालयों की स्थापना की गई उस दृष्टि से आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में आश्रम विद्यालयों की वर्तमान सुविधा नामांकन, विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का दर और आश्रम विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर विशेष रूप से इस पत्र के अंत्रगत विचार किया गया है। आश्रम विद्यालयों के उद्देश्यों और संकल्पनाओं का एक संक्षिप्त परिचय इस पत्र सें दिया गया है। इसके उपरांत आंध्रप्रदेश के आश्रम विद्यालयों पर भी एक संक्षिप्त भाग है। चौथे अनुभाग में संरचना सुविधा, नामांकन, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्र, अध्यापक छात्र अनुपात, तथा विशेष रूप से अदिलाबाद जिले के आश्रम विद्यालयों में स्टाफ पैटर्न पर चर्चा की गई है। पांचवें अनुभाग में आश्रम विद्यालयों की अकादमिक तथा अन्य गतिविधियों पर चर्चा की गई है। अंतिम अनुभाग में निष्कर्ष दिया गया है।

6.2 पुस्तकालय

संस्थान में शैक्षिक योजना, प्रशासन और अंतरशास्त्रीय विषयों पर एक सुसंगठित पुस्तकालय है। कई साल से यह विद्वानों, छात्रों तथा प्रशिक्षुओं को बिना किसी अड़चन के पुस्तकालय तथा प्रलेखन सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। इस पुस्तकालय में अच्छी सुविधाओं के साथ पढ़ने लायक वातावरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

1989-90

6.2.1 पुस्तकें

पुनरीक्षण अवधि के दौरान 1000 प्रलेख पुस्तकालय में संग्रहित किए गए तथा 181 पुस्तकें मंगाई गईं। पुस्तकालय में अब 43,666 पुस्तकें हैं और इसके अलावा अंर्तराष्ट्रीय अभिकरण जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, ओ.ई.सी.डी., आई.एल.ओ, यू.एन.आई.सी.ई.एफ.आदि द्वारा आयोजित अंर्तराष्ट्रीय संगोष्ठी/ सम्मेलन की रिपोर्ट भी हैं।

6.2.2 जर्नल

शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंध और अन्य क्षेत्रों से पुस्तकालय में 325 पत्रिकाएं आती हैं। इन जर्नलों में प्रकाशित होने वाली सभी प्रमुख लेखों की सूची बना दी जाती है। वर्ष के दौरान 2301 लेखों की सूची इन जर्नलों से निकाल कर बना दी गई।

6.2.3 अमुद्रित सामग्री

वर्ष 1986 में पुस्तकालय का आधुनीकीकरण करने का निर्णय लिया गया और इसे बहु-माध्यमिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने का निश्चय किया गया। इस उद्देश्य से, दृश्य कैसेट, श्रव्य कैसेट चित्र, लघु चित्र और माइक्रोफिस प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान स्टॉक में छः फिल्म; 33 दृश्य कैसेट; 80 श्रव्य कैसेट, 54 लघु चित्र तथा 48 माइक्रोफिस हैं।

6.2.4 पुस्तकों का वितरण

पुनरीक्षण अविध के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, संकाय तथा अंतर पुस्तकालय व्यवस्था के रूप में अन्य संस्थानों को पुस्तकें वितरित की गई।

शोधकर्ताओं ने पुस्तकालय के 70,109 प्रलेखों का उपयोग किया।

6.2.5 समाचार (क्लीपिंग) कटिंग

पुस्तक तथा जर्नल के अतिरिक्त पुस्तकालय में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में विशेष रूप सें समाचार (क्लीपिंग) कटिंग भी रखे गए हैं। पुस्तकालय में अब 150 विषयों से सम्विन्धित फाइलहैं।

6.2.6 सामान्य ज्ञान संबंधी सेवाएं

6.2.6.1 शिक्षा से संबन्धित पत्रिकाएं : प्राप्त शीर्षक तथा विषय सूची

इसका मुख्य ध्येय पखवाड़े के दौरान प्राप्त शिक्षा जर्नल की विषय वस्तु के संवंध में पाठकों को जानकारी देना है। पुस्तकालय ने अपना पाक्षिक मिमियोग्राफ का प्रकाशन ''पीरियोडिलक्स ऑन एजूकेशन'' ' टाइटिल्स रिसीवड एंड देअर कंटेंस' जारी रखा।

6.2.6.2 नीपा के पुस्तकालय में प्राप्तियां

मासिक पत्रिकाओं की संगणकीकृत सूची पुस्तकालय में उपलब्ध की गई ताकि पाठकों को अपनी रुचि के प्रलेख तथा नई पत्रिकाओं के संबंध में अवगत करा सकें।

6.2.7 चयनित सूचनाओं का प्रसार

विभिन्न माध्यगों से प्राप्त सूचनाओं को पुस्तकालय, अकादमिक एकक तथा अनुसंधान परियोजना दलों को भेजता है जहां उसका सही और आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है।

6.2.8 ग्रंथ सूची

इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की ग्रंथसूची पुस्तकालय ने तैयार कर ली है।

6.2.9 क्षेत्रीय सूचना की पुनः प्राप्ति

''एजुकेशन इन एशिया एण्ड पैसिफिक'', जर्नल में ''नोट्स

1989-90

ऑन एशिया डाक्यूमैंट्स शीर्षक के अंतर्गत पुस्तकालय ने एक संक्षिप्त विवरणिका प्रस्तुत की है। यह जर्नल यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक द्वारा निकाला गया है।

6.2.10 नीपा प्रलेखन सेवाएं

नीपा प्रलेखन सेवाएं शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और प्रबंध के क्षेत्र में विद्वानों तथा शिक्षाकर्मियों के लिए जानकारी प्रदान करने वाली सेवाओं का एक क्रम है। इस क्रम के अंतर्गत ग्रंथ सूची, पुस्तक पुनरीक्षण, अनुसंधान अध्ययन, राज्य रिपोर्ट आदि निकालने का विचार किया गया।

इस अवधि के दौरान निकाली गयी प्रथम प्रति स्टॉफ विकास की संक्षिप्त ग्रंथ सूची के लिए अर्पित की गई है। दूसरी प्रति शिक्षा पर है जो कि जे.पी. नायक के नाम से अर्पित की गई है। इसमें जे.पी. नायक द्वारा लिखी गई पुस्तकें तथा लेख हैं।

6.3 प्रलेखन केंद्र

संस्थान के कार्यक्रम विशेषकर राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी सूचना देने के उद्देश्य से केन्द्र प्रादेशिक प्रणाली एकक के सहयोग से कार्य करता है ताकि संस्थान सूचना और अनुभवों को प्रभावी रूप से देने का कार्य कर सके।

प्रादेशिक प्रणाली स्तर पर जिला प्राधिकरण और संस्था, तथा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित संदर्भ सामग्री केंद्र एकत्र करता है। केन्द्र का प्रमुख कार्य जिला स्तर पर सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उसका प्रसार करना है।

वर्ष के दौरान, केन्द्र ने 730 प्रलेख एकत्रित कर लिये। केन्द्र के पास अभी 9,496 प्रलेख हैं जिनमें निम्नांकित शामिल हैं: राज्य गजट, राज्य जनगणना, पुस्तिका, शैक्षिक सर्वेक्षण, राज्य शैक्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना, बजट, राज्य विश्वविद्यालय पुस्तिका, सामाजिक –आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास पर राज्य प्रलेख, मूल माध्यम पुस्तकें और ग्रंथ सूची, प्रैस क्लिपिंग, राज्य शैक्षिक संहिता, अधिनियम, नियम और विनियम, तकनीकी-आर्थिक और प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जिला गजट, जिला जनगणना हस्त पुस्तिका, वार्षिक योजना, शैक्षिक योजना, जिला क्रय योजना, लीड बैंक रिपोर्ट, जिला प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जिला शैक्षिक सर्वेक्षण, जिला सांख्यिकी आंकड़ों की हस्त पुस्तिका, ग्राम और प्रखंडस्तरीय योजना और अध्ययन अनुसंधान और परियोजना रिपोर्ट, अनुसंधान तालिका अध्ययन, तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण।

6.3.1 प्रलेखन और सूचना सेवाएं

शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नये तथा नवाचारी अनुभवों से संबंधित सूचनाओं का प्रसार प्रलेखन केन्द्र निम्नांकित माध्यमों से करती है:

(1) शोधकर्ताओं तथा संकाय सदस्यों के लिए चयनित सूचना प्रसार सेवा (च. सु. प्र. से.),
(2) प्रलेखन सूची, और
(3) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संक्षिप्त ग्रंथ सूची को संकलित करना।

1989-90

अध्याय 7

प्रशासन और वित्त

संस्थान का समस्त वित्तीय भार भारत सरकार वहन करती है। इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है।

संस्थान की नीति बनाने वाले निकाय हैं – नीपा परिषद, कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति और कार्यक्रम सलाहकार समिति।

निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। प्रशासन और वित्तीय मामलों में निदेशक की मदद के लिए कार्यकारी निदेशक होता है। अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यों में निदेशक की मदद के लिए संकायाध्यक्ष होता है।

कार्यालय का अध्यक्ष कुलसचिव होता है और वही अकादमिक, कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन का प्रभारी है।

7.1 नीति निर्माण के अंग

7.1.1 परिषद

संस्थान का शीर्ष निकाय परिषद् है। संस्थान के सभी कार्यों का सर्वेक्षण तथा उद्देश्य की प्राप्ति परिषद के प्रमुख कार्य है।

इसका सर्वोच्च अधिकारी अध्यक्ष होता है जिसको भारत सरकार मनोनीत करती है। नीपा का निदेशक इसका उपाध्यक्ष होता है। परिषद के सदस्य राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के शिक्षा प्रणाली के सर्वोच्च अधिकारी और विख्यात शिक्षाविद् होते है। अतः नीपा का गठन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; भारत सरकार के चार सचिव (शिक्षा, वित्त, कार्मिक और योजना आयोग); निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के छः शिक्षा सचिवों और छः शिक्षा निदेशकों; छः प्रसिद्ध शिक्षाविदों, कार्यकारी समिति के सभी सदस्य तथा नीपा संकाय के एक सदस्य से होती है। नीपा का कुलसचिव परिषद का सचिव होता है।

परिशिष्ट –Iमें 31 मार्च 1990 तक की परिषद के सभी सदस्यों की सूची दी गई है।

7.12 कार्यकारिणी समिति

संस्थान के प्रशासन तथा अन्य मामलों का प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति करती है।

संस्थान का निदेशक कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), वित्त और योजना आयोग के सचिवों द्वारा नामित व्यक्ति; राज्य के शिक्षा सचिव; एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् और नीपा के कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होते है। नीपा के कुलसचिव कार्यकारी समिति के सचिव हैं।

परशिष्ट-II में 31 मार्च 1990 तक की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची दी गई है।

7.13 वित्त समिति

वित्त समित लेखा तथा बजट निर्धारण की जांच करती है और नए व्यय तथा अन्य वित्त संबंधी मामलों के प्रस्तावों की

सिफारिश करती है। वित्त समिति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस संस्थान का निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें 5 सदस्य और होते हैं जिनमें वित्त सलाहकार और अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद् के सदस्य शामिल हैं। नीपा का कुलसचिव इस वित्त समिति का सचिव होता है।

परिशिष्ट-III में मार्च 31, 1990 की वित्त समिति के सदस्यों की सूची दी गई है।

7.1.4 कार्यक्रम सलाहकार समिति

कार्यक्रम सलाहकार समिति संस्थान के प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा अन्य कार्यक्रमों के साथ अकादमिक कार्यों की जांच करती है और उपयुक्त सुझाव देती है।

इस समिति में नीपा के निदेशक पदेन अध्ययक्ष होता है। इसके अन्य सदस्य है– मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि; योजना आयोग; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् और जनशिक्षा के निदेशक और राज्य शिक्षा सचिव, अकादमिक शिक्षाविद्; कार्यकारी निदेशक; डीन प्रशिक्षण और अनुसंधान, नीपा; नीपा संकाय के दो सदस्य तथा कार्यकारी समिति द्वारा नामित अन्य सदस्य। नीपा के कुल सचिव, कार्यक्रम सलाहकार समिति का सचिव होता है। परिशिष्ट–IV में कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों की 31 मार्च 1990 तक की सूची दी गई है।

7.2 संगठनात्मक ढांचा

7.2.1 अकादमिक एककें

संस्थान के संकाय को निम्नांकित 8 अकादमिक एककों में गठित किया गया है :

शैक्षिक योजना
शैक्षिक प्रशासन
शैक्षिक वित्त
शैक्षिक नीति
विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा
उच्च शिक्षा
प्रादेशिक प्रणाली
अंतर्राष्ट्रीय

नौंवा अकादमिक एकक अर्थात दूरवर्ती शिक्षा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी को मार्च 1990 में भंग कर दिया गया। अब इसका कार्य शैक्षिक प्रशासन एकक द्वारा किया जाता है। अकादमिक एकक का प्रमुख वरिष्ठ अध्येता होता है। यद्यपि शैक्षिक नीति एकक का प्रमुख अध्येता है।

संस्थान की नीति और अनुदान की उपलब्धता के अनुसार अकादमिक एककों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास तथा विभिन्न प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें तथा उन्हें परामर्शकारी तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करें।

7.2.2 कृतिक बल और समितियां

समय-समय पर विशेष कार्यक्रमों के लिए निदेशक विशिष्ट कार्य बल तथा समितियों का गठन करता है।

विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के विकास का संचारेक्षण और सलाह के लिए विशेषज्ञों की एक परियोजना सलाहकार समिति का गठन किया गया हैं।

अध्ययन के लिए सहायता योजना के अंतर्गत अनुसंधान अध्ययन सलाहकार परिषद् द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। इस सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष निदेशक होता है तथा इसके अन्य सदस्यों में अकादमिक एककों के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के रूप में कुलसचिव होते हैं।

7.2.3 अधिरचनात्मक समर्थन सेवा

संस्थान के बहु-मुखी कार्यक्रम, अनुसंधान तथा अन्य अकादमिक

1989-90

गतिविधियों के विकास में संस्थान के पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र, प्रकाशन एकक, संगणक केंद्र, हिंदी कक्ष तथा मानचित्रण कक्ष एक मज़बूत आधार प्रदान करते हैं।

अध्याय 6 में प्रकाशन, पुस्तकालय तथा प्रलेखन सेवाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

कंप्यूटर केंद्र में तीन डब्ल्यू.आई.पी.आर.ओ.पी.सी.-ए.टी,आई.बी.एम.पी.सी.ए.टी. स्थापित हैं। जिसमें आर.ए.एम. की एक-एक ए.एम.बी., हार्ड डिस्क के 40 एम.बी. और 1.2 एम.बी. की एकल फ्लोपी ड्राइव लगे हुए हैं। यह सभी डैटा प्रोसेसिंग के लिए हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए आरंभ में 10 पी.सी.एक्स.टी का प्रयोग किया जाता है जिसमें आर.ए.एम. के 640 के.एम. तथा हार्ड डिस्क के 20 एम.बी. तथा एकल फ्लोपी ड्राइव लगे हुए हैं। इस केंद्र में एक शक्तिशाली आंकड़ा विश्लेषण सॉफ्टवेयर एस.पी.एम.एस./पी.सी+ रूपांतर (वेर्शन) 3.0, डेस्क टॉप और एक शक्तिशाली पोस्ट स्क्रिप्ट लेसर प्रिंटर क्यू.एम.एस.पी.एस. 810 भी हैं।

अनुसंधान और प्रशिक्षण में मानचित्रण कक्ष मानचित्र सुविधाएं प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, ''भारत में शिक्षा- आलेख प्रस्तुतीकरण'' पर भाग-Iप्रकाशित किया गया।

हिंदी कक्ष की मुख्य गतिविधियों में निम्नांकित शामिल हैं : अकादगिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग तथा कार्यालय संबंधी कार्य।

7.2.4 प्रशासनिक ढांचा

प्रशासन और वित्त प्रभाग को चार अनुभाग तथा दो कक्षों में बांटा गया है। ये हैं- अकादमिक प्रशासन, लेखा, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन, प्रशिक्षण कक्ष तथा समन्वयन कक्ष। अकादमिक प्रशासन तथा समन्वयन कक्ष का संचालन कुलसचिव करता है जबकि कार्मिक, सामन्य प्रशासन अनुभाग और प्रशिक्षण कक्ष का पर्यवेक्षण प्रशासनिक अधिकारी करता है। किंतु इन सभी कार्यों के प्रभारी कुलसचिव होता है। लेखा अनुभाग का प्रभारी वित्त अधिकारी होता है।

7.3 संवर्ग योजना

31मार्च 1990 तक संस्थान के संवर्ग की संख्या 176 थी :

संवर्ग पद	संख्या
संकाय	35
(निदेशक, परामर्शदाता, वरिष्ठ अध्येता, अध्येता और सह-अध्येता)	(20%)
अकादमिक कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्ति	24
प्रकाशन अधिकारी, पुस्तकाध्यक्ष, प्रलेखन अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, हिन्ही संपादक, सहायक प्रकाशन अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी (ग्रेड) – II और (ग्रेड) III, हिन्दी अनुवादक और पुस्तकालय सहायक	(14%)

1989-90

नीपा का संगठनात्मक ढांचा

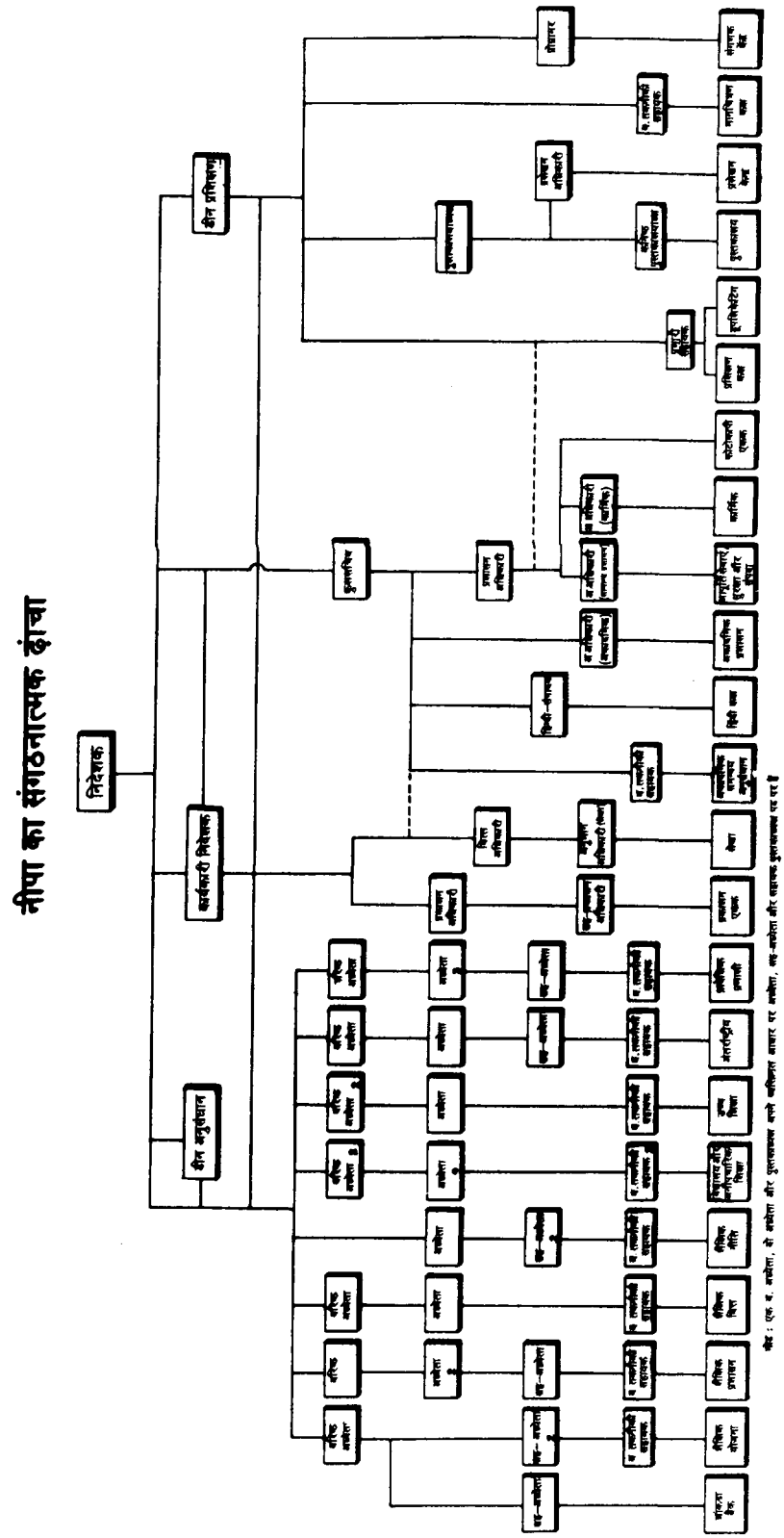

1989-90

संवर्ग पद	संख्या
प्रशासनिक और सचिव स्टाफ	39 (22%)
तकनीकी कर्मचारी (निदेशक के निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक, वरिष्ठ आशुलिपिक, मशीन परिचालक, वाहन चालक, संगणक, इलेक्ट्रिशियन, कार्यक्रम परिचर, पुस्तकालय परिचर और वरिष्ठ तथा कनिष्ठ गेस्टेटनर परिचालक)	33 19%
वर्ग – IV (गैर–तकनीकी)	45 (26%)
योग	176

इसके अतिरिक्त 31मार्च 1990 तक परियोजना में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 51 है।

7.4 विशेष लेखा पुनरीक्षण

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा मार्च–जून 1989 में संस्थान के कार्यो का पुनरीक्षण किया गया। यह पुनरीक्षण कार्य विशेषकर 1981–89 के बीच हुए अनुसंधान अध्ययनों तथा 1984–89 की अकादमिक गतिविधियों पर हुआ। नियंत्रक और महालेखा परिक्षक ने अपनी रिपोर्ट के प्रथम प्रारुप में वित्त और लेखा, विनियम, अकादमिक गतिविधियां, प्रकाशन, पुस्तकालय और प्रलेखन केन्द्र आदि पर अपने अभिमत दिए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पुनरीक्षण की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

7.5 विशेषज्ञ समीक्षा समिति की रिपोर्ट

श्री पी. के. उमाशंकर की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा स्थापित समीक्षा समिति ने सितम्बर 1989 में अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को प्रस्तुत की।

इस समिति ने नीपा की भावी भूमिका विशेषकर उसके प्रशासनिक ढ़ांचे और प्रशिक्षण शोध तथा प्रकाशन में सुधार लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए है।

पुनरीक्षण समिति के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

7.6 सेवा विनियम

शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित विनियम समिति ने अपनी रिपोर्ट के साथ सेवा विनियम का प्रारूप जून 1989 में प्रस्तुत की। सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर नीपा का सेवा विनिमय दिनांक 5- 1- 1990 से लागू किया गया।

सेवा विनिमय की मुख्य विशेषताओं में अंगीकरण धारा है जिससे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के समतुल्य वर्ग के कार्मिकों के लिए निर्धारित सेवाशर्तों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान के आधार पर संकाय के सदस्य तथा अन्य कर्मचारियों पर लागू कर सकें। संस्थान के कार्यों में सुधार लाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं।

1989-90

7.7 सामूहिक बचत बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बचत बीमा योजना के अंतर्गत वर्ग अ, ब, स, द के कर्मचारियों के बीमा रकम क्रमशः 80,000 रूपये, 40,000 रूपये और 10,000 रूपये है।

7.8 कार्य पद्धति

संस्थान ने कार्य की क्रियात्मक क्षमता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के उद्देश्य से नियमित कर्मचारियों की बजाए कार्य को शीघ्र निपटाने की एक विशेष पद्धति अपनाई है। इस नई पद्धति के अंतर्गत संस्थान ने छात्रावास के खानपान, सुरक्षा और सफाई तथा आवासीय परिसर की सुरक्षा का प्रबंध बाहरी अभिकरणों को सौप दिया है। पानी के पंप तथा जेनरेटर का परिचालन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ठेके पर होता है।

7.9 कार्यक्रम की रिपोर्ट

संस्थान की मुख्य गतिविधियों का एक संक्षिप्त त्रैमासिक रिपोर्ट निकालकर सभी लोगों में वितरित किया जाता है।

7.10 कार्यालय उत्पादकता की रिपोर्ट और नवाचारी अभिगम

कार्यालय की रिपोर्ट के लिए एक नवाचारी तरीका अपनाया गया है जो सांस्थागत है और जिसके अंतर्गत कार्यालय की प्रभाविता के प्रमुख क्षेत्र, परिचालन और विभिन्न स्थापित, मशीन और उपकरणों के संचालन के अलावा कार्यों के निपटाने से संबंधित संचारेक्षण का कार्य भी होता है।

7.11 स्टाफ में परिवर्तन

संवर्ग स्टाफ

श्री एस. एस. डूडानी (अध्येता) दिनांक 5/4/1989 को सेवानिवृत हुए।

प्रोफेसर श्री प्रकाश ने वरिष्ठ अध्येता (शिक्षा योजना) का पदभार दिनांक 10/4/1989 को ग्रहण कर लिया।

सुश्री. जयलक्ष्मी इंदिरेसन ने वरिष्ठ अध्येता (उच्च शिक्षा) का कार्यभार दिनांक 31/5/1989 को ग्रहण कर लिया।

नीपा के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर के. एम. बहाउद्दीन ने 31/5/1989 को सेवानिवृत हुए।

निदेशक के निजी सहायक श्री ए. के. मलिक अकादमिक स्टाफ कालेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक के पद पर विदेश सेवा हेतु दिनांक 31/5/1989 को प्रतिनियुक्त हुए।

श्री एस. एम. आई. ए. जैदी ने सह–अध्येता (शिक्षा योजना) का पदभार दिनांक 5/9/1989 से ग्रहण कर लिया है।

डा. आरिफ हसन ने अध्येता का पदभार दिनांक 31/12/1989 से संभाल लिया है। (विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा)

डा. जे. वी. जी. तिलक ने वरिष्ठ अध्येता (शिक्षा वित्त) का पदभार दिनांक 1/11/90 से ग्रहण कर लिया है।

डा. अंजना मंगलागिरि ने अध्येता (अंर्तराष्ट्रीय एकक) का पदभार दिनांक 6/2/1990 को ग्रहण कर लिया है।

परियोजना कर्मचारी

सुश्री सुषमा पोपली ने प्रारंभिक शिक्षा (कोप) के संगणीकृत योजना में परियोजना सह–अध्येता का पद भार 1/4/1989 को ग्रहण कर लिया है।

द्वितीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण परियोजना में श्री राजवीर त्यागी ने परियोजना सह–अध्येता का पदभार दिनांक 23/6/1989 से प्रहण कर लिया है।

विद्यालय मानचित्रण परियोजना में श्री सुधीर मलाकार ने परियोजना सह–अध्येता का पदभार दिनांक 30/6/1989 से ग्रहण कर लिया है।

1989-90

विद्यालय मानचित्रण परियोजना में परियोजना अध्येता का पदभार प्रोफेसर एब्रोल ने दिनांक 1/7/1989 से ग्रहण कर लिया है।

प्रोफेसर आर. पी. कथूरिया ने ''बेसिक शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता'' नामक परियोजना पर भोपाल में परियोजना अध्येता और समन्वयक क्षेत्र परिचालक का पदभार 1/11/1989 को ग्रहण कर लिया है।

नीपा में बेसिक शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता नामक परियोजना में डॉ. जी.पी. सिंह, श्री कैलाश और डॉ. देव दीक्षित ने परियोजना सह-अध्येता का पदभार क्रमशः 13/10/1989, 17/10/1989 और 1/11/1989 को ग्रहण कर लिया है।

शैक्षिक प्रशासन के द्वितीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण में डा. जे. सी. गोयल ने दिनांक 23/3/90 को परियोजना अध्येता का पदभार ग्रहण कर लिया है।

7.12 सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.12.1 अंतर्राष्ट्रीय

नीपा मे अध्येता पद पर कार्यरत श्री चिरंजीव मेहता स्टाकहोम विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में दिनांक 1/4/1987 से पी-एच. डी. कर रहे है ।

नीपा में अध्येता पद पर कार्यरत डा. वाई. पी. अग्रवाल ने ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा संस्थान, लंदन विश्वविद्यालय से 'विकासशील देशों में शिक्षा' विषय पर पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान अध्ययन पूरा किया (28/9/1988 से 30/6/1989)

नीपा में सह–अध्येता पद पर कार्यरत सुश्री रंजना श्रीवास्त्व आई. आई. ई. पी. पेरिस, फ्रांस में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में उच्चतर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त की। (28/9/1988 से 20/12/1989)

सुश्री वाई. जोसीफीन, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने पेरिस (फ्रांस) में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में आई. आई. ई. पी. के उच्चतर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया (26/10/1989 से 26/5/1990)

7.12.2 राष्ट्रीय

श्री जे. डी. भाटिया, इलेक्ट्रिशियन ने श्रमिक विद्यापीठ नई दिल्ली से ''इलेक्ट्रिकल ट्रेड'' पर आयोजित पाठ्यक्रम को पूरा किया। (12/6/89 से 21/9/1989)

मानचित्रकार श्री पी. एन. त्यागी ने पुणे के अनुसंधान प्रणाली संस्थान में आयोजित द्वितीय जी. आई. एस. और डेस्कटाप मानचित्रण कार्यक्रम में भाग लिया।

नीपा में सह–अध्येता पर पर कार्यरत श्री ए. सी. मेहता आठ महीने के लिए दिनांक 19/3/1990 में अध्ययन अवकाश पर गए है।

7.13 विदेश में नियुक्तियां

अध्येता डा. जे. बी. जी. तिलक विश्व बैंक वाशिंगटन में अर्थशास्त्री के रूप में मई 1987 से अगस्त 1987 तक और विरजीनिया विश्वविद्यालय यू. एस. ए. में दिनांक 1 सितम्बर से 20 सितंबर 1989 तक प्रोफेसर के रूप में अध्यापन किए।

डा. एन. वी. वर्गीस अध्येता अंर्तराष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान (पेरिस) फ्रांस में दिनांक जनवरी 1988 से जुलाई 1989 तक विसिटिंग फेलोशिप पर कार्यरत रहे।

शैक्षिक योजना एकक के वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष डा. ब्रह्म प्रकाश दिनांक 6 जून 1989 से 12 दिसंबर 1989 तक श्रीलंका में यूनेस्को की ओर से परामर्श कार्य पर कार्यरत रहे और तत्पश्चात् वे मनिला में ऐशियाई विकास बैंक के शैक्षिक प्रभाग में उन्होंने दिनांक 19 जनवरी 1990 को परियोजना अर्थशास्त्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया।

1989-90

7.14 विदेश दौरे

प्रोफेसर सत्यभूषण ने शैक्षिक नीति और सुधार के कार्यान्वयन पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी मे भाग लेने के लिए बैकाक में स्थित यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। (25 अप्रैल – 3 मई 1989)

डा. एन. एम. भागिया ने शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन के लिए अमरीका के सिराक्यूस विश्वविद्यालय का दौरा किया। (अप्रैल – मई 1989)

7.15 परिसर सुविधाएं

संस्थान का कार्यालय चार मंजिला इमारत में है और इसका छात्रावास सात मंजिला है जिसमें 48 कमरे हैं। यह पूर्णतया सुसज्जित है जिसमें शौच वगैरह जुड़ा हुआ है। एक आवासीय परिसर भी है जिसमें आवासीय फ्लैट है जिसमें 16 टाईप – I के क्वार्टर टाईप – II III औरVके आठ–आठ क्वार्टर और एक आवास निदेशक के लिए बना हुआ है। टाईप – IV के आठ क्वार्टरों का निर्माण कार्य जारी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि वार्डन, मेहमान संकाय आवास सुविधा और छात्रावास मे अतिरिक्त ब्लाक का निर्माण किया जाए।

वर्ष के दौरान, दिल्ली फायर सेवा की सलाह से फायर सुरक्षा कदम उठाये गए। इस कार्य में लगभग 9.50 लाख रूपये व्यय होने की संभावना है जिसमें ड्राई राईसर–कम–डाऊन कमर, फाइबर ग्लास की पानी की टंकियां और छात्रावास के लिए सीमेंट और कांक्रीट से बनी सड़कें तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ मिलकर 2 लाख लीटर धारिता वाली पानी की टंकी आदि का प्रावधान इसमें सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान छात्रावास से कुल राशि 3.59 लाख रूपये प्राप्त हुए।

7.16 वित्त

वर्ष 1989–90 के दौरान संस्थान ने 137.50 लाख (80.50 लाख रूपये योजनेत्तर और 57.00 लाख रूपये योजना) रूपये अनुदान प्राप्त किए जबकि 1988–89 में यह राशि 117.36 लाख (79.86 लाख रूपए योजनेत्तर और 37.50 लाख रूपए योजना) रूपये थी।

वर्ष के आरंभ मे संस्थान के पास बकाया राशि कुल 10.15 लाख रूपये (4.50 लाख रूपए योजनेत्तर और 5.65 लाख रूपए योजना) थी। वर्ष के दौरान कार्यालय और छात्रावास से 13.79 लाख रूपए प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 161.44 लाख रूपयों में, वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान से हुए कुल खर्चे 144.00 लाख रूपए है जबकि वर्ष 88-89 क दौरान यह राशि 132.36 लाख रूपएमात्र थी।

वर्ष के दौरान अन्य अभिकरणों से प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन के लिए संस्थान के पास जो बकाया 11.73 लाख रूपए थे उसके अलावा 14.45 लाख रूपए अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन पर कुल व्यय 18.95 लाख रूपये हुए हैं।

वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान तथा अनुदान प्राप्त कार्यक्रम और अध्ययन पर हुए कुल व्यय की राशि वर्ष 1988–89 के 158.70 लाख रूपए के मुकाबले में 162.95 लाख रूपए है।

1989-90

अध्याय 8

सातवीं योजना की उपलब्धियां

सातवी योजना में 1985–90 अवधि के दौरान संस्थान में प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। इसमें कई तरह की विविधताएं भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। अनुसंधान तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों में भी विकास तथा विविधता स्पष्ट रूप से देखा गया है । सातवीं योजना के दौरान संस्थान की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखत है:

प्रशिक्षण गतिविधियां

सातवीं योजना के दौरान लगभग 8000 शिक्षाकर्मी विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिए । इनमें से 48 विदेशी देशों से 350 शिक्षाकर्मियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इसका विस्तारपूर्वक विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 8.1

कार्यक्रम : विकास और भागीदारी

विवरण	1985–86	1986–87	1987–88	1988–89	1989–90	योग योजना VII
कार्यक्रमों की संख्या	57	65	58	66	60	306
कार्यक्रम दिवस	1370	1001	790	740	715	4616
भागीदारों की संख्या	1551	1591	1474	1453	1824	7893
कार्यक्रम व्यक्ति दिवस	21862	19459	15620	15380	19726	92047

शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों और सामाजिक रूप से शोषित वर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और अल्पसंख्यक वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया । शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों से भागीदारों की संख्या 2934 हैं। यह संख्या राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के कुल भागीदारों का 42 प्रतिशत है।

शिक्षा की नई नीति के कार्यान्वयन और सभी कार्यक्रमों के लिए शिक्षा के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुयायीगण समूह में एक परिवर्तन है । शिक्षा अधिकारी और संस्थान के अध्यक्ष जैसे पारस्परिक प्रशिक्षणार्थियों के अतिरिक्त निम्न स्तर पर कार्यरत समुदाय नेता, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक कर्मचारी, राज्य संसाधन केन्द्र, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अकादमिक स्टाफ कालेज के निदेशक और स्वायत्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य आदि कुछ ऐसे नए समूह हैं।

राष्ट्रीय, क्षेत्रवार और अंतराष्ट्रीय भागीदारी तालिका 8.2, 8.3, 8.4 और 8.5 में क्रमशः दी गई है ।

1989-90

प्रशिक्षण गतिविधियां

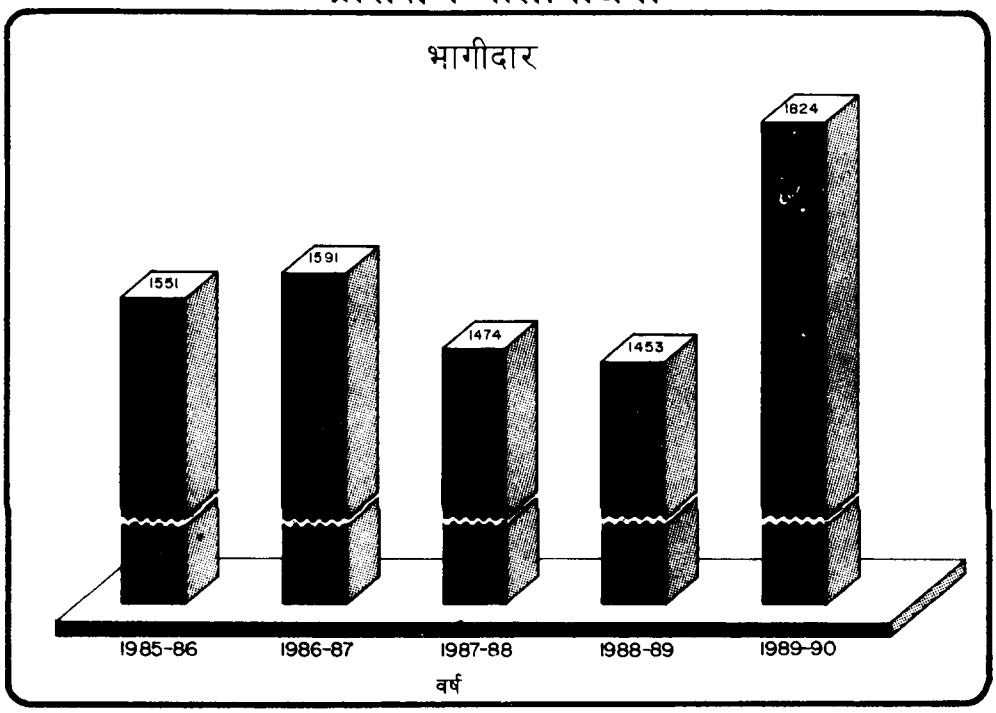

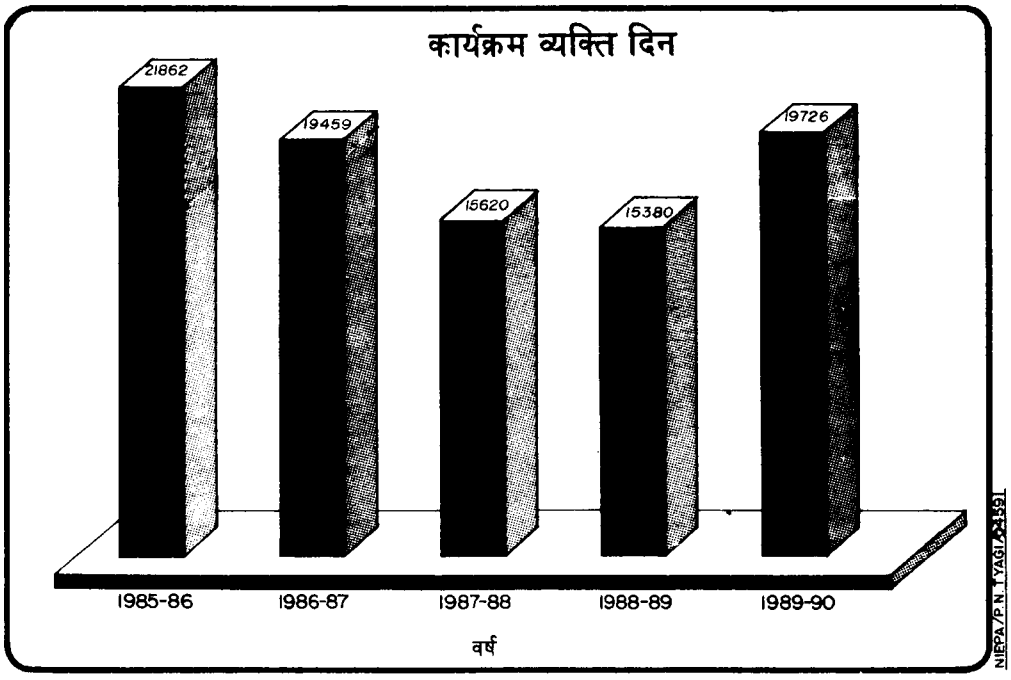

1989-90

तालिका 8.2

राष्ट्रीय भागीदारी

राज्य/के. शा. प्र.	सातवीं योजना					
	1985–86	1986–87	1987–88	1988–89	1989–90	योग
आंध्र प्रदेश @	29	42	23	79	87	260
अरूणाचल प्रदेश @	5	11	3	4	70	93
असम @	27	37	8	8	25	105
बिहार @	28	62	66	39	30	225
गुजरात	44	51	52	72	99	318
गोवा	16	35	50	3	3	107
हरियाणा	338	78	73	111	61	661
हिमाचल प्रदेश	42	22	43	28	21	156
जम्मू और कश्मीर @	15	24	21	38	30	128
कर्नाटक	33	49	39	41	50	212
केरल	37	30	18	25	44	154
मध्य प्रदेश @	210	219	44	77	117	667
महाराष्ट्र	94	80	100	110	81	465
मणिपुर	15	13	11	11	12	62
मेघालय	10	10	13	3	15	51
मिजोरम	2	8	238	10	9	267
नागालैड	5	2	7	17	6	37
उड़ीसा @	17	40	172	36	67	332
पंजाब	23	183	32	31	32	301
राजस्थान @	46	44	115	120	71	396
सिक्किम	4	1	3	8	4	20
तमिलनाडु	43	58	28	97	305	531
त्रिपुरा	14	8	5	15	49	91
उत्तर प्रदेश @	85	104	119	144	86	538
पश्चिम बंगाल @	38	60	38	25	29	190
अंडामान और निकोबार द्वीप समूह	3	2	3	1	2	11
चंडीगढ़	15	17	10	7	11	60
दादरा और नागर हवेली	32	4	6	4	2	48

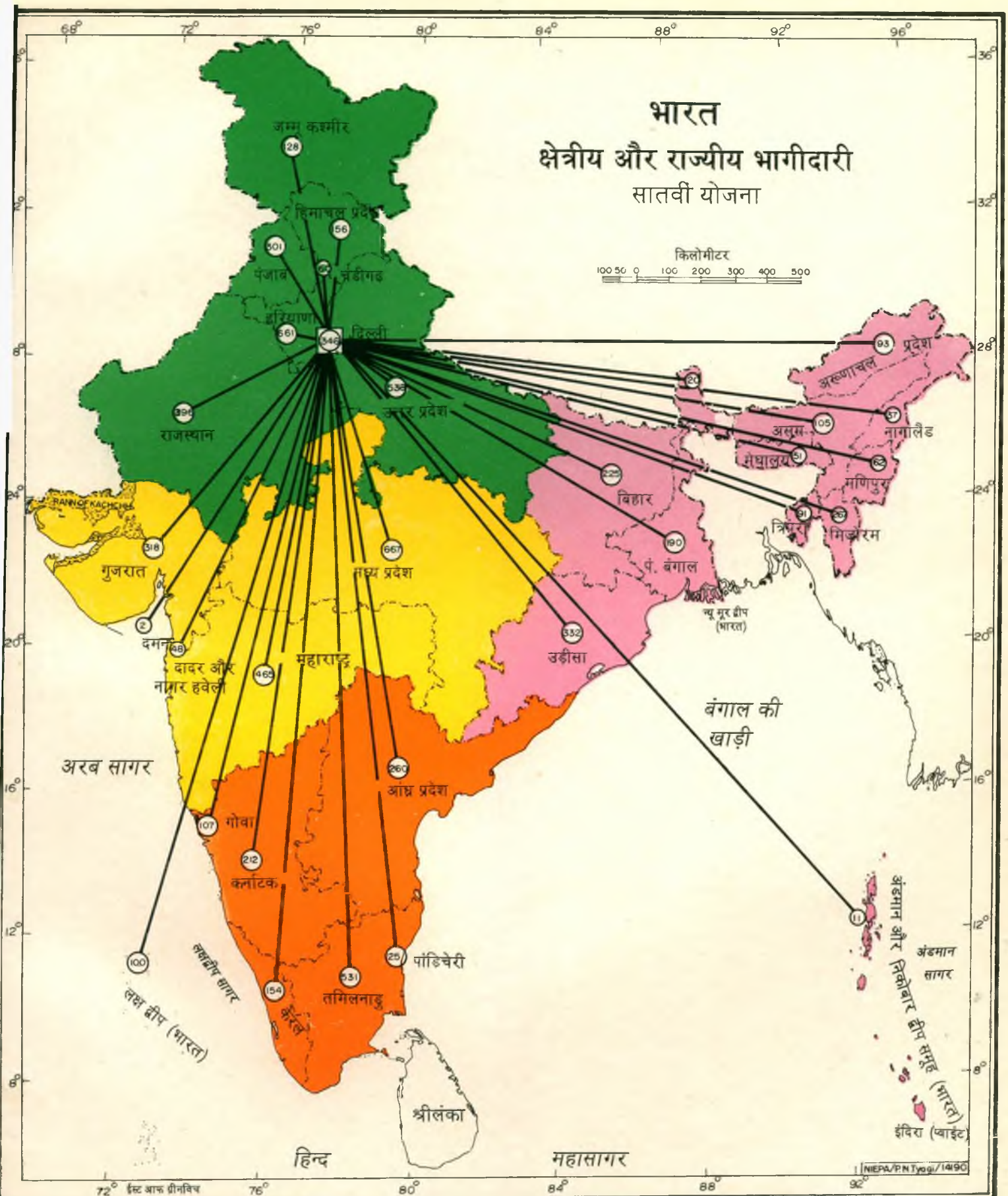

भारत
क्षेत्रीय और राज्यीय भागीदारी
सातवीं योजना
किलोमीटर
100 50 0 100 200 300 400 500
जम्मू कश्मीर
28
हिमाचल प्रदेश
56
301
पंजाब
चंडीगढ़
हरियाणा
561
348
दिल्ली
396
राजस्थान
536
उत्तर प्रदेश
93
प्रदेश
अरुणाचल
20
57
नागालैंड
105
असम
51
मेघालय
62
मणिपुर
225
बिहार
91
त्रिपुरा
26
मिज़ोरम
190
पं. बंगाल
318
गुजरात
RANN OF KACHCHH
667
मध्य प्रदेश
2
दमन
48
दादर और नागर हवेली
465
महाराष्ट्र
332
उड़ीसा
न्यू मूर द्वीप (भारत)
बंगाल की खाड़ी
अरब सागर
260
आंध्र प्रदेश
107
गोवा
212
कर्नाटक
11
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भारत)
अंडमान सागर
100
लक्षद्वीप सागर
लक्षद्वीप (भारत)
25
पांडिचेरी
154
531
तमिलनाडु
केरल
श्रीलंका
हिन्द
महासागर
इंदिरा (प्वाइंट)
ईस्ट आफ ग्रीनविच
NIEPA/P.N.Tyagi/14190

1989-90

1	2	3	4	5	6	7
दमन और दिव	*	*	*	1	1	2
दिल्ली	83	76	31	43	113	346
लक्षद्वीप		2	1	16	1	100
पांडिचेरी	1	3	1	9	11	25
योग	1354	1375	1373	1313	1544	6959
भारत सरकार तथा अन्य	132	133	38	82	231	616
योग	1486	1508	1411	1395	1775	7575

@ शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य

* दमन और दिव को वर्ष 1985-88 में शामिल नहीं किया गया। इसके स्थान पर गोवा को शामिल किया गया।

तालिका 8.3

क्षेत्रवार भागीदारी

क्षेत्र	1985–86	1986–87	1987–88	1988–89	1989–90	योग
पूर्वी	168	254	567	177	318	1484
उत्तरी	647	547	444	522	425	2585
दक्षिणी	142	182	110	347	498	1279
पश्चिमी	397	392	252	267	303	1611
योग	1354	1375	1373	1313	1544	6959

तालिका 8.4

स्तरवार भागीदारी

क्रम सं.	स्तर	भागीदारी
1.	विद्यालय प्राचार्य	1073
2.	जिला शिक्षा अधिकारी	417
3.	अन्य विद्यालय कार्मिक	1746

1989-90

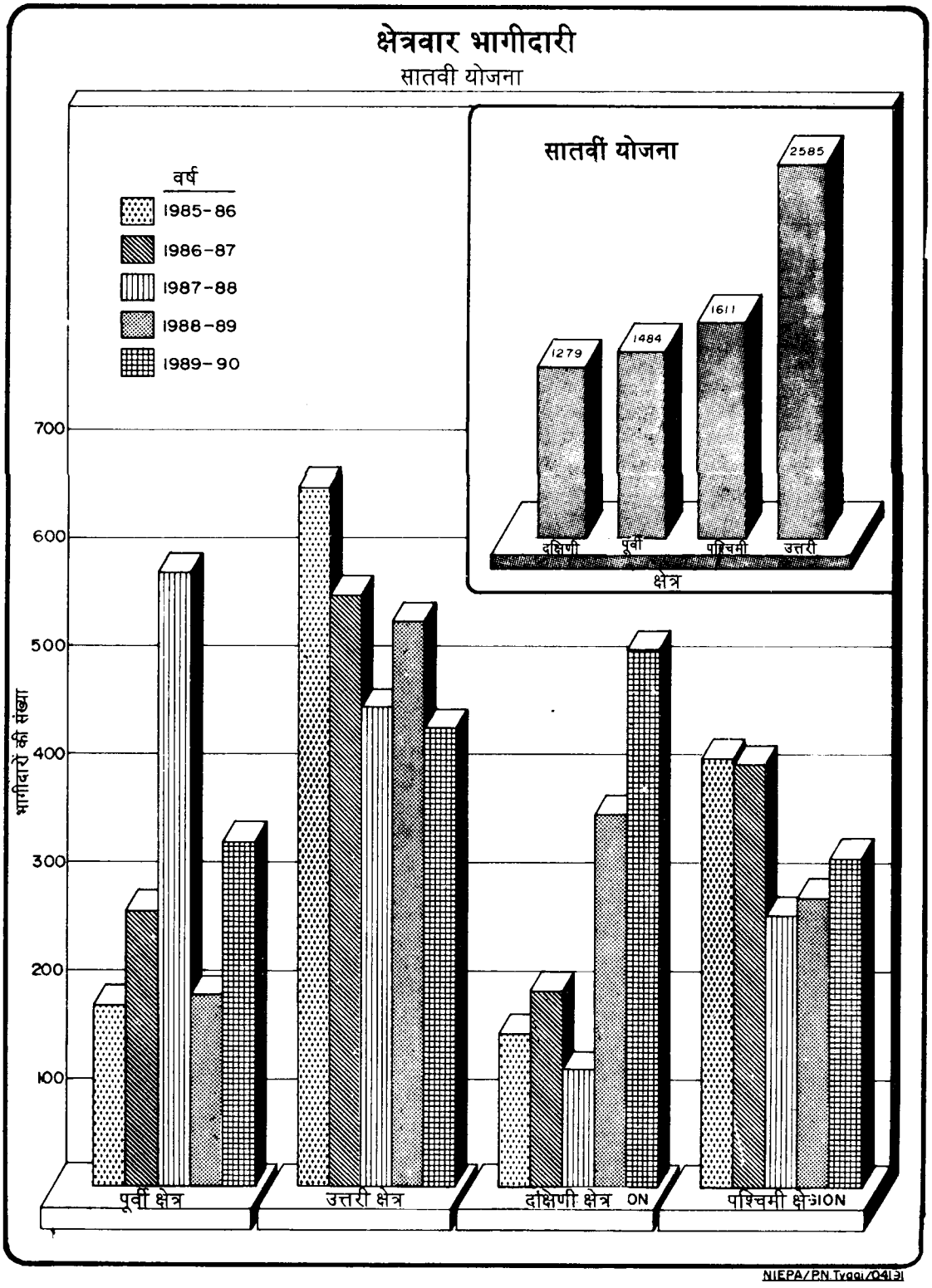
क्षेत्रवार भागीदारी
सातवी योजना
वर्ष
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
सातवीं योजना
2585
1611
1484
1279
दक्षिणी
पूर्वी
पश्चिमी
उत्तरी
क्षेत्र
भागीदारों की संख्या
700
600
500
400
300
200
100
पूर्वी क्षेत्र
उत्तरी क्षेत्र
दक्षिणी क्षेत्र
पश्चिमी क्षेत्र
NIEPA/PN Tyagi/04131

अंतरोष्ट्रीय भागीदारी

सातवीं योजना

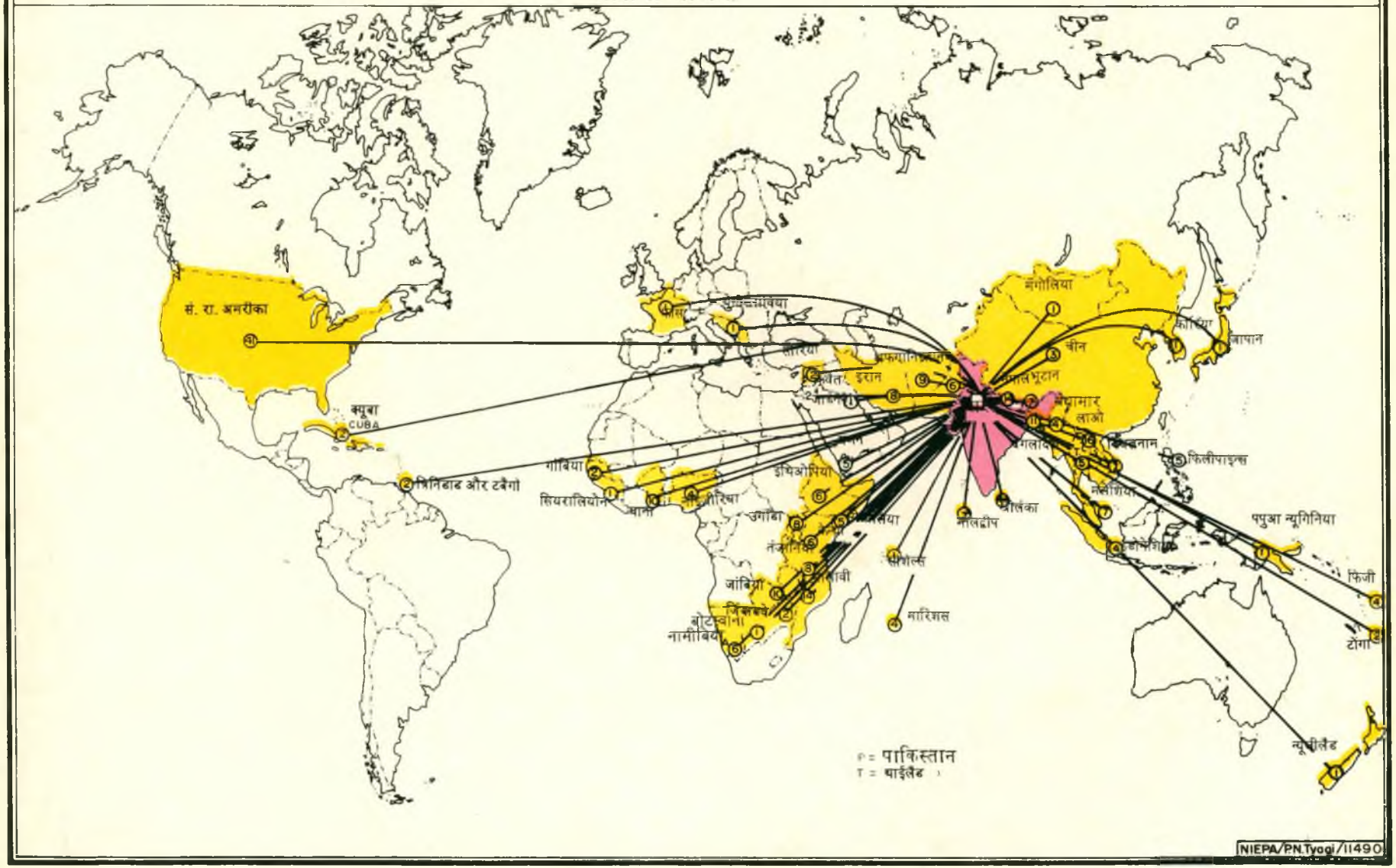

1989-90

क्रम सं.	स्तर	भागीदारी
4.	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	454
5.	वित्त अधिकारी	52
6.	सांख्यिकी कार्मिक	16
7.	महाविद्यालय प्राचार्य	1024
8.	अन्य विश्वविद्यालय कार्मिक	1012
9.	अन्य	1781
10.	विदेश	308
11.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	
	(I) यूनेस्को	3
	(II) यू. एन. आई. सी. ई. एफ.	3
	(III) विश्व बैक	4
	कुल योग	7893

तालिका 85

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

क्रम संख्या	देश का नाम	योग
1.	अफगानिस्तान	9
2.	बंगलादेश	11
3.	बोट्स्वाना	1
4.	भूटान	7
5.	चीन जनगणराज्य	3
6.	क्यूबा	2
7.	इथोपिया	6
8.	फिजी	4
9.	फ्रांस	1
10.	गांबिया	2
11.	घाना गणराज्य	10
12.	इंडोनेशिया	4

1989-90

क्रम संख्या	देश का नाम	योग
13.	ईरान इस्लाम गणराज्य	8
14.	जापान	1
15.	जोर्डन	2
16.	केन्या गणराज्य	6
17.	कोरिया	1
18.	कुवैत	1
19.	लाओ गणराज्य	16
20.	मलेशिया	7
21.	मालावी	14
22.	मालदिव	7
23.	मोरिशस	4
24.	मयांमार	4
25.	मंगोलिया	1
26.	नामीबिया	6
27.	नेपाल	14
28.	न्यूजीलैड	1
29.	नाइजीरिया	4
30.	पाकिस्तान	6
31.	पपुआ नेवागिनिया	1
32.	फिलिपाइंस	5
33.	सीशेलस	1
34.	सियारा लियोन	1
35.	सोमालिया	5
36.	श्रीलंका गणराज्य	44
37.	सिरिया	2
38.	तंजानिया	8
39.	थाईलैड	5
40.	टोंगा	2
41.	ट्रिनिडाड और टोबेगो	2
42.	सयुक्त राष्ट्र अमरीका	41
43.	वियतनाम नणराज्य	2
44.	यमन गणराज्य	5
45.	यूगोस्लाविया	1

1989-90

क्रम संख्या	देश का नाम	योग
46.	यूगांडा	8
47.	जाम्बिया	10
48.	जिम्बाबवे	2
	योग	308
49.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	
	(I) यूनेस्को	3
	(II) यू. एन. आई. सी. ई. एफ.	3
	(III) विश्व बैंक	4
	कुल योग	318

प्रशिक्षण सामग्री

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर सामूहिक प्रशिक्षणम कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान ने 32 मोड्यूल बना लिए हैं । मोड्यूलों की सूची परिशिष्ट V में दी गयी है । शैक्षिक योजना और प्रबन्ध पर कई केस अध्ययन, अनुसंधान अध्ययन, सांख्यिकी आंकड़े तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री तैयार किए गए ताकि प्रशिक्षण सामग्री में इसका उपयोग किया जा सके और इसका विस्तृत प्रसार भी हो सके ।

कुछ प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

(अ) राष्ट्रीय डिप्लोमा

सातवीं योजना के अंतर्गत सात डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किए गए । 22 राज्य 3 केन्द्र शासित प्रदेशों से 144 प्रतिभागियों ने भाग लिया । तालिका 8.6 और 8.7 में इसका विस्तृत बिवरण दिया गया है ।

तालिका 8.6

राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम

वर्ष	डिप्लोमा कार्यक्रम	प्रतिभागियों की संख्या
1985–86	चौथा डिप्लोमा	20
1985–86	पांचवां डिप्लोमा	35
1986–87	छठां डिप्लोमा	18
1986–87	सातवां डिप्लोमा	13
1987 -88	आठवां डिप्लोमा	13
1988-89	नवां डिप्लोमा	19
1989–90	दसवां डिप्लोमा	26
	योग	144

1989-90

तालिका 8.7

राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम में राज्यवार भागीदारी

क्रम संख्या	राज्य/के. शा. प्र. का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	अरूणाचल	3
3.	गुजरात	5
4.	हरियाणा	5
5.	हिमाचल प्रदेश	1
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	12
8.	केरल	14
9.	मध्य प्रदेश	11
10.	महाराष्ट्र	10
11.	मणिपुर	3
12.	मेघालय	6
13.	मिजोरम	3
14.	नागालैंड	2
15.	उड़ीसा	3
16.	पंजाव	5
17.	राजस्थान	9
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	2
20.	त्रिपुरा	4
21.	उत्तर प्रदेश	14
22.	पश्चिम बंगाल	10
23.	चंडीगढ़	2
24.	दिल्ली	11
25.	पांडिचेरी	4
	योग	144

(ब) अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा

पांच अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 33 दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमरीका तथा अन्य तीसरी दुनिया के देशों से 102 वरिष्ठ शिक्षा प्रशासनिकों ने भाग लिया । विस्तृत विवरण तालिका 8.8 और 8.9 में दिया गया है ।

1989-90

तालिका 8.8

अंर्तराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम

वर्ष	डिप्लोमा कार्यक्रम	भागीदारों की संख्या
1985–86	द्वितीय डिप्लोमा	10
1986–87	तीसरा डिप्लोमा	24
1987–88	चौथा डिप्लोमा	20
1988–89	पांचवां डिप्लोमा	31
1989-90	छठां डिप्लोमा	17
	योग	102

तालिका 8.9

अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी

क्रम संख्या	देश का नाम	भागीदारों की संख्या
1.	अफगानिस्तान	3
2.	बंगलादेश	2
3.	क्यूबा	1
4.	इथोपिया	3
5.	फिजी	2
6.	गांबिया	1
7.	घाना	5
8.	इंडोनेशिया	1
9.	ईरान गणराज्य	7
10.	जोर्डन	1
11.	केन्या गणराज्य	3
12.	लाओ	8
13.	मलेशिया	3
14.	मालावी	7
15.	मालदिव	2
16.	मारीशस	2

1989-90

क्रम संख्या	देश का नाम	भागीदारों की संख्या
17.	मंगोलिया	1
18.	मंयामार	2
19.	नामीबिया	3
20.	नेपाल	3
21.	नाइजीरिया	2
22.	फिलिपाइन्स	1
23.	सीशेल्स	1
24.	सियारा लियोन	1
25.	श्रीलंका गणराज्य	16
26.	सीरिया	1
27.	तंजानिया	5
28.	टोंगा	1
29.	ट्रिनिडाड और टोबेगो	1
30.	उगांडा	5
31.	यमन	2
32.	जाम्बिया	5
33.	जिम्बाबवे	1
	योग	102

(स) कैडर पर आधारित अन्य मुख्य कार्यक्रम

- वरिष्ठ विद्यालय प्रशासनिक (तीन सप्ताह के कार्यक्रमों की श्रृंखला)
- जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी
- अनौपचारिक शिक्षा के राज्य स्तरीय अधिकारी
- आई. ए. एस. अधिकारी
- सहायक आयुक्त, शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रधानाचार्य
- महाविद्यालय के प्रधानाचार्य (तीन सप्ताह के कार्यक्रमों की श्रृंखला)
- स्वायत्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य
- अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशक
- विश्व विद्यालयों के वित्त अधिकारी

कुछ प्रमुख कार्यक्रम

- प्रारंभिक शिक्षा के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना
- प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
- पिछड़ी जनजाति के कल्याण के लिए शिक्षा का विकास
- व्यावसायिक शिक्षा
- शिक्षा में समतुल्यता
- शिक्षा और रोजगार संबंध
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी

1989-90

कुछ मुख्य संगोष्ठी/कार्यशिविर

- नई शिक्षा नीति की योजना और प्रबंध संबंधी मामले तथा कार्यान्वयन रणनीतियां
- विद्यालय मानचित्रण
- विद्यालय परिसर
- संस्थागत योजना
- जिला स्तरीय योजना
- शैक्षिक योजना की विकेंद्रीकृत प्रणाली
- ओपरेशन ब्लैक बोर्ड
- प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और गरीबी हटाओ कार्यक्रम में अतः संबंध
- शिक्षा के व्यासायीकरण का प्रबंध मॉलड
- कक्षा 12 के व्यावसायीकरण के लिए कार्यान्वयन रणनीतियां
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रोत्साहन का प्रबंध
- कमजोर वर्गों के लिए मॉडल (रेसिडेंशियल) आवासीय विद्यालय
- महिलाओं की शिक्षा
- कार्यरत बालकों की शिक्षा के लिए रणनीतियां
- पर्यावरण शिक्षा
- विकास के लिए ग्रामीण शिक्षा
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष नीति
- शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली
- शैक्षिक विकास के सूचक
- शिक्षा के संसाधनों का प्रभावी उपयोग
- बेस बजट और निष्पादन बजट
- शिक्षा का अर्थशास्त्र
- प्रयोगशाला क्षेत्र अभिगम
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- विकास के चार दशक : एक पुनरीक्षन सम्मेलन
- शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणक का प्रयोग

अनुसंधान गतिविधियां

सातवीं योजना के अंतर्गत शैक्षिक योजना और प्रशासन में अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान ने काफी प्रगति की है । जून 1987 में संस्थान ने उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय सहायता देने की नई पद्धति शुरू की है । इस योजना की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है ।

सातवीं योजना के अंतर्गत अनुसंधान के खर्चे में काफी वृद्धि हुई है । इसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है :

तालिका 8.10

अनुसंधान पर हुए खर्चे

वर्ष	सरकारी अनुदान का व्यय	वित्तीय सहायता प्राप्त अनुसंधान अध्ययन का व्यय	योग
1985–86	2.97	8.60	11.57
1986–87	3.63	4.27	7.90
1987–88	4.91*	3.06	7.97
1988–89	5.24*	9.26	14.50
1989–90	12.33*	5.24	17.57
योग	29.08@	30.43	59.51

* इसमें वर्ष 1987–88, 1988–89 और 1989–90 के दौरान दी गई क्रमशः 0.48, 0.61 लाख और 1.27 लाख रूपये अनुदान राशि शामिल है । यह राशि अध्ययन के लिए नीपा, वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत है ।

@ सातवीं योजना के दौरान नीपा वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत दी गई 2.36 लाख रूपये का अनुदान इसमें शामिल है।

1989-90

अनुसंधान पर सरकारी अनुदान के व्यय में हुए कुल व्यय में एक तरह से वृद्धि हुई है । यह वर्ष 1985–86 की 2.97 लाख रूपयों के मुकाबले वर्ष 1989–90 में 12.33 लाख रूपये है । इस तरह राशि में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और इसकी कुल प्रतिशत 320 है । प्रायोजित अभिकरणों के अनुरोध पर आयोजित अध्ययन के लिए पर्याप्त राशि एकत्रित की गई । वित्तीय सहायता प्राप्त अनुसंधान अध्ययन के मुकाबले में कुल व्यय की राशि सरकारी अनुदान का अनुसंधान पर हुए खर्चे से अधिक है ।

सातवीं योजना के अंतर्गत पचपन अध्ययन पूरे किए गए । निम्नलिखित तालिका में विवरण दिया गया हैं :

तालिका 8.11

पूरे किए गए अध्ययन

1985–86	20
1986–87	19
1987–88	8
1988–89	3
1989–90	5
योग	55

दिनांक 31.3.90 तक 22 अनुसंधान अध्ययन चल रहे थे और 3 नए अध्ययनों की स्वीकृति दे दी गई थी । सातवीं योजना के दौरान निम्नांकित अध्ययनों पर कार्य चल रहा है जिसमें 9 प्रायोजित अध्ययन है, 4 सहयोगात्मक अध्ययन है और 9 अध्ययन नीपा सहायता योजना के अंतर्गत हैं। इसमें यूनेस्को, ई. एस. सी. ए. पी. ई. बैकाक, आई. आई. ई. पी. पेरिस शिक्षा विभाग और योजना आयोग जैसे संगठन शामिल है जो प्रायोजित भी करते है । सहयोगात्मक अभिकरणों में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, आई. आई. ई. पी. पेरिस, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय शामिल है । परिशिष्ट IV में 31.3.90 तक सातवीं योजना के अंतर्गत पूरे किए गए अध्ययनों की सूची नए स्वीकृत अध्ययन और जारी अध्ययन दिए गए है।

कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान अध्ययन : सातवीं योजना के अंतर्गत पूरे किए गए कुछ प्रमुख अनुसंधान कार्य निम्नांकित हैं: विकास के कुछ मुख्य आयामों पर शिक्षा स्तर का प्रभाव, ग्रामीण घरों का अध्ययन ; भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वाह्य वित्तीय सहयोग; प्रलेख आयोग की रिपोर्ट का विषय विश्लेषण ; यह विश्लेषण नई शिक्षा नीति के सूत्रपादन के अनुसार किया गया है; वर्ष 2000 में भारत की शिक्षा एक दीर्घावधि निहितार्थ; शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन अध्ययन; शिक्षा और विकास का मोनोग्राफ; भारत में उच्च शिक्षा और रोजगार; शिक्षा और श्रम बाजार – भारतीय साक्ष्यों का सर्वेक्षण; उच्च शिक्षा में समता, गुणवत्ता और लागत; पुणहाना खंड के 20 ग्रामीण समूहों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी व्यवहारों पर आधारित कार्य अनुसंधान; महाविद्यालयों का प्रभावी कार्य और विकास; शिक्षा में परिवर्तन का प्रवंध – एक भारतीय नमूना; महिला और विकास पर एक एटलस; उच्च शिक्षा के विशेष क्षेत्रों में संसाधन वितरण पद्धति।

कुछ प्रमुख अध्ययन/परियोजना जिन पर कार्य चल रहा है वह निम्नांकित हैं–वर्ष 2000 में शिक्षा (दूसरा चरण), भारत में

1989-90

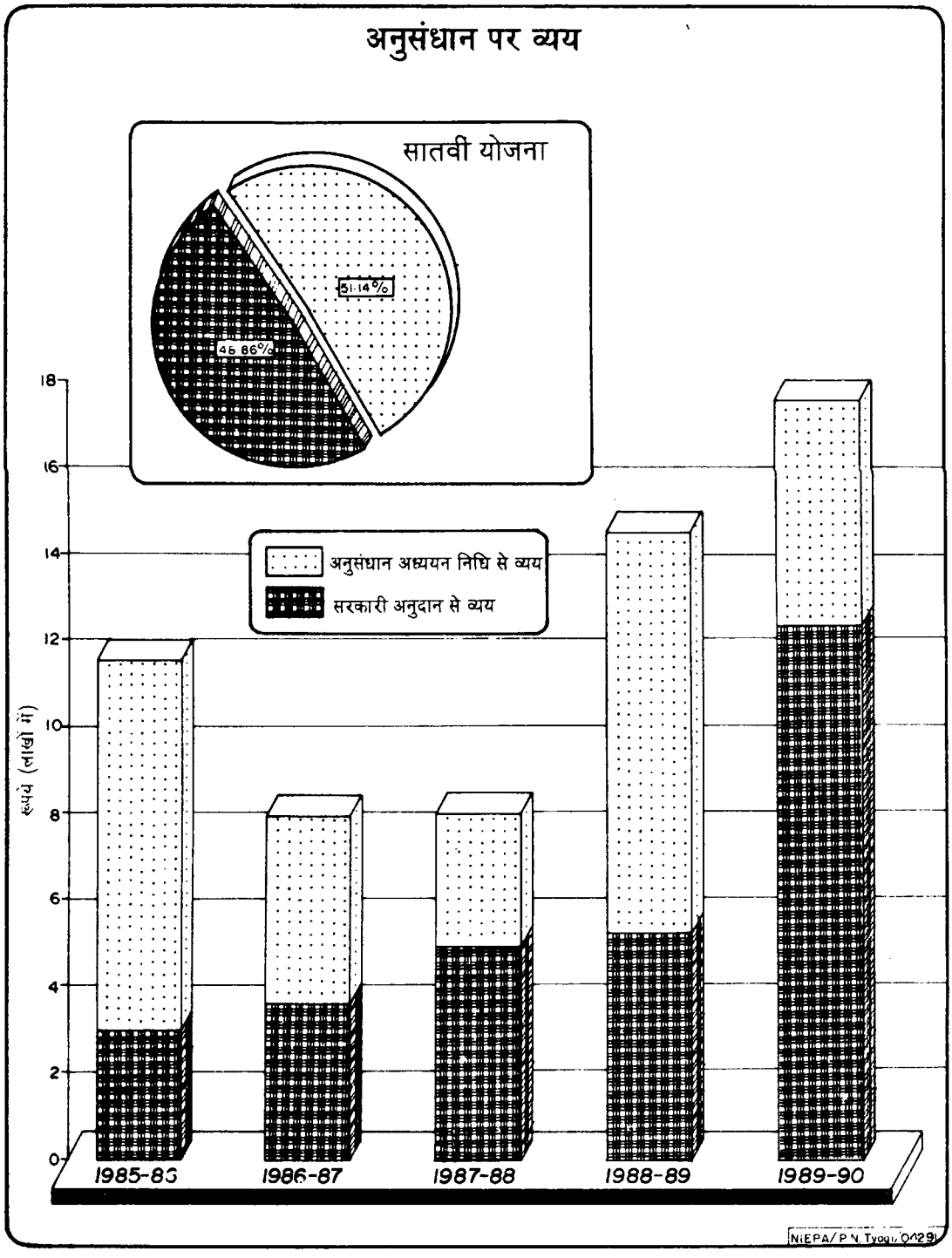

अनुसंधान पर व्यय
सातवीं योजना
51.14%
46.86%
अनुसंधान अध्ययन निधि से व्यय
सरकारी अनुदान से व्यय
रुपये (लाखों में)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
NIEPA/P.N. Tyagi/0429

1989-90

साक्षरता: देश कालिक विश्लेषण (1901–1981), प्रादेशिक क्षेत्र और पिछड़ी जनजातियों का शैक्षिक विकास, विद्यालय मानचित्र, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में द्वितीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण, भारत में अनुसूचित जाति और गैर–अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के साक्षरता स्तरों की विषमताओं का जिलावार विश्लेषण, बेसिक शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता, प्रारंभिक शिक्षा की योजना शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता का प्रबंध, स्वायत्त महाविद्यालयों का अध्ययन, उच्च शिक्षा में संसाधन/उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं का प्रभावी उपयोग, तमिलनाडु में शिक्षा का प्रबन्ध और भारतीय विश्वविद्यालयों का वित्त प्रबंध ।

परामर्शकारी, सलाहकारी और समर्थन सेवाएं

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का सूत्रपादन, क्रियान्वयन का कार्य और नीति के कार्यान्वयन ने संस्थान के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है कि वे अपने प्राप्त अनुभवों को विशेषज्ञों तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख कार्यो के लिए विभिन्न अभिकरणों के साथ बांट सके ।

(अ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के निर्णयों के अनुसार, स्वतंत्रता प्राप्त होने के उपरान्त से शैक्षिक विकास का एक नैदानिक निर्धारण किया गया और ''प्रतिष्ठा रिपोर्ट तथा नीति संबंधी मामले'' पर एक प्रलेख तैयार किया गया । मंत्रालय का प्रलेख ''शिक्षा की चुनौती'' कुछ हद तक संस्थान द्वारा किए गए अभ्यासों पर आधारित था ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए प्रस्तावो को प्रतिपादित करने के लिए नीपा ने चार क्षेत्रीय संगोष्ठी तथा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया ।

मंत्रालय द्वारा पत्र/प्रलेख/प्रेस क्लिपिग/ तथा अन्य रिपार्ट आदि ये सब मिलाकर लगभग 7000 के आस पास प्राप्त किए और विषय विश्लेषण का कार्य नीपा को सौपा गया । नीति प्रतिपादन के लिए आगत के रूप में मंत्रालय द्वारा गठित समूहों और विभिन्न समितियों को विभिन्न प्रलेख/संचार/रिपोर्ट के विषय विश्लेषण पर आधारित 16 प्रलेख तैयार करके दिए गए । इन अध्ययनों में नागरिक बोध, भारतीय शिक्षा प्रणाली की सामाजिक लेखा परीक्षा, भारीय शिक्षा का पुर्नगठन, शिक्षा के स्वैच्छिक और व्यावसायिक निकाय, नई शिक्षा नीति पर प्रेस टिप्पणी और राज्यों के प्रत्यक्षबोध शामिल है ।

(ब) कार्यवाही योजना

जून 1986 में नीपा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन रणनीतियों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय ने किया जिसमें यूनेस्को, यूनिसेफ, आठ विदेशी विशेषज्ञ, मंत्रालय, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और व्यावसायिक निकायों के प्रसिद्ध शिक्षा कर्मियों तथा विद्वानों आदि की मिलाकर 57 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

योजना आयोग, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान और ई. डी. आई. (विश्व बैंक) के सहयोग से एक दूसरी संगोष्ठी का आयोजन 1986 में किया गया । इस संगोष्ठी में 28 भारतीय विशेषज्ञों के साथ विश्व बैंक के विशेषज्ञों के एक दल ने भी भाग लिया ।

इन दोनों संगोष्ठियों का विवरण मंत्रालय को भेज दिया गया। गया ।

(स) नई शिक्षा नीति – 1986 का क्रियान्वयन

(i) मार्गदर्शन

संस्थान ने निम्नांकित की स्थापना हेतु मार्गदर्शिका तैयार करने के लिए विस्तृत अभ्यास किए :

राज्य शिक्षा सलाहकारी बोर्ड
जिला शिक्षा बोर्ड

1989-90

ग्राम शिक्षा समिति
राज्य शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
नवोदय विद्यालय

संस्थान ने निम्नांकित विषयों पर भी मार्गदर्शिकाएं तैयार की है:

व्यष्टि स्तरीय योजना
विद्यालय मानचित्रण
विद्यालय परिसर
ग्राम शिक्षा समिति

(ii) प्राथमिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों के प्राथमिक क्षेत्रों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । राज्य जिला और खंड स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए एक विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित की गई । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विविध पक्षों पर 32 आत्म शिक्षण मोड्यूल तैयार किए गए जिसकी सूची परिशिष्ट V में दी गई है । इसे राज्यों में भेजा गया है ताकि वे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इसे अपनाए या इसका अनुकूलन कर सके ।

(iii) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दादरा और नागर हवेली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अधिकारियों के लिए जिला स्तर पर राज्य शिक्षा विभाग के अनुरोध पर निम्नांकित विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । ये क्षेत्र है : विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय परिसर और शैक्षिक योजना की विकेन्द्रीकृत पद्धति ।

(iv) राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन योजनाएं बनाने के लिए सस्थान ने निम्नांकित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को व्यावसायिक समर्थन प्रदान किए है । ये है : अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, लक्ष्यद्वीप, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश।

(v) केन्द्रीय स्तर के संगठनों को व्यावसायिक सेवाएं

प्राथमिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), योजना आयोग, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों के लिए संस्थान ने व्यावसायिक समर्थन प्रदान किए । कुछ मुख्य प्रलेखों की सूची निम्नांकित है :

(अ) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए एक प्रारूप रिपोर्ट
(ब) भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना के लिए एक व्यापक प्रलेख
(स) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जिला स्तरीय शिक्षा प्रशासन की प्रशासनिक स्थापना हेतु ओरगेनोग्राम का एक सेट
(द) सीमा क्षेत्रों में शैक्षिक विकास के लिए प्रारूप मार्गदर्शिका

इन्होंने निम्नांकित क्षेत्रों को भी व्यावसायिक समर्थन दिए :

(अ) प्रौढ़ महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए शिक्षा पर संक्षिप्त पाठ्यक्रम का सिलेबस तैयार करने हेतु केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्थापित उपसमूह
(ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वाधान में विश्वविद्यालयों के लिए दूरवर्ती शिक्षा केंद्र की स्थापना हेतु मार्गदर्शिका का प्रतिपादन करने के लिए परामर्शकारी समिति
(स) नवाचार निदेशालय और ग्राम निर्माण की स्थापना के लिए पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना

1989-90

(vi)शिक्षा की केंद्रीय सलाहकार परिषद् (केब)

केब के निम्नांकित समिति को संस्थान ने व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की :

अध्यापकों का स्थानांनतरण : महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में फरवरी 1987 को समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्य सचिव नीपा के निदेशक है । इस समिति का काम अध्यापकों से परामर्श करके तैनाती और स्थानांतरण के लिए मानदण्ड तथा कार्यविधि तैयार करना है । रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर इसे राज्य सरकारों में वितरित किया गया ।

महिला अध्यापकों के लिए आवास सुविधाएं : राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में मई 1987 को एक समिति का गठन किया गया। प्रादेशिक प्रणाली एकक ने समिति को सेवाएं प्रदान की । इस समिति का काम महिला अध्यापकों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक मानदण्ड तैयार करना और सुझाव देना है ।

शिक्षा का प्रबन्ध :इस समिति का गठन मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में जून 1987 को किया गया । इस समिति के सदस्य सचिव नीपा के निदेशक होंगे । इस समिति का काम शिक्षा की दीर्घावधि योजना और प्रबन्ध निहितार्थ तथा देश का विकास और संसाधन आवश्यकताओं के साथ देश की एकता के लिए सिफारिश करना है ।

(vii) अनौपचारिक शिक्षा के क्रियान्वयन में आगत के रूप में अनुसंधान

अनौचारिक शिक्षा के क्रियान्वयन के संदर्भ में कई अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाओं का कार्य लिया गया है । (अनुबंध VI में अध्ययनों की संदर्भ सूची दी गई है ।

(द) अन्य परामर्शकारी, सलाहकारी तथा समर्थन सेवाएं

इनमें निम्नांकित शामिल है :

(i) राज्य के शा प्र. के शिक्षा विभागों का पुनर्गठन

संस्थान ने निम्नांकित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का व्यावसायिक मार्गदर्शन किया ताकि वे अपने राज्यों में शिक्षा विभागों का पुनर्गठन कर सकें। ये राज्य है : अरूणाचल प्रदेश, असम, दादरा नागर हवेली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा लक्ष्यद्वीप ।

(ii) आठवीं योजना कार्यसमूह और वार्षिक योजना से संबंधित परिचर्चाओं का व्यावसायिक समर्थन

(iii) राज्य सरकारों की दी गई समर्थन सेवाएं

संकाय द्वारा राज्य सरकारों को निम्नांकित क्षेत्रों सें समर्थन दिया गया है :

(अ) माध्यमिक विद्यालयों की सांस्थागत योजना और मूल्यांकन के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता,

(ब) जिला स्तर पर प्रारूप का डिजायन तथा नियंत्रण का मॉडल विकास करने के लिए हरियाणा और तमिलनाडु सरकार की मदद करना,

(स) विद्यालय के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए दादरा और नागर हवेली की मदद करना और

(द) अरूणाचल प्रदेश के लिए 20 साल की निहितार्थ योजना तैयार करने के लिए ई. डी. सी. आई. एल. को परामर्श देना।

(iv) विदेश परामर्श

संकाय द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों में परामर्श दिए गए :

(अ) ई. डी. सी. आई. एल. के अनुरोध पर सोमालिया के महिला शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास,

(ब) मालदीव गणराज्य के लिए मानव संसाधन विकास और शिक्षा कार्यान्वयन हेतु एटल वार कार्य योजना का विकास करना,

(स) यूनेस्को (बैंकांक) के लिए व्यष्टि स्तरीय शैक्षिक योजना और प्रबन्ध पर एक मैनुअल तैयार करना,

(द) शैक्षिक योजनाकारों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर पुस्तिका तैयार करना।

1989-90

अन्य अकादमिक गतिविधियां

(अ) नवाचारों का प्रसार

संस्थान ने निम्नांकित दो अध्ययन दौरे आयोजित किए :

(i)तमिलनाडु में 8–14 फरवरी 1986 तक 20 चुने हुए महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य द्वारा स्वायत्त महाविद्यालयों का अध्ययन दौरा । इस दौरे की रिपोर्ट का शीर्षक ''स्वायत्तता और उत्तरदायित्व'' रखा गया तथा इसका प्रकाशन किया गया ।

(ii)प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं में ग्रामीण विकास से संबंधित गांधीग्राम परीक्षणों की प्रथम सूचना लेने के लिए फरवरी 22–26 1988 तक का गांधीग्राम का अध्ययन दौरा ।

(ब) शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी संकलपनाओं और व्यवहारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए वर्ष 1982–83 के दौरान शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी संकलपनाओं और व्यवहारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने की वजह से इसे वर्ष 1986–87 से बंद करने का निर्णय लिया गया । अब यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करवाने के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में सफल दीर्घावधि नवाचारी परियोजनाओं की पहचान किया जाए ।

(स) शैक्षिक मुद्दों पर अनौपचारिक चर्चा

(द) शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासनिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना

प्रशिक्षण, अनुसंधान, सलाहकारी तथा अन्य गतिविधियों का समिश्रण

प्रशिक्षण और अनुसंधान पर हुए सरकारी अनुदान व्यय व्यय में का निम्नांकित विवरण प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के बीच ज्यादा संतुलन रखता है :

तालिका 8.12

सरकारी अनुदानों से प्रशिक्षण और अनुसंधान पर हुए व्यय (रूपये लाखों में)

वर्ष	प्रशिक्षण	अनुसंधान	योग
1985–86	10.68	2.97	13.65
	(78.24%)	(21.76%)	13.73
1986–87	10.10	3.63	13.73
	(73.56%)	(26.44%)	
1987–88	7.79	4.91*	12.70
	(61.34%)	(31.26%)	
1988–89	11.52	5.24*	16.75
	(68.74%)	(31.26%)	
1989–90	14.09	12.33*	26.42
	(53.33%)	(46.67%)	
	54.18	29.08*	83.26
	(65.07%)	(24.93%)	

*नीपा सहायता योजना के अंतर्गत दिए गए अनुदान भी शामिल किए गए है।

1989-90

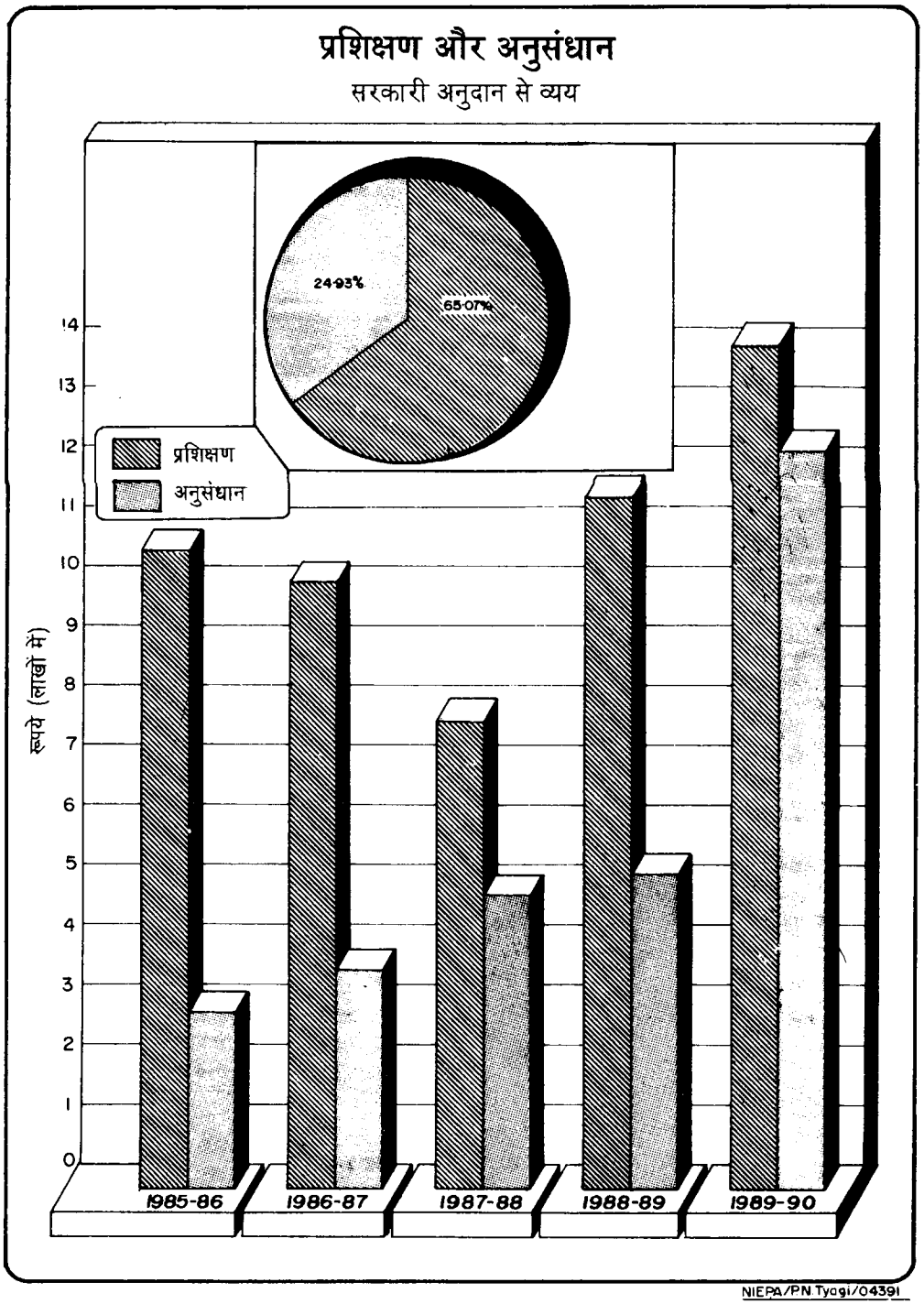
प्रशिक्षण और अनुसंधान
सरकारी अनुदान से व्यय
24·93%
65·07%
प्रशिक्षण
अनुसंधान
रुपये (लाखों में)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
NIEPA/P.N.Tyagi/04391

1989-90

जबकि सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान से प्रशिक्षण और अनुसंधान पर हुए कुल व्यय क्रमशः 78% और 22% के अनुपात में है जो कि सातवीं योजना के अंतिम वर्ष में बढ़कर 53% और 47% हो गया है । इसके अतिरिक्त, तालिका 8.10 में अन्य अभिकरणों द्वारा प्रायोजित वित्त प्राप्त अनुसंधान के लिए किए गए खर्चो से पता चलता है कि सातवीं योजना के अंतर्गत संस्थान में अकादमिक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान गतिविधियों को काफी प्राथमिकता मिली है ।

प्रकाशन

समूल्य

शैक्षिक योजना – एक दीर्घावधि निहितार्थ मूनिस रजा द्वारा संपादित, 1985
विद्यालय निरीक्षण पद्धति : आधुनिक अभिगम
–आर पी. सिंघल, एन. एम. भागिया, टी. के. डी. नायर और वी. ए. कलपांडे, 1986
एम. एल. सोही द्वारा लिखित विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए वित्त कोड, 1987
भारतीय विद्यालय : अध्यापन छात्र अनुपात
अध्ययन – आर. पी. सिंघल, 1988
शैक्षिक सेवाओं का विकास और संचालन : एक मानदंड का अध्ययन, श्री एम. एम. कपूर और सुश्री कुसुम प्रेमी, 1988,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां : पांच राज्यों का अध्ययन-सुश्री कुसुम प्रेमी 1989

मूल्यरहित

महाविद्यालयों में अध्यापन की प्रणाली
शिक्षा और विकास – श्री एस. सी. नूना
पर्यावरण शिक्षा : अध्यापकों का प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या का विकास, शैक्षिक योजनाकार और प्रशासक

शिक्षा का विकास : 1986–88 – आई. सी. ई. जेनेवा के 41 वां अधिवेशन के लिए भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट ।

विद्यालय मानचित्रण : राष्ट्रीय कार्यशिविर की रिपोर्ट पर आधारित मार्गदर्शिका

नीपा प्रलेखन सेवाएं – स्टाफ विकास और शिक्षा पर दो अंक और 'शिक्षा पर - श्री जे. पी. नायक'

ग्राम स्तर पर व्यष्टि योजना – एम. एडम

शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासनिकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर अंतरक्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रिपार्ट

अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबन्ध – परियोजना अधिकारियों के लिए एक मैनुअल (हिन्दी, अंग्रेजी, उड़िया, उर्दू, बंगला, तेलगू तथा असमिया)

सन् 2000 तक सभी के लिए शिक्षा – भारतीय निहितार्थ ।

प्रेस में

विद्यालय और ग्राम विकास – मूनिस रजा और एच. रामचंद्रन (समूलय)
शैक्षिक योजनाकारों के लिए पर्यावरण शिक्षा-
हस्तपुस्तिका – प्रो. सत्यभूषण, आर. गोविंदा और सुश्री ए. मंगलागिरि (मूल्य रहित)
भारत में विद्यालय शिक्षा- मुनिस रज़ा, ए. अहमद और एस.सी. नूना
शिक्षा मंत्रालय : एक संगठनात्मक इतिहास-ए. मैथ्यू (मूल्यरहित)
महिला और विकास एट्लस – एस. सी. नूना

बुलेटिन/जर्नल

ई. पी. ए. बुलेटिन के छः अंक प्रकाशित किए गए हैं। ई. पी. ए. बुलेटिन के स्थान पर संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रशासन त्रैमासिक जर्नल निकालने का निर्णय लिया। जर्नल के पांच विशेषांक निकाले गए : शैक्षिक समता संसाधन, शैक्षिक योजना, दूरवर्ती शिक्षा और तीसरी दुनिया में शैक्षिक योजना और प्रबंध शैक्षिक योजना और प्रशासन

1989-90

जर्नल का हिन्दी रुपांतर निकाला गया । शिक्षा में समता; शिक्षा और शैक्षिक योजना के लिए संसाधन पर विशेष अंक निकाले गए ।

अनियत पत्र

योजना अवधि के दौरान 10 अनियत पत्रों की सूची अनुबंध VII में दी गई है । ये पत्र विस्तृत रूप से वितरित किए गए।

कार्मिक

(अ) संवर्ग (कैडर) योजना

सातवीं योजना के दौरान संवर्ग (कैडर) योजना का मुख्य उद्देश्य विस्तार की बजाय मानव संसाधनों को समेकित तथा अनुकूल बनाने पर ध्यान देना है । योजना अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या अंश मात्र के लिए हुई है जैसा कि सातवीं योजना के प्रथम और अंतिम वर्ष में देखा जा सकता है । यह सूची निम्नलिखित है :

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या
1.4.1985	161
31.3.1990	176

इसके अलावा 31/3/1990 तक लगभग 50 परियोजना कर्मचारी कार्यरत थे ।

(ब) मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास के उपलक्ष में अकादमिक और अन्य कर्मचारियों की सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देश तथा विदेश से सेवारत प्रशिक्षण कर्यक्रम में संकाय तथा अन्त कर्मचारियों ने काफी तादाद में भाग लिया ।

(स) सामूहिक बचत बीमा योजना

संस्थान में मार्च 1986 से सामूहिक बचत बीमा योजना का कार्य लागूकिया गया।

(द) नीपा के नियम और विनियम

नीपा की सेवा विनियम 5/1/1990 से लागू की गई । इसमें संस्थान के कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं।

नीपा परिसर

टाईप – IIऔर टाईप III के आठ–आठ क्वार्टर बनाए गए और टाईप IVके 8 क्वार्टरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त तीसरी मंजिल का भी निर्माण किया गया जो कि कार्यालय में कमरों की कमी को कुछ हद तक पूरा कर रही है । लेक्चर हाल, कंप्यूटर केंद्र, संगोष्ठी कक्ष तथा अन्य परिचालन एकक के लिए एक जेनेरेटर सेट की भी स्थापना कर दी गई ताकि बिजली की सप्लाई में कोई बाधा न पहुंचे । नीपा छात्रावास में वार्डन के लिए आवास, अतिथि संकाय तथा अतिरिक्त खंड का निर्माण करने का भी निर्णय लिया गया है ।

अनुदान व्यय

संस्थान में प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श तथा अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में काफी हद तक विकास हुआ है जिसका प्रमाण व्यय में हुई वृद्धि है । इसे निम्नांकित तालिका 8.13 में देखा जा सकता है :

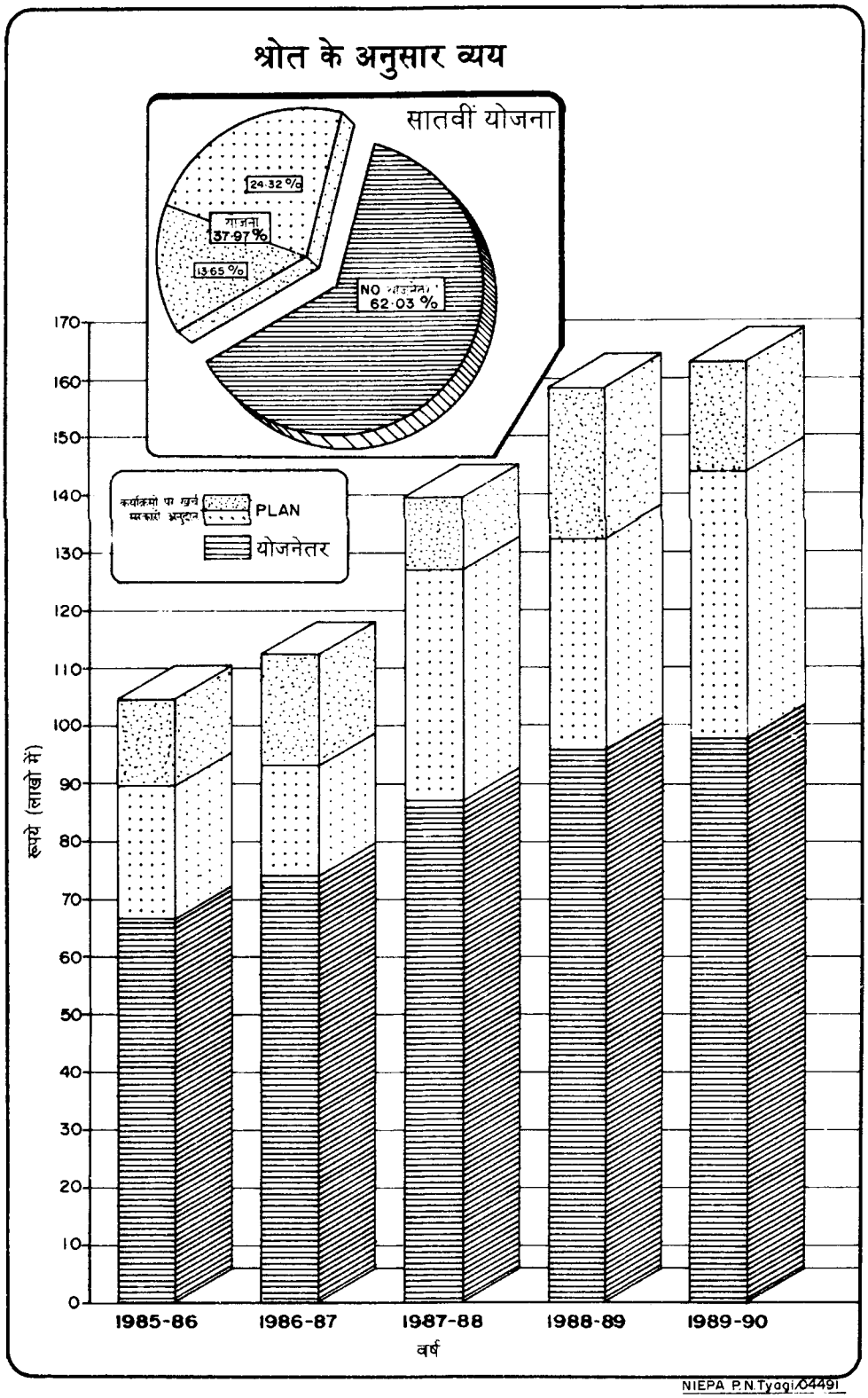

1989-90

NIEPA P.N.Tyagi.04491

1989-90

तालिका 8.13

सातवीं योजना के दौरान अनुदान व्यय

वर्ष	सरकारी अनुदान		निधि प्राप्त	योग
	योजनेत्तर	योजना		
1985–86	66.49	23.14	15.00	104.63
1986–87	73.92	19.07	18.33	112.75
1987–88	87.08	39.96	12.60	139.64
1988–89	96.45	35.91	26.34	158.70
1989–90	97.03	46.97	18.95	162.95
योग	420.97	165.05	92.65	678.67

योजनेत्तर और योजना के अंतर्गत अनुदान का उपयोग छठीं योजना के 299.35 रूपयों के मुकाबले में सातवीं योजना के दौरान 586.02 लाख रूपये हैं ।

छठी योजना के 42.19 लाख रूपयों के मुकाबले सातवी योजना में अन्य माध्यमों से एकत्रित की गई राशि दुगुनी से भी ज्यादा लगभग 92.65 लाख रूपये हो गई है ।

पुनरीक्षण

संस्थान की 1980–81 से सात वर्ष की अवधि का आंतरिक मूल्यांकन पुनरीक्षण का कार्य किया गया । पुनरीक्षण रिपोर्ट बहु–आयामी विकास का एक विस्तृत व्यौरा प्रस्तुत करता है और प्राथमिक संस्थानों की विस्तृत भूमिका का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में नए क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट करता है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा मार्च 1989 को एक विशेषज्ञ पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया । इस समिति ने सितंबर 1989 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की । इस समिति ने नीपा की भविष्य की भूमिका, प्रशासनिक ढांचे का पुर्नगठन और प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अनुसंधान और प्रकाशन आदि पर कुछ प्रमुख प्रस्ताव रखे।

मार्च–जून 1989 के दौरान सी. ए. जी. कार्यालय द्वारा संस्थान के कार्यो के संदर्भ में एक विशेष अंकेक्षण किया गया जिसमें 1981–89 तक का अनुसंधान अध्ययन और 1984–89 तक की अन्य अकादगिक गतिविधियों के क्षेत्र पर विचार किया गया है ।

1989-90

अनुबंध-I

तालिकाएं (सातवीं योजना)

तालिका 1.1

कार्यक्रम में भागीदारी (सातवीं योजना)

विवरण	संख्या
कार्यक्रमों की संख्या	306
कार्यक्रमों के दिनों की संख्या	4616
भागीदारों की संख्या	7893
कार्यक्रम दिनांक दिन	92047

तालिका 1.2

राष्ट्रीय भागीदारी (सातवीं योजना)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	योग
आंध्र प्रदेश*	260
अरूणाचल प्रदेश*	93
असम*	105
बिहार*	225
गुजरात	318
गोवा	107
हरियाणा	661
हिमाचल प्रदेश	156
जम्मू–कश्मीर*	128
कर्नाटक	212
केरल	154
मध्य प्रदेश*	667

1989-90

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	योग
महाराष्ट्र	465
मणिपुर	62
मेघालय	51
मिजोरम	267
नागालैंड	37
उड़ीसा*	332
पंजाब	301
राजस्थान*	396
सिक्किम	20
तमिलनाडु	531
त्रिपुरा	91
उत्तर प्रदेश*	538
पश्चिम बंगाल*	190
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	11
चंडीगढ़	60
दादरा नागर हवेली	48
दमन दिव**	2
दिल्ली	346
लक्षद्वीप	100
पांडिचेरी	25
योग	6959
भारत सरकार और अन्य	616
कुल योग	7575

*शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य

**वर्ष 1985–86 के दौरान गोवा के बदले दमन और दिव को शामिल किया गया ।

1989-90

तालिका 13

क्षेत्रवार भागीदारी (सातवीं योजना)

क्षेत्र	संख्या
उत्तरी	2585
पश्चिमी	1611
पूर्वी	1484
दक्षिणी	1279
योग	6959

तालिका 14

अनुसंधान पर व्यय (सातवीं योजना)

वर्ष	रू. (लाख में)
1985–86	11.57
1986–87	7.90
1987–88	7.97
1988–89	14.50
1989–90	17.57
योग	59.51

1989-90

अनुबंध-II

वर्ष 1989-90 (1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990) के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी/कार्यशिविर

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक &अवधि	प्रतिभागितयों की संख्या	कार्यक्रम व्यक्ति दिवस
1	2	3	4	5
1.	**डिप्लोमा कार्यक्रम** **राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम** जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में नौंवा पूर्व प्रवेश कार्यक्रम चरण-II (एस.एन.एफ.एकक) (जारी)	1 नवंबर 1988 30 अप्रैल 1989 (30 दिन)	19	570
	चरण-III	10-13 जुलाई 1989 (4 दिन)	19	76
1.1	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में दसवां पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम चरण-I (एस.एन.एफ.एकक)	1 नवंबर 1989 सें 31 जनवरी 1990 (92 दिन)	26	2392
	चरण-II	1 फरवरी-30 अप्रैल 1990 (59 दिन)	26	1534
	1*	185	45**	4572
	(ब) अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम शैक्षिक योजना और प्रशासन में पांचवीं अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (चरण II) (अंतर्राष्ट्रीय एकक) (जारी)	16 जनवरी से 15 जुलाई 1989 (106 दिन)	31	3286

1989-90

1	2	3	4	5
1.2	शैक्षिक योजना और प्रशासन में छठी अंर्तराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्य़क्रम (अंर्तराष्ट्रीय एकक)	22जनवरी-21 जुलाई 1990 (69 दिन)	17	1173
	1*	175	48**	4459
2.	**प्रशिक्षण अभिविन्यास कार्यक्रम (अ) स्तर विशेष**			
2.1	वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए नवोदय विद्यालय समिति की योजना और प्रबंध का अभिविन्यास कार्यक्रम (प्रशासन एकक)	25-29 सितंबर 1989 (5दिन)	16	80
2.2	वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए नवोदय विद्यालय समिति की शैक्षिक योजना और प्रबंध का अभिविन्यास कार्यक्रम (प्रशासन एकक)	16-20 अक्तूबर 1989 (5 दिन)	16	80
2.3	केंद्रीय विद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्यों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	16-27 अक्तूबर 1989 (12 दिन)	25	300
2.4	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों के लिए प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से) (एस.एन.एफ.एकक)	6-25 नवंवर 1989 (20 दिन)	45	900
2.5	रेलवे स्कूल बोर्ड के संसाधन व्यक्तियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (प्रशासन एकक)	15-17 नवंबर 1989 (तीन दिन)	12	36
2.6	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा डी.ए.ई. के सहयोग से)	29 जनवरी से 17 फरवरी 1990 (20 दिन)	33	660

1989-90

1	2	3	4	5
2.7	वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में सत्तरहवां अभिविन्यास कार्यक्रम (व्यावसायिक प्रतिभा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया) (एस.एन.एस.एकक)	12 फरवरी-2 मार्च 1990 (दो दिन)	14	266
2.8	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की योजना और प्रबंध एकक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस.एन.एस.एकक)	19-31मार्च 1990 (13 दिन)	39	497
	8	97	200	2819
	(ब) उच्च शिक्षा			
2.9	पंजाब राज्य के महाविद्यालयों के लिए महाविद्यालयों की योजना और प्रबंध हेतु संसाधन व्यक्तियों का अभिविन्यास कार्यक्रम (उच्च शिक्षा)	13-24 जून 1989 (12 दिन)	12	144
2.10	अकादमिक स्टाफ कालेज के निदेशकों के लिए कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	10-11 जुलाई 1989 (दो दिन)	40	80
2.11	महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	18 सितंबर से 6 अक्तूबर 1989 (19 दिन)	39	741
2.12	अकादगिक स्टाफ कालेज की योजना और प्रबंध से संबंधित अभिविन्यास कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	11-12 दिसंबर 1989 (2 दिन)	48	96
2.13	स्वायत्त महाविद्यालयों के योजना और प्रबंध में संकाय का अभिविन्यास (क्वीन मेरी महाविद्यालय मद्रास) (उच्च शिक्षा एकक)	8-10 फरवरी 1990 (3 दिन)	225	675
2.14	स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना और प्रबंध पर एक कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	5-16 मार्च 1990 (12 दिन)	33	396
	6	50	397	2132

1989-90

1	2	3	4	5
	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा			
2.15	अनौपचारिक शिक्षा कार्यकमों की योजना और प्रबंध के लिए राज्य स्तर के अधिकारियों का अभिविन्यास कार्यक्रम (एस.एन.एफ.एकक)	24 अप्रैल-26 अप्रैल 1989 (तीन दिन)	23	69
2.16	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और प्रबंध के लिए राज्य स्तर के अधिकारियों का अभिविन्यास (एस.एन.एफ.एकक)	8-10 मई 1989 (तीन दिन)	19	57
2.17	प्रौढ़ शिक्षा परियोजना ए.आर.आई.एस.ई. के अनुदेशकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण-III) (एस.एन.एफ.एकक)	9-10 सितंबर 1989 (दो दिन)	36	72
2.18	प्रौढ़ शिक्षा की योजना और प्रबंध के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (एस.एन.एफ. एकक)	4 दिसंबर 1989 से 12 जनवरी 1990 (40 दिन)	37	1480
	4	48	115	1678
	(ब) विषय/सेक्टर			
	(अ) शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणक प्रयोग।संगणक का उपयोग			
2.19	शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणक प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम : लोट्स 1,2,3 का प्रयोग (योजना एकक)	21-30 जून 1989 (10 दिन)	21	210
2.20	शैक्षिक योजना में संगणक का प्रयोग लोट्स 1,2,3 का प्रयोग (हिमाचल प्रदेश)	21-25 अगस्त 1989 (5 दिन)	4	20
2.21	महाविद्यालयों में संगणक के प्रभावी उपयोग पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम (डी.ई.ई.टी. एकक)	19-23 फरवरी 1990 (5 दिन)	31	155
	3	20	56	385

1989-90

1	2	3	4	5
(आ) शैक्षिक योजना के लिए परिमाणात्मक तकनीक				
2.22	शैक्षिक योजना के लिए परिमाणात्मक तकनीक पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम (योजना एकक)	16-27 अक्तूबर 1989 (12 दिन)	37	444
	1	12	37	444
(इ) विस्तृत शैक्षिक योजना				
	भा.प्रशा.से. अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (दीर्घावधि शैक्षिक योजना) (योजना एकक)	15-20 जनवरी 1990 (6 दिन)	29	174
	1	6	29	174
(ई) व्यष्टि स्तरीय योजना				
2.24	प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उड़ीसा के क्षेत्र अधिकारियों के लिए विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टि स्तरीय योजना पर अभिविन्यास कार्यक्रम (एस.एन.एस.एकक)	27-30 नवंबर 1989 (चार दिन)	35	140
2.25	बिदीसा, मध्यप्रदेश में क्षेत्र अधिकारियों के लिए विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टि स्तरीय योजना पर अभिविन्यास कार्यक्रम	15-16 मार्च 1990 (2 दिन)	40	80
	2	6	75	220
(इ) वंचित वर्ग				
2.26	वंचित वर्ग के लिए शिक्षा में योजना और प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम (नीति एकक)	8-12 जनवरी 1990 (5 दिन)	20	100
	1	5	20	100
(ऊ) नीति कार्यान्वयन				
2.27	त्रिपुरा (अगरतल्ला) के शैक्षिक अधिकारियों के लिए विशेष कार्यान्वयन रणनीति के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम	15-19 मई 1989 (5 दिन)	39	195
	1	5	39	195

1989-90

1	2	3	4	5
3. कार्यशिविर/संगोष्ठी/सम्मेलन				
(अ) शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणक का प्रयोग				
3.1	महाविद्यालय में संगणक के प्रभावी उपयोग पर एक कार्यशिविर (डी.ई.ई.टी.एकक)	17-22 अप्रैल, 1989 (6 दिन)	30	180
3.2	महाविद्यालयों (डी.ई.ई.टी) में संगणक के प्रबंध पर एक कार्यशिविर	25-27 मई 1989 (तीन दिन)	15	45
3.3	दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों (डी.ई.ई.टी.एकक) के प्रबंध का संगणक प्रयोग पर एक कार्यशिविर	11-13 सितंबर 1989 (3 दिन)	17	51
	3	12	62	276
(आ) वंचित वर्ग				
3.4	अनु.जा/अनु.ज.जा. के लिए शिक्षा की योजना और प्रबंध पर एक कार्यशिविर डी.आई.ई.टी. के कार्मिकों के लिए मार्गदर्शिका का विकास (नीति एकक)	8-10 मई 1989 (3 दिन)	16	48
3.5	अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा प्रबंध किए गए संस्थानों का प्रबंध और सांस्थागत योजना पर राष्ट्रीय/संगोष्ठी/कार्यशिविर (नीति एकक)	29 मई से 2 जून 1989 (5 दिन)	5	25
3.6	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सहयोग से मुसलमानों द्वारा प्रबंध किए गए संस्थानों के प्राचार्य और प्रबंधकों की संगोष्ठी (नीति एकक)	5-8 जून 1989 (4 दिन)	17	68
3.7	पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए शैक्षिक तकनीक पर राष्ट्रीय कार्यशिविर (डी.ई.ई.टी.एकक)	23-25 अगस्त 1989 (3 दिन)	23	69
	4	15	61	210

1989-90

1	2	3	4	5
(इ) विद्यालय मानचित्रण				
3.8	अरुणाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए एम.आई.एस. और विद्यालय मानचित्रण पर अभिविन्यास कार्यशिविर (एस.एन.एस.एकक)	10-16 सितंबर 1989 (7 दिन)	48	336
3.9	विद्यालय मानचित्रण परियोजना पर कार्यशिविर (प्रथम तकनीकी कार्यशिविर) (एस.एन.एस.एकक)	18-22 दिसंवर 1989 (5 दिन)	7	35
3.10	विद्यालय मानचित्रण पर द्वितीय तकनीकी कार्यशिविर (एस.एन.एस.एकक)	5-7 मार्च 1990 (3 दिन)	4	12
	3	15	59	383
(ई) शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण				
3.11	शैक्षिक प्रशासन का द्वितीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर एक कार्यशिविर) (एस.एन.एस.एकक)	12-15 दिसंबर 1989 (4 दिन)	20	80
3.12	शैक्षिक योजना और प्रशासन की द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण पर दूसरा राष्ट्रीय तकनीकी कार्यशिविर (एस.एन.एस. एकक)	26-28 फरवरी 1990 (3 दिन)	4	12
	2	7	24	92
(उ)राष्ट्रीय साक्षरता अभियान				
3.13	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय (सूरत) के सहयोग से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर महाविद्यालय के प्रचार्यों की एक दिवसीय वैठक	22 अप्रैल, 1989 (एक दिन)	22	22
3.14	शिक्षा विभाग मानक संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत सामग्री और उपकरण के उत्पादन, वितरण और उपलब्धि पर कार्यशिविर (एस.एन.एस.एकक)	12-14 जून 1989 (3 दिन)	41	123

1989-90

1	2	3	4	5
3.15	ग्वालियर के अनौपचारिक शिक्षा अधिकारियों पर कार्यशिविर (कोप परियोजना ग्वालियर)	16-18 जून 1989 (3 दिन)	25	75
	3	7	88	220
(ऊ) शैक्षिक तकनीक और दूरवर्ती शिक्षा				
3.16	उच्च शिक्षा कार्यक्रम (डी.ई.ई.टी.) की शैक्षिक तकनीक पर कार्यशिविर	22-24 मई 1989 (3 दिन)	25	75
3.17	देश के दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों में नेटवर्क तैयार करने से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशिविर (डी.ई.ई.टी.एकक)	14-15 सितंबर 1989 (2 दिन)	19	38
	2	5	44	113
(ए) अन्य				
3.18	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सामान्य) के सहयोग से विकास कार्य पर हुए चार दशक (पुनरीक्षण सम्मेलन)	15-17 अप्रैल 1989 (3 दिन)	96	288
3.19	संस्थागत मूल्यानकन की योजना और प्रबंध पर संगोष्ठी/कार्यशिविर (उच्च शिक्षा एकक)	3-5 मई 1989 (3 दिन)	17	51
3.20	प्रारंभिक स्तर पर संस्थागत योजना के लिए जे.पी.नायक स्मारक संगोष्ठी/कार्यशिविर (पुणे) (एस.एन.एस. एकक)	23-25 जून 1989 (3 दिन)	39	117
3.21	जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासन की दो दिवसीय बैठक (एस.एन.एफ. एकक)	14-15 जुलाई 1989 (दो दिन)	39	78
3.22	शिक्षा के अर्थशास्त्र अनुसंधान में समस्या तथा प्राथमिकता पर राष्ट्रीय कार्यशिविर (योजना एकक)	21-22 जुलाई 1989 (2 दिन)	37	74
3.23	प्रयोगशाला-क्षेत्र अभिगम को अपनाने के लिए मार्गदर्शिका तैयार करने हेतु कार्यशिविर (नीति एकक)	21-24 अगस्त 1989 (4 दिन)	17	68

1989-90

1	2	3	4	5
3.24	शैक्षिक प्रबंध में प्रशिक्षकों पर कार्यशिविर (अंर्तराष्ट्रीय एकक)	11-16 सितंबर 1989 (6 दिन)	18	108
3.25	जिला स्तरीय प्रशासन की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान पर कार्यशिविर (नीति एकक)	15-16 सितंबर 1989 (दो दिन)	18	36
3.26	एन.आई.एस.टी.ए.डी. के सहयोग से उच्च शिक्षा संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान की योजना और प्रबंध पर संगोष्ठी (उच्च शिक्षा एकक)	18-20 सितंबर 1989 (3 दिन)	37	111
3.27	शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय विषमताओं पर एक राष्ट्रीय कार्यशिविर (एस.एन.एस.एकक)	25-27 सितंबर 1989 (3 दिन)	41	123
3.28	संस्था अध्यक्ष के लिए कृतिक विश्लेषण पर कार्यशिविर (डी.ई.ई.टी. एकक)	25-28 सितंबर 1989 (4 दिन)	20	80
3.29	जिला शिक्षा अधिकारियों का कृतिक विश्लेषण: प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान पर कार्यशिविर (नीति एकक)	10-12 नवंबर 1989 (3 दिन)	19	57
3.30	शैक्षिक आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण पर कार्यशिविर (मानचित्रण कक्ष)	4-8 दिसंबर 1989 (5 दिन)	3	15
3.31	माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर की भूमिका तथा उनकी प्रतिष्ठा स्तर में वृद्धि पर कार्यशिविर (एस.न.एफ.एकक)	28-29 दिसंबर 1989 (दो दिन)	24	48
	14	45	425	1254
	60*	715	1824*	19726

*इनमें जारी एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल नहीं किए गए हैं।
**जारी डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रतिभागी भी शामिल किए गए हैं।

1989-90

अनुबंध-III

प्रशिक्षण सामग्रियों की सूची

- भारत में बाल श्रम : शैक्षिक विकास के सांख्यिकीय आंकड़े
- मार्गदर्शिका प्रयोगशाला क्षेत्र
- असमानताएं उन्मूलन के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध पर माड्यूल
- अनु.जा. और अनु.ज.जा. की शिक्षा के लिए योजना और प्रबंध पर माड्यूल
- भारत में शैक्षिक योजना का विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
- गुणवत्ता के लिए शिक्षा : अलग-थलग पड़े पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का सार्वजनीकरण
- शिक्षा में सुरक्षात्मक भेदभाव और क्षेत्रीय विषमताएं : भारतीय जन जातियों का एक अध्ययन
- अल्पसंख्यकों की शिक्षा
- विकलांगों की शिक्षा और पुनर्वास में असंतुलन
- शिक्षा के प्रतिदर्शों की प्रामाणिकता और परीक्षणः प्राविधिक समीक्षा
- शिक्षा और अर्थशास्त्र के संतुलित अधिकतम विकास का एक प्रतिदर्श
- भारत में साक्षरता विकास के स्रोत : घटक में अपघटन का एक मॉडल
- सांस्थानिक योजना पर केस अध्ययननों के 11 सारांश-जे.पी. नायक स्मृति व्याढयान माला
- प्रादेशिक स्तर पर जनसंख्या प्रक्षेपण की तकनीक
- शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक निष्पादन और विद्यालय छोड़ने की दर का आकलन : विद्यालय छोड़ने की विभिन्न स्थिति का एक अध्ययन
- नागालैंड की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में अंतर-जनपदीय विषमताएं
- विद्यालय छोड़ने से पूर्व का शैक्षिक निष्पादन और विद्यालय छोड़ने के बाद की आमदनी संबंधी विवरण : विद्यालय छोड़ने वालों के विभिन्न वर्गों का एक तुलनात्मक अध्ययन
- भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर साक्षरता का प्रभाव
- प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने के रूप में अपव्यय की समस्याएं
- शैक्षिक संस्थानों के स्थानिक निर्धारण का एक मॉडल
- कालेज शिक्षा की इकाई लागत
- शैक्षिक स्थितिः उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में अंतर जनपदीय विषमताएं
- एक अंतर-उद्योग माडॅल : शिक्षा पर आर्थिक प्रभाव
- जनसंख्या और शिक्षा की सामाजिक मांग
- योजना : आर्थिक, शैक्षिक, मानवशक्ति संकल्पनाएं और अंतर संबंध
- योजना के प्रकार : समष्टिगत, व्यष्टिगत, और संस्थागत
- शैक्षिक योजना के लिए सामाजिक मांगः अभिगम संभाविता का सिद्धांत
- शैक्षिक परियोजनाओं के मूल्यांकन की तकनीक और मॉडल
- शैक्षिक प्रणाली का गणितीय मॉडल
- शैक्षिक योजना के अभिगम
- छात्र प्रवाह और स्टाक संकेतक
- संगणक-एक परिचय और शिक्षा में उसका अनुप्रयोग
- साक्षरता और सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा का निदान और योजना माडॅल
- प्रक्षेपण तकनीक : नामांकन
- सन् 2001 ई० में राजस्थान की आबादी
- शैषिक योजना के परिणामात्मक पक्ष पर कार्यशिविर
- आंकलन के नियम
- असमानताओं की माप
- वापसी अभिगम की दर

1989-90

- आंकड़ा : प्रकृति और क्षेत्र
- जी.एल.एस./लाजिट विश्लेषण
- केंद्रीय प्रवृत्ति की माप
- अकादमिक स्टाफ काालेज के कार्यक्रमों की प्रभाविता: अकादमिक घटकों का एक विश्लेषण
- उच्च शिक्षा में योजना और प्रबंध की पाठ्यचर्या–एक माड्यूल
- अनुसूचित जातियों/जन जातियों की शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित योजना और प्रबंध मुद्दे पर अनुसंधान आलेख
- आश्रम विद्यालय में शिक्षा पर एक अनियत पत्र आंध्र प्रदेश का केस अध्ययन

जि.शि.अ.के दसवें राष्ट्रीय डिप्लोमा के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची (1 नवंबर 1989 से 30 अप्रैल 1990)

- आंध्रप्रदेश में जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया : जि.शि.अ.की भूमिका
- पढ़ने के साथ कमाई करने की योजना : मध्यप्रदेश में एक जिले का आलोचनात्मक अध्ययन
- मणिपुर में अवर-स्नातक कालेजों में अध्यापकों के कार्य-दर्शन और छात्रों के निष्पादन के संबंध का एक अध्ययन
- मणिपुर में राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा की योजना का अध्ययन
- जिला कड़प्पा, आंध्रप्रदेश में प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का विश्लेषण
- कक्षा IXके लिए इ.एल.टी. पैकेज का एक अध्ययन
- दिल्ली के दक्षिण जिले में कार्य अनुभव के कार्यान्वयन में अन्वेषण की समस्याओं का एक अध्ययन
- नेतृत्व शैली और प्रभाविता .: असम के नलबाड़ी जिले के परिषदीय मिडिल स्कूलों का एक अध्ययन
- कलकत्ता जनपद में प्रारंभिक स्तर पर न्यायालय मामालों का एक अध्ययन
- नागालैंड में ग्राम शिक्षा समिति का संविधान और प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति में उसकी जिम्मेवारियां–मोकोचुंग जिले का एक अध्ययन
- हिमाचल प्रदेश के एस.डी.ए.आर. मण्डी जिले में उप-प्रखंडीय स्तर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय निरीक्षण और सर्वेक्षण की प्रभाविता का अध्ययन
- कर्नाटक में जिला स्तर के शैक्षिक प्रशासकों के दाब गतिकी का एक आलोचनात्मक अध्ययन
- विकसित राज्यों में शैक्षिक विकास : कट्टपना शैक्षिक जनपद का एक केस अध्ययन
- मेघालय के ईस्ट हिल जनपद में माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की प्रशिक्षण जरुरतों की पहचान
- कर्नाटक राज्य के नगर जनपद बैंगलौर के अल्प संख्यक भाषाओं के प्राईमरी और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन
- बीकानेर जिले के बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन
- असम के सोनितपुर जिले में माध्यमिक विद्यालयों के प्राचायों के प्रशिक्षण की जरुरतों का एक निदानात्मक अध्ययन
- नेतृत्व शैली और विद्यालय प्रभाविता : तमिलनाडु के वेल्लूर शैक्षिक जनपद के उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं के प्राचार्यों का एक अध्ययन
- शांति के प्रति छात्रों के मनोभावों पर प्रभाव डालने वाले तत्व
- उत्तर प्रदेश के पौढ़ी गढ़वाल जिले की अनौपचारिक शिक्षा की लागत का एक विश्लेषण

पांचवां अंतराष्ट्रीय डिप्लोमा की परियोजना रिपोर्ट
(16 जनवरी-18 जुलाई 1989)

- अफगानिस्तान में शिक्षा प्रणाली
- अफगानिस्तान में साक्षरता या अनौपचारिक शिक्षा
- बंगलादेश में माध्यमिक शिक्षा : एक निदानात्मक अध्ययन
- क्यूबा में उच्च शिक्षा में वित्तीय संसाधनों की योजना का अध्ययन : निर्धारण, नियंत्रण और विश्लेषण
- शैक्षिक निरीक्षण की भूमिका : इथोपिया के शिक्षा मंत्रालय का एक नवाचारी कार्यक्रम
- इथोपिया में विद्यालय के स्थानिक वितरण और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में क्षेत्रीय विषमता
- घाना में शिक्षा का वित्त

1989-90

- घाना के पश्चिमी क्षेत्र तुमू अपर के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने की दर पर नवाचार
- वर्ष 1988 में जार्डन के प्रीपरेटरी स्टेट में अधिगम के क्षेत्र में परिमाणात्मक विकास (विस्तार)
- प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्गठन
- योजना और उत्पादन
- मालवी के शैक्षिक विकास में विद्यालय समितियों की भूमिका का अध्ययन : प्राथमिक स्तर पर
- डेज़ा जिले के विशेष संदर्भ में मालावी प्राथमिक विद्यालय में अनुपस्थित के कारणों और प्रभावों का एक अनुसंधानात्मक अध्ययन
- जोवा के विशेष संदर्भ में अनुपस्थिति के कारणों का एक अध्ययन
- नेपाल में प्रबंध द्वारा शैक्षिक विकास
- नाइजीरिया के अकवा-इबोम राज्य में प्राचार्यों द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में शुरू किया गया प्रारंभिक प्रौद्योगिकी विषय की समस्या का विश्लेषण
- नाइजीरिया में प्रशासनिक प्रभाविता पर असर डालने वाले कारक
- शैक्षिक सुविधाओं के महत्तम प्रयोग के स्तर और मानदंडों का एक अध्ययन
- सीरिया में अध्यापन प्रणाली के निर्माण की समस्याएं
- श्रीलंका में त्रिंकोमाली के इस्ट क्लस्टर में विद्यालय प्रभावशालिता और स्टाफ मूल्यांकन का एक अध्ययन
- श्रीलंका में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों का एक अध्ययन
- समूह प्रणाली : श्रीलंका में विद्यालय प्रणाली शैक्षिक योजना और प्रशासन में सुधार के लिए नवाचार
- श्रीलंका के कैंडी जिले के विशेष संदर्भ में लोकप्रिय जिले की भूमिका
- लोकप्रिय प्राचार्यों की प्रभावी भूमिका
- श्रीलंका में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सुधार के लिए विकास की रणनीतियां
- लोकप्रिय प्राचार्यों की नेतृत्वकारी भूमिका
- श्रीलका के हगगाना जिले में विद्यालय की गुणवत्ता के सुधार में जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका
- दो पाली के अवर माध्यमिक विद्यालयों में विपालीकरण और 3 वर्ष से 5 वर्ष के विद्यालयी शिक्षा में उनका रूपांतरण
- प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा के संक्रमण काल में सफलता के वावजूद विद्यालय छोड़ने की दर का एक अध्ययन : उगांडा का एक केस अध्ययन
- उगांडा के लुमेरो जिला के विशेष संदर्भ में महिला कार्यक्रमों का मूल्यांकन
- ज़िम्बाबवे में शिक्षा क्षेत्र के विशेष संदर्भ में मानव शक्ति की योजना और भविष्यवाणी

1989-90

अनुबंध IV

संकाय का अकादमिक योगदान (1989-90)

पुस्तकें

एन.एम. भागिया और सुश्री सुषमा भागिया ''भारत तथा अन्य विकासशील देशों में शैक्षिक प्रशासन'' 1990

जय श्री जलाली

फ्रम वैकल टू गेंजस, पाठ का नाम 'वी लोस्ट अवर हार्टस' संपादक प्रो. ए. शान्तुरोव (शिक्षा) मास्को 1989.

एम. मुखोपाध्याय

''शैक्षिक तकनीक : वार्षिक पुस्तक'', 1988 नई दिल्ली-ए.आई.ए.ई.टी, 1989.

''शैक्षिक तकनीक : चुनौतीपूर्ण मुद्दे'' नई दिल्ली: स्टेरलिंग प्रकाशन, 1989.

''अध्यापक शिक्षा का प्रबंध''-एल.सी. सिंह (शिक्षा) अध्यापक शिक्षा पर संसाधन पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली (प्रेस में)

''शैक्षिक प्रबंध में अनुसंधान-एक प्रवृत्ति विश्लेषण''-एम.बी.बुक (शिक्षा) शिक्षा में अनुसंधान का चौथा सर्वेक्षण (प्रेस में)

''दूरवर्ती शिक्षा में कार्मिकों को तैयार करना''-के.एस. राव (शिक्षा), ''खुली अधिगम प्रणाली'' नई दिल्ली' : लैंसर, 1989

''दूरवर्ती शिक्षा : एक स्वॉट विश्लेषण''-एम. मुखोपाध्याय शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी : वार्षिक पुस्तक, 1988, (शिक्षा और समाज में इसे भारत में दूरवर्ती शिक्षा के नाम से निकाला गया) नई दिल्ली : ए. आई. ए. ई. टी., 1989.

''शैक्षिक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान'' : योजना और प्रबन्ध का निहितार्थ – एम. मुखोपाध्याय (शिक्षा) शैक्षिक तकनीक : वार्षिक पुस्तक 1988, नई दिल्ली : ए. आई. ए. ई. टी. 1989

''राष्ट्रीय शिक्षा'' नीति और शैक्षिक प्रौद्योगिकी'' – एम. मुखोपाध्याय (शिक्षा), शैक्षिक प्रौद्योगिकी : चुनौती पूर्ण मुद्दे, स्टेलिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1990.

''शैक्षिक प्रौद्योगिकी की योजना और प्रबन्ध'' – मुखोपाध्याय एम. (शिक्षा) शैक्षिक प्रौद्योगिकी : चुनौती पूर्ण मुद्दे स्टेलिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1990.

एस. सी. नूना

''भारत में राजनीतिक गतिविधियों का स्थानिक संविभाजन'' संसदीय चुनाव संकल्पना 1989 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य

एन. वी. वर्गीस

आई. आई. ई. पी. पेरिस द्वारा प्रकाशित भारत में शिक्षा और श्रम बाजार, 1989.

कैमरून में तेल उद्योग का तकनीकी विकास और शैक्षिक योजना में इसका निहितार्थ (बी. सन्याल ई. टी. ए. एल.) आई. आई. ई. पी. पेरिस (शीघ्र प्रकाश्य)

1989-90

अनुसंधान पत्र/प्रकाशित लेख

एन. एम. भागिया

भारत में महाविद्यालयों के प्राचार्यो की भूमिका की कारगुजारी, यूनिवर्सिटी न्यूज 17 अप्रैल 1989.

शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विकास, खंड एजुकेशनल हेराल्ड III सं. 4. 1989.

आरिफ हसन

''सामाजिक व्यवहार की समता और न्याय'' थर्ड वर्ल्ड इंपैक्ट – खंड I, जनवरी 1990. भारत की प्रारंभिक शिक्षा - नए दृष्टिकोण की आवश्यकता, थर्ड वर्ल्ड इंपैक्ट खंडI सं. 2 फरवरी 1990.

''संगठनात्मक संस्कृति'' थर्ड वर्ल्ड इंपैक्ट खंड I सं. 3, फरवरी 1990.

''नेतृत्वकारी गुण और संगठनात्मक परिणाम'', जर्नल ऑफ सोशल एण्ड इकोनागिक स्टडीज नई शंखला नई दिल्ली

ए. मंगलागिरि

समीक्षा – ''हैरस्तोरी'' हिंदुस्तान टाइम्स फरवरी 1990.

''बुक स्केन आन वुमन स्टडीज'' 4 मार्च 1990, श्रृंखला लेख 1989-90 हिंदुस्तान टाइम्स.

ए. मैथ्यू

'विद्यालय स्तर पर अध्यापकों का प्रबन्ध : उभरते हुए नीति परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना और प्रशासन, विशेषांक, खंड 3, सं. 3. और 4. 1989.

''शिक्षा मंत्रालय का संगठनात्मक इतिहासः विकास के चार दशक : पुनरीक्षण सम्मेलन में प्रस्तुत आलेख नई दिल्ली, 15–17 अप्रैल 1989.

एम. मुखोपाध्याय

''शिक्षा में इलेक्ट्रोनिक माध्यम की भूमिका'' विदुरा, जुलाई 1989.

शैक्षिक प्रौद्योगिकी में भारतीय अनुसंधान मीडिया एण्ड टेक्नॉलाजी फार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिल्द। सं. 4, जुलाई 1989

''कार्मिक विकास कर्त्ता के रूप में प्राचार्य'' इंडियन जर्नल आफ स्कूल मैनेजमेंट, जुलाई 1989.

''शिक्षा के विकास में चार दशक'' एजुकेशनल टेक्नॉलाजी खंड। सं. 11 अप्रैल 1989.

''पत्राचार द्वारा किए गए बी. एड. को अमान्य मानना : अपरिपक्व कदम'' एजुकेशनल टैक्नालाजी खंड 1 सं. 12 मई 1989.

''शैक्षिक नीति के कार्यान्वियन पर चिंता'' एजुकेशन टैक्नालोजी खंड 2 सं. 2 जुलाई 1989.

''दूरवर्ती शिक्षा : एक सिंहावलोकन, एजुकेशनल टैक्नोलाजी खंड 2 सं. 4 और 5 सितंवर–अक्टूबर 1989.

''दूरवर्ती शिक्षा : अनिश्चित भविष्य'' नेशनल हेराल्ड, 1989

'' दूरवर्ती शिक्षा'', पेट्रियट, 11 सितम्बर 1989.

''कम लागत पी. सी. : संगणक शिक्षा के लिए एक वरदान'' एजुकेशनल टैक्नोलाजी खंड 2 और सं. 6, नवंवर 1989

''नए संदर्भ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी'' एजुकेशनल टैक्नॉलाजी, खंड 2 सं. 8 जनवरी 1990.

''शिक्षा की केन्द्रीय योजना का अंतरण'' एजुकेशनल टैक्नॉलाजी, खंड 2 सं. 9 फरवरी 1990.

''सभी के लिए शिक्षा : एक नया कार्य : एजुकेशनल टैक्नॉलाजी, खंड 2 सं. 10 मार्च 1990.

1989-90

''दूरवर्ती शिक्षा का नेटवर्क'' इंडियन जर्नल आफ डिस्टैंस एजुकेशन, खंड III 1990.

''शिक्षा में भर्ती : आधुनिकीकरण की आवश्यकता'', शैक्षिक योजना और प्रशासन जर्नल, 1990.

''प्राप्त हो सकने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करना और उसी दिशा में कार्य करना'' द हिन्दू जनवरी 30 1990.

सुदेश मुखोपाध्याय

''आई. ई. डी. सी. मिमियो 1990 के लिए विशेष रूप से अध्यापन क्षमताओं की पहचान करना (रा. शै. अ. प्र. प. द्वारा अनुदान प्राप्त ।

एस. सी. नूना

''भारत में रहने वाले शहर के निवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा व्यवस्था : समाजशास्त्र के कुछ मुद्दे'' स एम. शाजी फुड सीस्टम आफ द वर्ल्ड,रामोट प्रकाशन, 1989 (ए. अहमद के साथ)

''शिक्षा स्वास्थ्य संबंध : एक विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य'' शैक्षिक योजना और प्रशासन जर्नल खंड 3 सं. 1 और 2 (अनिता नूना के साथ)

कुसुम के. प्रेमी

''प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण और बाल श्रम'' मेनपावर जर्नलखंड XIII सं. 2 अक्टूबर 1989.

''समता के लिए शिक्षा : पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा'' न्यू फ्रांटियर इन एजुकेशन खंड XX सं. 1 जनवरी – मार्च 1990.

के सुधाराव

''स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना और प्रबन्ध में नाजुक मसले'', नीपा 1989

''उत्तरदायित्व और प्रत्यायन : अधिकार क्षेत्र और आयाम'' नीपा 1989.

''कक्षा 12 के स्तर पर व्यावसायीकरण : कर्नाटक पर एक केस अध्ययन, परिवर्तन का प्रबंध'' नीपा 1989.

''स्वायत्त महाविद्यालयों का प्रबंध : 42 स्वायत्त महाविद्यालयों के केस अध्ययन का विश्लेषण

के. सुजाता

''विद्यालय स्तर पर भारत मे दूरवर्ती शिक्षा'' न्यू फ्रांटियर इन एजुकेशन खंड XIX सं. 1 1989.

''जनजातियों में शिक्षा – विकास में असमानताए ''' द राजस्थान बोर्ड जर्नल आफ एजुकेशन खंड XXV, सं. 2 अप्रैल–जून 1989.

''दूरवर्ती शिक्षा'' नेशनल हेराल्ड, 1989.

शैक्षिक तकनीक – तीसरी दुनिया के अनुभव'' शैक्षिक प्रौद्योगिकी वार्षिक पुस्तक 1989, ए. आई. ए. ई. टी. नई दिल्ली 1989.

''पिछड़ी जनजातियों का अध्यापन, – एम. मुखोपाध्याय स. शैक्षिक प्रौद्योगिकी चुनौतीपूर्ण मुद्दे'' स्टेरलिंग पब्लिशर्स.

''आश्रम विद्यालयों में शिक्षा – अदिलाबाद का केस'' जर्नल आफ एजुकेशन एण्ड सोशल चेंजेज खंड – III सं. 1, अप्रैल–जून 1989.

''अध्यापक प्रशिक्षण के लिए दूरवर्ती शिक्षा'' शैक्षिक योजना और प्रशासन जर्नल खंड 2, सं. 3 तथा 4, दूरवर्ती शिक्षा विशेषांक

रंजना श्रीवास्तव

''दीर्घावधि शैक्षिक योजना : राज्य स्तर की योजना और प्रशासन'' के निहितार्थ द एजुकेशन क्वार्टरली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ग्रीष्म 1988.

1989-90

जे. बी. जी. तिलक

''भारत में शिक्षा का राजनीतिक अर्थशास्त्र'', (बफैलो) न्यूयार्क के स्टेट ओरियंट मे प्रकाशित 1990.

''शैक्षिक तकनीक अर्थशास्त्र के कुछ पहलू'' एजुकेशनल टेक्नालाजी नई दिल्ली 1990.

''भारत में शिक्षा और मूल आवश्यकताए '' मानव संसाधन विकास, बंबई हिमालय, 1990.

एन. वी. वर्गीस

''परिवर्तन के तौर पर सुधार : भारत में नई शिक्षा नीति'' (विकास संयाल के साथ एजुकेशन कम्पेयर, सं. 41, 1989 (फ्रेंच में)

''उच्च शिक्षा और रोजगाार : कुछ प्रमुख साक्ष्य तथा उसके निहितार्थ'', पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन खंड 5, सं. 2, 1989.

''समाज विज्ञान में शास्त्रीय और अंतरशास्त्रीयता'' जर्नल आफ एजुकेशन एण्ड सोशल चेंजेज खंड 3 सं. 2 1989.

''शैक्षिक तकनीक अर्थशास्त्र के कुछ प्रमुख पहलू'' (जे. बी. जी. तिलक के साथ) एजुकेशनल टेक्नालाजी ए. आई. ए. ई. टी. नई दिल्ली जनवरी 1990.

''उच्च शिक्षा में प्रभावी प्रबन्ध का सुधार : साहित्य का पुनरीक्षण'' आई. आई. ई. पी. पेरिस 1989 (मिमियो)

जर्नल संपादन

एम. मुखोपाध्याय

''मानव संसाधन विकास के लिए संचार माध्यम प्रौद्योगिकी'' नई दिल्ली ए. आई. ए. ई. टी. – अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर 1989 तथा जनवरी 1990 के चार अंक

''एजुकेशनल टैक्नालाजी'' (शिक्षा की मासिक समाचार पत्रिका) – 12 अंक

''शैक्षिक योजना और प्रशासन, जर्नल – दूरवर्ती शिक्षा विशेषांक जुलाई और अक्तूबर अंक 1989, नई दिल्ली, नीपा 1989.

पुस्तक समीक्षा

एन. वी. वर्गीस

''शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली'' (लार्स माहिक के साथ पुस्तक समीक्षा

इंटरनेशनल रिव्यू आफ एजुकेशन खंड 35 सं. 3, 1989

''उच्च शिक्षा और रोजगार'' (पुस्तक समीक्षा) एजुकेशन पालिसी खंड 3 सं. 3 1989

''शिक्षा और मानव संसाधन विकास : क्षेत्रीय संदर्भ मे उभरती हुई चुनौतियां (पुस्तक समीक्षा) जर्नल आफ एजुकेशन एण्ड सोशल चेंज, खंड 3, से 4 1990

एस. एम. आई. ए. जैदी

''वुमंस ओप्रेशन – मैन रेस्पोंसिबिल–सोशियल चेंज-इंदु प्रकाश सिंह खंड 18 सं. 3, सितंबर 1988.

चेजिंग स्ट्रेटस आफ ऐजुकेट्ड़ वर्किंग वुमन'' – सी. आर. रेड्डी – जर्नल आफ इंडियन एजुकेशन खंड XIV सं. 4 नवंबर, 1988

सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशिविर/अन्य निकायों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

एन. एम. भागिया

महाविद्यालयों में अध्यापक की भूमिका और महाविद्यालयों में संगठनात्मक संरचना पटना विश्वविद्यालय, पटना में इन्होंने एक व्याख्यान दिया। (16–17 अगस्त 1989)

1989-90

केन्द्रीय विद्यालय माऊंट अबु में ''विद्यालय के प्रबंध'' पर इन्होंने एक व्याख्यान दिया (23 नवंबर 1989). अकादमिक स्टाफ कालेज पटना विश्वविद्यालय पटना में महाविद्यालयों की संगठनात्मक संरचना और महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं की भूमिका'' पर एक व्याख्यान दिया (4–5 दिसम्बर 1989)

सुषमा, भागिया

''महाविद्यालयों में अध्यापन की तकनीक और पद्धति तथा महाविद्यालयों की संगठनात्मक संरचना पर (अकादमिक स्टाफ कालेज पटना विश्वविद्यालय, पटना में व्याख्यान दिया । (14–16 अगस्त 1989)

''भारत और तीसरी दुनिया के देशों में अनौपचारिक और प्रौढ़–शिक्षा का प्रबंध'' के विषय पर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल में व्याख्यान दिया (12 सितंबर 1989)।

''निर्णय लेना'' नामक विषय पर केन्द्रीय विद्यालय, माऊँट आवु में व्याख्यान दिया (23 नवंबर 1989)

सत्यभूषण

अकादमिक स्टाफ कालेज, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित एक अभिविन्यास कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित किया (30 जून 1989)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''महिलाओं के लिए नीति कार्यक्रम में शैक्षिक प्रशासक और योजनाकारों की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान दिया (26 सितंबर 1989)

जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू में विस्तृत व्याख्यान दिया (24–28 जनवरी 1990)।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति/अनु. जन. जा. की लड़कियों के संदर्भ में आयोजित शिक्षा की राष्ट्रीय कार्यशिविर योजना और प्रबंध के पक्ष पर एक व्याख्यान दिया (24 मार्च 1990)

आर. गोविंद

दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यावसायिक उच्च शिक्षा विकास केन्द्र में ''संरचना अभिगम – शिक्षा का प्रसार'' विषय पर एक व्याख्यान दिया । (16 गई 1989)

दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यावसायिक उच्च शिक्षा विकास केंद्र में ''ज्ञान का प्रसार'' विषय पर इन्होंने एक व्याख्यान दिया (8 जुलाई 1989)

आई. आई. ई. पी. पेरिस के श्री ता. ना. यो के साथ मिलकर ''बेसिक शिक्षा सेवा की गुणवत्ता'' पर आयोजित एक पुनरीक्षण कार्यशिविर में भाग लिया। (16–18 अक्टूबर 1989)

नई दिल्ली में साक्षरता कार्मिकों के प्रशिक्षण पर आयोजित यूनेस्को उप–क्षेत्रीय कार्यशिविर में संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभाई (15–29 नवंबर 1989)

शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी ''मूल अधिगम संबंधी आवश्यकताएं और उपलब्धि स्तर'' में भाग लिया। (19–20 दिसंबर 1989)

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार और ईष्टर्न विल्ली प्रकाशन द्वारा नव–साक्षरों के लिए सामग्री विकास पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशिविर में भाग लिया (22 दिसंबर 1989)

विकास अध्ययन संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित कार्यशिविर ''शिक्षा कर्मी परियोजना – एक मूल्यांकन'' में भाग लिया (12–13 जनवरी 1990)।

भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे द्वारा सन् 2000 तक सभी के लिए शिक्षा पर आयोजित जे. पी. नायक संगोष्ठी में भाग लिया (2–4 फरवरी 1990)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा (डी. आई. ई. टी.) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्मिकों

1989-90

के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला संसाधन एकक और शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एक व्याख्यान दिया।

आरिफ हसन

नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली द्वारा नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभायी। (5 फरवरी 1990)

जया इंदिरेसन

ऐशियाई अनुसंधान और विकास संगठन, गौहाटी द्वारा कार्यशिविर में ''प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण'' पर आयोजित संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभायी (22–24 जून 1989)

ऐशियाई अनुसंधान और विकास संगठन गौहाटी द्वारा ''विस्तार शिक्षा में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के क्षेत्र परीक्षण'' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति की भूगिका निभायी। (8–9 जुलाई 1989)

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली में ''ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण'' पर आयोजित कार्यशिविर में संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभायी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित था (6 सितंबर 1989)

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी ''मूल्यांकन का प्रत्यायन'' में भाग लिया। (6–7 नवंबर 1989)

नवोदय विद्यालय समिति के स्वॉट विश्लेषण में भाग लिया, नई दिल्ली (6–9 नवंबर 1989)

स्वायत्त स्थिति के संदर्भ में अध्यापकों के बोध का अध्ययन करने के लिए क्वीन मेरी कालेज, मद्रास में ''स्वॉट विश्लेषण'' अभ्यास किया। (4–5 दिसम्बर 1989)

भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी द्वारा आयोजित तथा जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए सम्मेलन ''शिक्षा और विकास'' में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया और छात्र विकास पर एक आलेख प्रस्तुत किया (26–28 दिसंबर 1989)

नवोदय विद्यालय प्रशिक्षण केन्द्र में ''स्वॉट विश्लेषण'' पर एक व्याख्यान दिया और इसके उपरान्त नवोदय विद्यालय के प्राचार्यों के लिए एक अभ्यास कार्यक्रम की भी आयोजना की गई (1 जनवरी 1990)

गृहविज्ञान भानुबेन गहेंद्र मनावती महाविद्यालय, बंबई में ''छात्र विकास में अध्यापन की भूमिका'' पर एक व्याख्यान दिया (बंबई – 12 जनवरी 1990)।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित संगोष्ठी ''उच्च शिक्षा मे अभिजात्यवाद और आरक्षण नीति'' में भाग लिया, नई दिल्ली (31 जनवरी 1990)

नवोदय विद्यालय समिति में आयोजित संगोष्ठी ''राष्ट्रीय एकता में नवोदय विद्यालय समिति की भूमिका'' में भाग लिया (15–16 मार्च 1990)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशिविर अनु. जा./अनु. जन. जा. की लड़कियों के लिए शिक्षा : 1990 के लिए परिलक्ष्य में भाग लिया। (26-27 मार्च, 1990)

एम. एम. कपूर

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्मिकों तथा प्राचार्यों के प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने हेतु परिचर्चा के लिए रा. शै. प. परिषद द्वारा आयोजित कार्यशिविर में संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभायी (26–28 अप्रैल 1989)।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली में ''संस्थागत योजना तथा प्रबन्ध और विद्यालय परिसर'' पर एक व्याख्यान दिया। (3 मई 1989)

राज्य शिक्षा संस्थान दिल्ली में ''संस्थागत खंड और प्रबंध'' पर एक व्याख्यान दिया। (8 मई 1989)

शिक्षा विभाग उदयपुर, राजस्थान द्वारा आयोजित शिक्षा संस्थाओं के प्राचार्यों के सम्मेलन में ''संस्थागत योजना और मूल्यांकन'' पर एक व्याख्यान (5 फरवरी 1990)

1989-90

उदयपुर के जिला शैक्षिक अनुसंधान सनगठन की बैठक में ''संस्थागत योजना और मूल्यांकन की आवश्यकता'' पर एक व्याख्यान दिया (6 फरवरी 1990)

दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों की बैठक में ''संस्थागत योजना और कार्यान्वयन रणनीतियों'' पर एक व्याख्यान (9 मार्च 1990) को दिया।

अंजना मंगलागिरी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के महिला कक्ष द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ''महिला और विकास'' पर व्याख्यान दिया। (16 मई 1989)

रा. शै. अनु. और प्रशि. परि. के महिला कक्ष द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिला और जनसंचार माध्यम पर एक व्याख्यान दिया (29 मई 1989)

भारतोय शिक्षा तुलना सोसाइटी नई दिल्ली के पांचवें सम्मेलन में ''शैक्षिक विकास की संरचना और संदर्भ : एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य'' पर एक आलेख प्रस्तुत किया। (26–28 दिसंबर 1989)

पिछड़ी जनजाति के महिलाओं की विकास से संबंधित आवश्यकताओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशिविर में ''आधुनिकीकरण और विकास का पिछड़ी महिलाओं पर प्रभाव'' पर एक आलेख प्रस्तुत किया। एन. आई. पी. सी. सी. डी. गोपालपुर, उड़ीसा (27–29 मार्च 1990)

ए. मैथ्यू

''जिला शिक्षा अधिकारियों का कृतिक विश्लेषण : मध्य प्रदेश पर एक केस अध्ययन'' पर आयोजित कार्यक्रम में समन्वयक की भूमिका अदा की। (इंदौर)

अरूण मेहता

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''शैक्षिक योजना और संगणक के विनियोजन'' पर एक व्याख्यान दिया। नई दिल्ली (28 अगस्त 1989)

एम. मुखोपाध्याय

महिलाओं के विकास (व्यष्टि स्तरीय अनुभव) पर नेपाल के प्रतिनिधियों को संवोधित किया।

कार्मिक विभाग, भारत सरकार, बंबई में ''साक्षात्कार कौशल'' पर एक कार्यशिविर आयोजित किया। (2–4 मई 1989)

ए. आई. ए. ई. टी. नई दिल्ली द्वारा आयोजित बैठक में ''सी. ए. आई. सोफ्टवेयर विकास कार्यक्रम की लिपि से सबंधित मूलभूत नियम'' पर एक व्याख्यान दिया। (नई दिल्ली – 24 मई 1989)

जिला शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (आगरा) द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी ''अध्यापक शिक्षा और शैक्षिक तकनीक'' का उद्घाटन किया। (26 मई 1989)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा ई. टी. टी. डी. सी. (भारत सरकार) द्वारा ''शैक्षिक सोफ्टवेयर सूचना प्रणाली के विकास'' पर आयोजित परामर्शकारी बैठक में भाग लिया। (29 मई 1989)

कार्मिक विभाग, भारत सरकार शिलौंग के लिए साक्षात्कार कौशल पर एक कार्यशिविर का आयोजन किया। (23–24 अक्टूबर 1989)

त्रिवेंद्रम मे शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर हुए ऐशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में ''शैक्षिक तकनीक: विकास की दुविधा'' पर एक अध्यक्षीय संभाषण दिया (14 नवंबर 1990)

कार्मिक विभाग, पणजी, गोवा में ''साक्षात्कार कौशल'' पर एक कार्यशिविर (1–3 फरवरी 1990) का आयोजन किया।

एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय में दूरवर्ती शिक्षा सामग्री के विकास पर हुए राष्ट्रीय कार्यशिविर में मुढढप व्याख्यान दिया। (19 मार्च 1990)

1989-90

सुदेश मुखोपाध्याय

राष्ट्रीय नेत्र विकलांग संस्थान, देहरादून द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विकलांग बच्चों की शिक्षा की योजना और प्रबंध पर एक व्याख्यान दिया (27 अप्रैल 1989)

राष्ट्रीय नेत्र विकलांग संस्थान, देहरादून द्वारा उत्तरी राज्यों के अंध पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्षों की विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आई. ई. डी. सी. के शैक्षिक प्रशासकों के लिए आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभायी (29–30 अगस्त 1989)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, नई दिल्ली में यू. एन. आई. सी. ई. एफ. द्वारा सहयोग प्राप्त परियोजना के परियोजना अधिकारियों के अभिविन्यास के लिए आयोजित कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभायी (30–31 अगस्त 1989)।

विकलांग बच्चों के लिए गुड़ियों के चुनाव में संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभायी। (7-8 नवंबर 1989)

कमजोर दृष्टि वाले बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से अध्यापकों के लिए हैंडबुक के निर्माण के लिए राष्ट्रीय दृश्य विकलांग संस्थान में आयोजित कार्यशिविर में संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभायी (3 फरवरी 1990)

नई दिल्ली में, विकलांगों की शिक्षा पर हुई संगोष्ठी में भी भाग लिया (12–13 फरवरी 1990)।

श्री प्रकाश

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए ''रोजगार शिक्षा योजना पर एक व्याख्यान दिया (3 मई 1989)।

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रशासकों के लिए मानव संसाधन प्रबन्ध के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल चर्चे के अंतर्गत पेनोलिस्ट की भूमिका निभायी (15 मई 1989)

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रग में शैक्षिक योजना जनशक्ति योजना और सामाजिक आर्थिक योजना के बीच संबंध पर व्याख्यान दिए। नई दिल्ली 25 मई 1989)।

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आर्थिक विकास और पूंजी सिद्धान्त तथा कौशल के लिए ''विकास युक्त शैक्षिक संरचना'' पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान दिया। (4–6 जुलाई 1989)

अकादमिक स्टाफ कालेज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा ''शिक्षा का अर्थ शास्त्र कुछ विशेष बिंदु'' विषय पर आयोजित अभिविन्यास कायरक्रम में एक व्याख्यान दिया (17 जुलाई 1989)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के अर्थशास्त्र विभाग में ''भारतीय अर्थशास्त्र के संदर्भ में विकास का प्रतिरूप भारतीय अनुभव और वहु प्रयोजन सिद्धान्त की आवश्यकता तथा मुद्रा स्फीति सिद्धांत पर इन्होंने व्याख्यान दिए (18 जुलाई 1989)

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम गे ''जनशक्ति योजना अभिगम: वापसी की विधि, सागाजिक मांग, और जनशक्ति की मांग'' पर व्याख्यान दिए। (9 अगस्त 1989)

डा. एच. एस. गौर विश्वविद्यालय सागर के अकादमिक स्टाफ कालेज में ''शिक्षा विकास में शिक्षा की भूमिका'' और ''मानव संसाधन पर आधारित विकास की रणनीति'' नामक विषयों पर दो व्याख्यान दिए (1–5 सितंबर 1989)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा आयोजित ''अल्पाधिकारी बाजार संरचना में मूल्य निर्धारण प्रक्रिया'' पर दो व्याख्यान दिए। (12 सितम्वर 1989)

रावेंशॉ कालेज कटक में नेहरू जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 'भारत में योजना' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य सदस्य की भूमिका निभायी (25 सितम्बर 1989)

1989-90

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अकादमिक स्टाफ कालेज में रोजगार और जनशक्ति योजना पर एक व्याख्यान दिया। (4 अक्टूबर 1989)

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के उच्च शिक्षा में व्यावसायिक विकास केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा और विकास पर एक व्याख्यान दिया (9 अक्टूबर 1989)

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''जनशक्ति अनुमान के लिए आगत निर्गत नमूने'' पर एक व्याख्यान दिया (12 अक्टूबर, 3 जनवरी, 19 फरवरी, 1990)

अकादमिक स्टाफ कालेज, पौंडिचेरी में ''शैक्षिक और आर्थिक विकास और लागत मूल्य विश्लेषण'' पर एक व्याख्यान दिया। (14–15 दिसंबर 1989)

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ कालेज, नई दिल्ली कार्यक्रम ''जनशक्ति योजना और रोजगार'' पर एक व्याख्यान दिया (2 फरवरी 1990)

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान, संस्थान नई दिल्ली में ''शैक्षिक योजना अभिगम और वापसी की दर'' आदि पर एक व्याख्यान दिया। (20 फरवरी 1990)

अनु. जा. और अनु. जन. जा. आयोग समाज कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''बंधुआ मजदूरों की सामाजिक आर्थिक पहलू'' पर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया । (4–5 जनवरी 1990)

कुसुम के. प्रेमी

उच्चतर शिक्षा संस्थान (ऐडवांसड इंस्टिट्यूट) शिमला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत में बाल श्रम : शैक्षिक विकास के सांख्यिकी आंकड़े पर उन्होंने एक आलेख प्रस्तुत किया। (16–18 अप्रैल 1989)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक विकास और शिक्षा नीति पर एक व्याख्यान दिया। (21 अगस्त 1989)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ''महिलाओं के संदर्भ में सूचक का चुनाव और विकास'' विषय पर एक व्याख्यान दिया (23 अगस्त 1989)

राज्य प्रशासन अकादगी, भोपाल मे अनु. जा./अनु. जन. जा. को शिक्षा देने की चुनौती और समस्याएं पर एक व्याख्यान दिया (27 अक्टूबर 1989)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक योजना की वहुस्तरीय संरचना पर एक व्याख्यान दिया।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में शैक्षिक विकास के सूचक विषय पर इन्होंने एक व्याख्यान दिया (21 नवंबर 1989)

आई. एल. ओ. के सहयोग से सामान्य निदेशक (शिक्षा और प्रशिक्षण) द्वारा महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार विविधिकरण पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (23–25 फरवरी, 1990)

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन केन्द्र (नई दिल्ली) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा में संभ्रांत वर्गवाद विषयक संगोष्ठी में भाग लिया (31 जनवरी 1990)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा ''1990 ''2'' में अनु. जा./अनु. जन. जा. की लड़कियों की शिक्षा'' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशिविर में भाग लिया और ''अनु. जाति/अनु. जन. जा. की शिक्षा योजना और प्रबंध आयाग'' पर एक आलेख प्रस्तुत किया (26–28 मार्च 1990)

के. सुधाराव

भारतियार विश्वविद्यालय, कोयंबतूर के अकादमिक स्टाफ कालेज में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय अध्यापकों के संकाय मूल्यांकन पर एक व्याख्यान दिया (25 अप्रैल 1989)

1989-90

जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में ''उद्देश्य और लक्ष्य के प्रबन्ध पर एक व्याख्यान दिया। (16 जून 1989)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रशिक्षण, नई दिल्ली में ''केन्द्रीय नेतृत्वगुण के प्रभावी शैक्षिक नेतृत्वगुण'' पर एक व्याख्यान दिया। (19 जून 1989)

केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम के अकादमिक स्टाफ कालेज में ''उच्च शिक्षा प्रणाली और संस्थान मूल्यांकन तथा प्रवृति'' पर एक व्याख्यान 12–13 जुलाई 1989 को दिया।

मैसूर विश्वविद्यालय) मैसूर द्वारा आयोजित संगोष्ठी में''कर्नाटक के महाविद्यालयों में स्वायत्त योजनाओं के कार्यान्वयन की व्याहार्यता'' पर एक आलेख प्रस्तुत किया (1 अगस्त 1989)

कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ में ''उच्च शिक्षा प्रणाली और प्रवृति संप्रेषण कौशल'' तथा स्वायत्त योजना पर एक व्याख्यान दिया (3–4 अगस्त 1989)।

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में ''स्वायत्तता और उत्तरदायित्व : कार्यान्वयन की व्यवहार्यता'' पर केन्द्रीय संस्थान के संकायों के समक्ष एक व्याख्यान दिया। (21 अगस्त 1989)

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशिविर प्रत्याचन और मूल्यांकन में भाग लिया (11–12 नवंबर 1989)

भारतियार विश्वविद्यालय कोयंबतूर में उच्च शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशिविर में भाग लिया (11-12 नवंबर 1989)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा ''महिलाओं के कार्य का मार्गदर्शन'' विषय पर आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया (28–30 नवंबर 1989)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ''प्रभावी प्रबंध के लिए संप्रेषण की भूमिका'' पर एक व्याख्यान दिया (16 दिसम्बर 1989)

कर्नाटक विश्वविद्यालय, कर्नाटक के अकादमिक स्टाफ कालेज में ''समय का प्रबन्ध'' और स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व पर एक व्याख्यान दिया। (18–19 दिसंबर 1989)

नवोदय विद्यालय प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली में ''संप्रेषण कौशल'' पर इन्होंने एक व्याख्यान दिया ।

क्वीनस् मेरी महाविद्यालय, मद्रास में ''कार्यान्वयन स्वायत्तता – परिप्रेक्ष्य और संभावना'' पर एक व्याख्यान दिया (8–9 फरवरी 1990)

मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों की स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व, उच्च शिक्षा प्रणाली और प्रवृति और अध्यापकों की जिम्मेदारी पर व्याख्यान दिए (20–22 मार्च 1990)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली, द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशिविर ''अनु. जा./अनु. जन. जा. की लड़कियों की शिक्षा : 1990 का परिप्रेक्ष्य'' में भाग लिया (26–28 मार्च 1990)

जी. डी. शर्मा

दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षा विकास केन्द्र में ''अध्यापक कार्यसेवा की स्थिति – सामग्री स्थिति'' पर एक व्याख्यान दिया (15 अप्रैल 1989)

देवी अहिल्या महाविद्यालय, इंदौर में ''उच्च शिक्षा'' पर एक व्याख्यान दिया (11 मार्च 1989)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा महिलाओं की शिक्षा और विकास प्रणाली पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशिविर में भारत एक परिचय तथा भारत का अर्थशास्त्र पर एक व्याख्यान दिया (23 मई 1989)

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के व्यावसायिक उच्च शिक्षा विकास केन्द्र में अध्यापकों के कार्य की स्थिति पर एक व्याख्यान दिया। (23 मई, 1989)

जामिया गिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के अकादमिक स्टाफ

1989-90

कालेज में ''उच्च शिक्षा – शिक्षा नीति'' पर एक व्याख्यान दिया (24 मई 1989)

दिल्ली विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केन्द्र में केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति और कार्यक्रमों का प्रभाव पर एक व्याख्यान दिया (26 मई 1989)

द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, गुड़गांव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के रसायन शास्त्र विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए एक व्याख्यान दिया (8 जून 1989)

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास में उच्च शिक्षा पर एक व्याख्यान दिया । (26 जुलाई 1989)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशिविर में शैक्षिक अनुसंधान पर एक व्याख्यान दिया। (25–28 सितंबर 1989)

दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के व्यावसायिक उच्च शिक्षा केन्द्र में ''उच्च शिक्षा केन्द्र में ''उच्च शिक्षा की संरचना पर एक व्याख्यान दिया। (16 अक्टूबर 1989)

लखनऊ विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ कालेज में ''उच्च शिक्षा'' पर एक व्याख्यान दिया। (17 अक्टूबर 1989)
कर्नाटक विश्वविद्यालय में ''नई शिक्षा नीति पर व्याख्यान दिया। (19–20 अक्टूबर 1989)

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के व्यावसायिक उच्च शिक्षा केन्द्र में ''उच्च शिक्षा के अध्यापकों की स्थिति'' पर एक व्याख्यान दिया। (29 अक्टूबर 1989)

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र हरियाणा के अकादमिक स्टाफ कालेज में ''उच्च शिक्षा'' पर व्याख्यान दिया। (2–3 नवंबर 1989)

बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में ''उच्च शिक्षा'' पर व्याख्यान दिया। 28–29 दिसंबर 1989)

हैदराबाद के अकादमिक स्टाफ कालेज द्वारा आयोजित ''उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय विकास'' पर एक व्याख्यान दिया (18 जनवरी 1989)

भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में'' विश्वविद्यालय में अकादमिक निर्णयों के लिए योजना विषय पर एक व्याख्यान दिया। (20 फरवरी 1990)

कोयंबतूर के अकादमिक स्टाफ कालेज द्वारा आयोजित संगोष्ठी में ''उच्च शिक्षा और विकास परिप्रेक्ष्य'' पर एक व्याख्यान दिया (26–27 फरवरी 1990)

शिमला के अकादमिक स्टाफ कालेज द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय विकास और ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति'' पर एक व्याख्यान दिया (21 मार्च 1990)

चंडीगढ़ के अकादमिक स्टाफ कालेज में उच्च शिक्षा और विकास का परिप्रेक्ष्य पर एक व्याख्यान दिया (26 मार्च 1990)

आर. एस. शर्मा

रा. शै. अ. और प्र. प... नई दिल्ली द्वारा आयोजित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के संकायों की परिचर्चा बैठक में भाग लिया। (26 –28 अप्रैल 1989)

बी. एच. श्रीधर

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में ''जनशक्ति योजना में संगणक का प्रयोग'' विषय पर एक व्याख्यान दिया (29 अगस्त 1989)

रा. शै. अ. और प्र. परि. नई दिल्ली द्वारा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्रचार्यो के लिए आयोजित कार्यक्रम में एक व्याख्यान दिया (7 फरवरी 1990)

जे. बी. जी. तिलक

अनुपयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में ''जनशक्ति योजना में शिक्षा की लागत'' पर एक व्याख्यान दिया (14 फरवरी 1990)

1989-90

के. जी. विरमानी

हैदराबाद के उसमानिया विश्वविद्यालय में यूनेस्को के सहयोग से भारत राष्ट्रीय आयोग में हुई संगोष्ठी ''मानव शांति की रक्षा के लिए यूनेस्को की भूमिका'' में (28–30 अप्रैल 1989)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्राचार्यो के शैक्षिक प्रबन्ध पर तीन व्याख्यान दिए। (26 जून 1989)

जामिया मिलिया इस्लामिया के शैक्षिक प्रशासकों के लिए ''प्रबन्ध विकास कार्यक्रम'' पर एक व्याख्यान दिया। (27 जून 1989)

हैदराबाद में कोयला उद्योग के अधिकारियों के लिए प्रबन्ध विषय पर एक व्याख्यान दिया। (13 अक्टूबर 1989)

देहरादून में तेल उद्योग के अभियंताओं के लिए ''प्रबंध'' विषय पर एक व्याख्यान दिया। (30 अक्टूबर 1989)

केन्द्रीय विद्यालय सनगठन नई दिल्ली द्वारा दूरभाष (टेलिफोन) उद्योग के अधिकारियों तथा केन्द्रीय विद्यालय के प्रचार्यो के लिए प्रबन्ध विषय पर एक व्याख्यान दिया (12,18 और 27 दिसंबर 1989)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली के अभियंताओं द्वारा आयोजित विषय ''प्रबन्ध'' पर एक व्याख्यान दिया। (10 जनवरी 1990)

शिक्षा और अनुसंधान संगठन के लिए सरकार का प्रबंध विषयक कार्यशिविर में भाग लेने वाले अधिकारियों के लिए प्रवंध विषय पर एक व्याख्यान दिया। (6–7 फरवरी 1990)

1989-90

अनुबंध -V

समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए माड्यूलों की सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–विकास के प्रमुख क्षेत्र
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986: योजना और प्रबन्ध के आयाम
3. समुदाय भी भागीदारी और विकेद्रीकरण
4. विद्यालय निरीक्षण और पर्यवेक्षण
5. संस्थागत आत्म मूल्यांकन
6. जिला स्तर पर शैक्षिक योजना की विकेंद्रित पद्धति
7. विकेंद्रित योजना की संकल्पना
8. जिला स्तरीय शैक्षिक याजना के लिए संगठनात्मक व्यवस्था और कार्यान्वयन रणनीतियां
9. जिला स्तरीय योजना की पूर्व आवश्यकताएं
10. जिला स्तर पर शैक्षिक योजना की प्रणाली
11. संस्थागत योजना और प्रबंध
13. विद्यालय परिसर का प्रबंध
14. सूचना और संचारेक्षण पद्धति
15. परियोजना प्रतिपादन और प्रबनध
16. शैक्षिक तकनीक–योजना और प्रबन्ध
17. शैक्षिक वित्त
18. शिक्षा का प्रबंध
19. आदर्श पेश करने वाले विद्यालयों के प्राचार्य :गतिशील समाज में जटिल भूमिका
20. प्रभावी शैक्षिक नेतृत्वगुण
21. कार्यकारी निर्णय
22. केन्द्रीय विद्यालय का प्रबन्ध : कार्यरत प्राचार्यो का केस
23. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्यविधि : विद्यालय के अध्यक्षों का निहितार्थ
24. विद्यालय परिसरों की स्थापना और प्रबन्ध पर एक मार्गदर्शिका
25. विद्यालय में अकादमिक का प्रबंध : शैक्षिक पर्यवेक्षण अभ्यास
26. विद्यालयों के अध्यक्ष का कार्मिक प्रबंध
27. प्रारंम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण: व्यष्टि स्तरीय योजना
28. समुदाय नेताओं के प्रशिक्षण की मार्गदर्शिका
29. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रणाली प्रबंध और संस्था की प्रभावी कार्यपद्धति
30. शैक्षिक कार्यक्रम और पाठ्चर्या में लिंग पूर्वाग्रह
31. दूरवर्ती शिक्षा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी की योजना और प्रबन्ध पर अनुसंधान
32. वित्तीय योजना और प्रबंध

इन माइयूलों की प्रतियां राज्यों को भेजी गयी थी ताकि वे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यकताओं के अनुसार इनका उपयोग कर सकें।

1989-90

अनुबंध- VI

सातवीं योजना के दौरान चालू किए गए अनुसंधान अध्ययनों की सूची (1985–1990)

1985–86 (20)

1. विद्यालयों में अनुकूलतम अध्यापक–छात्र औसत का अध्ययन
2. भारत में शैक्षिक नीति और योजना का अध्ययन–योजना आयोग की भूमिका : भविष्य परिप्रेक्ष्य और वर्तमान प्रतिष्ठा के संदर्भ में
3. विकास के कुछ आयामों पर शैक्षिक स्तरों का प्रभाव – ग्रामीण घरों पर एक अध्ययन
4. भारत में शिक्षा के लिए बाह्य वित्त व्यवस्था

5-16. नई शिक्षा नीति के सूत्रपादन के लिए विभिन्न प्रलेख/संचार/रिपोर्ट के विषयवस्तु विश्लेषण पर आधारित निम्न अध्ययन :

- भारतीय शिक्षा का पुनर्रचना : नागरिक बोध खंड I–IV
- भारतीय शिक्षा प्रणाली : जनवाणी संचार अध्ययन पर सामाजिक लेखापरीक्षण.
- भारतीय शिक्षा की पुनर्रचना : तकनीकी संस्थाओं का बोध
- भारतीय शिक्षा की पुनर्रचना : विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व
- भारतीय शिक्षा की पुनर्रचना : शैक्षिक संस्थाओं/निकायों के सुझाव
- भारतीय शिक्षा की पुनर्रचना : गैर – शैक्षिक संगठनों का विचार
- स्वैच्छिक और व्यावसायिक शिक्षा निकाय : खंड I और II
- नई शिक्षा नीति में प्रेस की भूमिका
- भारतीय शिक्षा पुनर्रचना : प्रेस का दृष्टिकोण
- नई शिक्षा नीति : उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य
- भारतीय शिक्षा की पुनर्रचना : राज्य स्तरीय विचार-विमर्श का विश्लेषण
- भारतीय शिक्षा पुनर्रचना : राज्यों का प्रत्यक्षबोध

17-20. वर्ष 2000 में भारतीय शिक्षा परियोजना के अंतर्गत पूरे किए गए चार अध्ययन – एक दीर्घावधि प्रत्यक्ष बोध (चरण–I)

- भारत में प्राथमिक शिक्षा – जनगणना द्वारा प्राप्त कुछ साक्ष्य
- शैक्षिक योजना और प्रबन्ध के लिए सिमुलेशन नमूनों के उपयोग पर प्राथमिक शिक्षा
- भारत में प्राथमिक शिक्षा – एक प्रवृत्ति विश्लेषण
- भविष्य विकास के लिए शिक्षा योजना – मुद्दे और वरण

1986–87 (19)

21. महाविद्यालयों के अध्यक्ष की निष्पादन भूमिका पर एक अध्ययन
22. अभियांत्रिकी महाविद्यालायों में कार्मिक संरचना
23. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में मालसूची नियंत्रण प्रबन्ध
24-32. शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के प्रारंभिक चरण में अनौपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन अध्ययन परियोजना के

1989-90

अंतर्गत नौ मूल्यांकन रिपोर्ट
शैक्षिक रूप से पिछड़े यह राज्य निम्नलिखित हैं :–

- आंध्र प्रदेश
- असम
- बिहार
- जम्मू और कश्मीर
- मध्य प्रदेश
- उड़ीसा
- राजस्थान
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल

33. भारत में शिक्षा अवसरों की समता और अवसरों की पर विशेष ध्यान देते हुए एक शैक्षिक वित्त अध्ययन – केरल और उत्तर प्रदेश के विद्यालय शिक्षा पर एक केस अध्ययन (आई. सी. एस. एस. आर.)
34. शिक्षा और विकास का मोनोग्राफ
35. भारत में उच्च शिक्षा और रोजगार : एक पुनरीक्षण (आई. आई. ई. पी. अध्ययन)
36. भारत में पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य : मानव संसाधनों का विकास (ई. एस. सी. ए. पी. ई. बैंकाक)
37. शिक्षा और श्रम बाजार : भारतीय साक्ष्यों का सर्वेक्षण (आई. आई. ई. पी. पैरिस)
38. उच्च शिक्षा में समता, गुणवत्ता और लागत (यूनेस्को)
39. केरल में शैक्षिक विकास के इतिहास पर एक अध्ययन

1987–88 (8)

40. वर्ष 2000 में भारतीय शिक्षा – एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य (प्रथम चरण)
41. हरियाणा के (जिला गुड़गांवा) पुणहाना खंड के 20 ग्राम समूहों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से शैक्षिक योजना और प्रशासन के नवाचारी व्यवहारों पर आधारित कार्य अनुसंधान (प्रथम चरण)
42. महाविद्यालयों का प्रभावी कार्य और विकास – एक कार्य अनुसंधान अध्ययन (प्रथम चरण)
43. प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के सीमित पाठ्यक्रम और स्वायत्त कार्यक्रमों का पुनरीक्षण अध्ययन (एस. डब्बलू. बी. और नीपा)
44. शिक्षा और उत्पादन कार्य : सामाजिक रूप से उपयुक्त उत्पादन कार्य के अनुभव – भारतीय अनुभव (यूनेस्को द्वारा प्रायोजित)
45. शिक्षा में निर्णय और शैक्षिक अनुसंधान : भारतीय प्रतिष्ठा (यूनेष्को द्वारा प्रायोजित)
46. नगर निगम दिल्ली के शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण और प्रशासन कर्मचारियों के लिए अध्यापन के मानक पर एक अध्ययन
47. व्यष्टि स्तरीय योजना पर एक मोनोग्राफ : गांधी ग्राम परीक्षण (नीपा सहयोग योजना के अंतर्गत)

1988–89 (3)

48. पुनहाना खंड में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से शैक्षिक योजना और प्रशासन के नवाचारी व्यवहारों पर आधारित कार्य अनुसंधान (चरण–II)
49. शैक्षिक परिवर्तन का प्रबंध : एक भारतीय नमूना
50. जम्मू और कश्मीर के जिला शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन अध्ययन (नीपा सहयोग योजना के अंतर्गत)

1989–1990 (30)

पूरा किया गया (5)

51. महिला और विकास के एट्लस पर एक अनुसंधान परियोजना
52. आंध्र प्रदेश के शिक्षा और विकास पर एक मोनोग्राफ
53. उच्च शिक्षा के चुने हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधन विनिधान पद्धति (आई. आई. ई. पी. – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – नीपा)
54. महिला कार्यपालकों की प्रतिष्ठा और पृष्ठभूमि पर एक पूछताछ (नीपा सहयोग योजना के अंतर्गत)
55. जिला शिक्षा अधिकारियों का कृतिक विश्लेषण : एक राष्ट्रीय अध्ययन

1989-90

जारी (22)

56. वर्ष 2000 में शिक्षा (चरण –II)
57. भारत में साक्षरता : देशकाल विश्लेषण (1901 – 1981)
58. हरियाणा (गुड़गांव जिला) के पुनहाना खंड में (प्रारंभिक शिक्षा सार्वजनीकरण/प्रौढ़ शि.) (ए. आर. आई. एस. ई.) शैक्षिक योजना और प्रशासन की क्रियान्वयन रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए कार्य अनुसंधान
59. महाविद्यालयों का प्रभावी कार्य और विकास : एक कार्य अनुसंधान अध्ययन (द्वितीय चरण)
60. पिछड़ी जनजाति तथा उपयोजना क्षेत्रों के शैक्षिक विकास पर एक अध्ययन
61. विद्यालय मानचित्रण परियोजना पर एक अध्ययन
62. शैक्षिक प्रशासन का द्वितीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण
63. लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध – भारत के लिए निहितार्थ तथा पाठ पर एक अध्ययन
64. महाविद्यालयों के विकास में महाविद्यालय विकास परिषद की भूमिका : चुने हुए 10 महाविद्यालय विकास परिषद पर गहराई से एक अध्ययन
65. भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता स्तरों के बीच विषमताओं का जिलावार विश्लेषण
66. शैक्षिक संस्थाओं में स्वायत्तता का प्रबंध : स्वायत्त महाविद्यालयों का अध्ययन
67. महाराष्ट्र में शिक्षा और विकास का मोनाग्राफ

सहयोगात्मक अध्ययन (2)

68. मूल शिक्षा सेवाओं की गुणवता (नीपा – आई. आई. ई. पी. सहयोगात्मक अध्ययन)
69. महिला महाविद्यालयों के प्रशासकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान (एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय के सहयोग से)

प्रायोजित अध्ययन (3)

70. प्रारंभिक शिक्षा का संगणकीकृत योजना (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
71. जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एम. आई. एस. (शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
72. उच्च शिक्षा में वर्तमान सुविधाओं/संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग पर एक अध्ययन (योजना आयोग द्वारा प्रायोजित)

नीपा सहयोग योजना के अंतर्गत (5)

73. भारतीय विश्वविद्यालयों का वित्त प्रबंध (नीपा सहयोग योजना के अंतर्गत)
74. विभिन्न वर्ग आकार के दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों की लागत का अध्ययन (नीपा सहयोग योजना के अंतर्गत)
75. भारत की वर्तमान पत्राचार संस्थानों में अध्यापन और अधिगम के लिए अपनाई गई पद्धति का समीक्षात्मक मूल्यांकन (नीपा सहयोग योजना के अंतर्गत)
76. तमिलनाडु में शैक्षिक तकनीक का प्रबन्ध (नीपा सहयोग योजना के अंतर्गत)
77. दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के प्रभावी कार्य के लिए औपचारिक विश्वविद्यालय ढ़ाचे के भीतर दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली का संगठनात्मक तथा संकाय संरचना का अध्ययन ताकि उचित और पर्याप्त संगठनात्मक तथा संकाय संरचना तैयार किया जा सके (नीपा सहयोग के अंतर्गत)

स्वीकृत नए अध्ययन (3)

78. भारत में कृषि स्नातक बाजार : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर का लागत मूल्य अध्ययन (नीपा सहयोग योजना के अंतर्गत)
79. भारत में शैक्षिक विकास की क्षेत्रीय असमानता : बुनियादी स्तर पर समाज कल्याण के संदर्भ में शैक्षिक असमानताओं पर एक पूछताछ
80. शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी उपयोग – एक केस अध्ययन

1989-90

अनुबंध VII

सातवीं योजना के दौरान निर्मित अनियत पत्रों की सूची

1.	भारत में पिछड़ी जनजाति की साक्षरता – क्षेत्रीय आयाम	मूनिस रजा ए. अहमद एस. सी. नूना
2.	भारत में शिक्षा की लागत का विश्लेषण	जे. बी. जी. तिलक
3.	शिक्षा के क्षेत्र में वित्त सुविधा प्रदान करने के सिलसिले में अंतर क्षेत्रीय विभिन्ताऐं-- क्षेत्रीय आयाम	सी. बी. पद्मानाभन
4.	भारत में शैक्षिक वित्त	जे. बी. जी. तिलक
5.	सभी के लिए शिक्षा में संघीय वित्त की भूमिका: भारतीय शिक्षा में अर्थपूर्ण केन्द्र-राज्य वित्त व्यवस्था	सी. बी. पद्मानाभन
6.	प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की योजना और उसके निहितार्थ	ब्रह्म प्रकाश और वाई. पी. अग्रवाल
7.	महाविद्यालय के अध्यक्षों की निष्पादन भूमिका	एन. एम. भागिया एन. जुनेजा और डी. एच. श्रीकांत
8.	भविष्य के लिए शिक्षा योजना-विकास, मुद्दे और वरण	ब्रह्म प्रकाश-वाई. पी. अग्रवाल एन. वी. वर्गीस एल. एस. गणेश
9.	एकांत क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण : अरूणाचल प्रदेश से संबंधित एक केस	के. सुजाता
10.	आश्रम विद्यालयों में शिक्षा – आन्ध्र प्रदेश से संबंधित केस	के. सुजाता

1989-90

परिशिष्ट I

नीपा परिषद के सदस्य
(31 मार्च 1990 तक)

अध्यक्ष

रिक्त

उपाध्यक्ष

प्रोफेसर सत्यभूषण
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

पदेन सदस्य

प्रोफेसर यशपाल	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
श्री अनिल बोर्डिया	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
श्री एल. एस. नारायणन	वित्त सलाहकार, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री ए. आर. बंधोपाध्याय	अतिरिक्त सचिव, जन शिकायत और प्रशासनिक, सुधार मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
श्री एम. आर. कोल्हाटकर	सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
श्री के. गोपालन	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

शिक्षा सचिव

श्री डेंगनुना	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, मिजोरम सरकार, एजवाल

1989-90

श्री वी. टोबडेन	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, सिक्किम सरकार, ताशिलिंग एक्सटेंशन, गंगटोक
सुश्री सुषमा चौधरी	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, सिविल सचिवालय, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर, जम्मू तवी
सुश्री कुमुद बंसल	तकनीकी शिक्षा सचिव, महाराष्ट्र सरकार, बंबई – 400032
श्री बी. के. भट्टाचार्या	आयुक्त और सचिव, शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार, सचिवालय – II, डा. बी आर. अम्बेडकर रोड, बैंगलौर
श्री प्रदीप सिंह	समाहर्ता और विकास आयुक्त, लक्ष्यद्वीप, कवारती

शिक्षा निदेशक/डी. पी. आई.

श्री एस. बी. विश्वास	विद्यालय निदेशक, त्रिपुरा सरकार, अगरतला
डा. घनश्याम दास	निदेशक (उच्च शिक्षा सचिवालय), उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर
श्री पी. एस. भूपल	निदेशक, जन शिक्षा (प्राथमिक), सेक्टर – 17 सी, चंडीगढ़
श्री ललित के. पवार	निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर
तिरू वी. ए. शिवाज्ञानम्	निदेशक (अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा), कालेज रोड, डी. पी. आई. परिसर, मद्रास
श्री बेअंत सिंह	निदेशक (शिक्षा प्रशासन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), पोर्ट ब्लेयर

विख्यात शिक्षाविद

डा. के. वेंकटासुब्रामनियम	कुलपति, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी – 60500
डा. एन. आर. सेठ	निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद
डा. एस. पी. अहलूवालिया	प्रोफेसर, अध्यक्ष और डीन, सागर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश – 470003
डा. पी. डी. शुक्ला	ए. १४/१५ वसंत बिहार, नई दिल्ली

1989-90

प्रोफेसर अबद अहमद	निदेशक, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली
डा. मंगल दूबे	बी. बी. /35, अधिकारी फ्लैट, शास्त्री नगर, पटना

कार्यकारी समिति के सदस्य

श्री एस. पी. तूली	संयुक्त सचिव (योजना), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली
कार्यकारी निदेशक	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

संकाय सदस्य

डा. के. जी. विरमानी	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सचिव

श्री आर. पी. सक्सेना	कुलसचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

1989-90

परिशिष्ट II

कार्यकारी समिति के सदस्य
(31 मार्च 1990 तक)

प्रोफेसर सत्य भूषण — अध्यक्ष
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

श्री एल. एस. नारायणन
वित्त सलाहकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली

श्री एस. पी. तूली
संयुक्त सचिव (योजना)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

श्री एम. आर. कोलहाटकर
सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग
योजना भवन
नई दिल्ली

सुश्री कुमुद बंसल
तकनीकी शिक्षा सचिव
महाराष्ट्र सरकार
बंबई

1989-90

6. डा. एन. आर. सेठ
निदेशक
भारतीय प्रबन्ध संस्थान
वस्त्रपुर
अहमदाबाद 380015

7. कार्यकारी निदेशक
नीपा
नई दिल्ली

8. श्री आर. पी. सक्सेना
कुलसचिव
नीपा
नई दिल्ली

1989-90

परिशिष्ट III

वित्त समिति के सदस्य
(31 मार्च 1990 तक)

1.	प्रो. सत्यभूषण निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री एल. एस. नारायणन वित्त सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग नई दिल्ली	
3.	श्री एस. पी. तूली संयुक्त सचिव (योजना) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग नई दिल्ली	
4.	डा. घनश्याम दास निदेशक (उच्च शिक्षा सचिवालय) उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर – 751001	
5.	कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली	
6.	श्री आर. पी. सक्सेना कुलसचिव राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली	सचिव

1989-90

परिशिष्ट IV

कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य
(31 मार्च 1990 तक)

1. प्रो. सत्यभूषण — अध्यक्ष
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. प्रो. जे. एस. राजपूत
संयुक्त सचिव सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग, नई दिल्ली

3. श्री एस. पी. तूली
संयुक्त सचिव (योजना)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

4. श्री एल. मिश्रा
संयुक्त सचिव और महा निदेशक
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

1989-90

परिशिष्ट II

कार्यकारी समिति के सदस्य
(31 मार्च 1990 तक)

प्रोफेसर सत्य भूषण — अध्यक्ष
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

श्री एल. एस. नारायणन
वित्त सलाहकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली

श्री एस. पी. तूली
संयुक्त सचिव (योजना)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

श्री एम. आर. कोलहाटकर
सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग
योजना भवन
नई दिल्ली

सुश्री कुमुद बंसल
तकनीकी शिक्षा सचिव
महाराष्ट्र सरकार
बंबई

1989-90

6. डा. एन. आर. सेठ
निदेशक
भारतीय प्रबन्ध संस्थान
वस्त्रपुर
अहमदाबाद 380015

7. कार्यकारी निदेशक
नीपा
नई दिल्ली

8. श्री आर. पी. सक्सेना
कुलसचिव
नीपा
नई दिल्ली

1989-90

परिशिष्ट III

वित्त समिति के सदस्य
(31 मार्च 1990 तक)

1. प्रो. सत्यभूषण — अध्यक्ष
   निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

2. श्री एल. एस. नारायणन
   वित्त सलाहकार
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   नई दिल्ली

3. श्री एस. पी. तूली
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   नई दिल्ली

4. डा. घनश्याम दास
   निदेशक (उच्च शिक्षा सचिवालय)
   उड़ीसा सरकार
   भुवनेश्वर – 751001

5. कार्यकारी निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
   प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

6. श्री आर. पी. सक्सेना — सचिव
   कुलसचिव
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

1989-90

परिशिष्ट IV

कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य
(31 मार्च 1990 तक)

1. प्रो. सत्यभूषण — अध्यक्ष
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. प्रो. जे. एस. राजपूत
संयुक्त सचिव सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग, नई दिल्ली

3. श्री एस. पी. तूली
संयुक्त सचिव (योजना)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

4. श्री एल. मिश्रा
संयुक्त सचिव और महा निदेशक
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

1989-90

योजना आयोग

5. श्री एम. आर. कोलहाटकर
सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग
नई दिल्ली

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग

6. प्रो. एस. के. खन्ना
सचिव
विश्व विद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली – 110002

राज्य शिक्षा सचिव और जन शिक्षा निदेशक

7. श्री एच. एम. माथुर
आयुक्त और सचिव (राजस्थान)
शिक्षा विभाग, जयपुर
राजस्थान – 302004

8. श्री टी. वेंका रेड्डी, भा. प्रशा. से.
निदेशक (विद्यालय शिक्षा)
आंध्र प्रदेश
हैदराबाद – 500004

अकादमिक सदस्य

9. प्रो. इकबाल नारायण
कुलपति
नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय
लोवर लाक्यूमियर
शिलाँग – 793001

10. डा. डी. डी. नरूला
अवैतनिक वरिष्ठ अध्येता
विकास अध्ययन संस्थान
डी. 124 ए. मंगल मार्ग
बापू नगर मंगल जयपुर
राजस्थान

1989-90

11. डा. पी. आर. पंचमुखी
निदेशक
भारतीय शिक्षा संस्थान
128/2, कार्वे रोड, कोतरूड
पुणे – 411007, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

12. प्रो. एम. के. रैना
अध्यापक शिक्षा विभाग
विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
नई दिल्ली

संकाय सदस्य

13. डा. एम. पुखोपाध्याय
वरिष्ठ अध्येता
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

14. डा. आर. गोविन्द
वरिष्ठ अध्येता
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

15. डा. जी. डी. शर्मा
वरिष्ठ अध्येता
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

सचिव

16. श्री आर. पी. सक्सेना
कुलसचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1989-90

परिशिष्ट V

संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ
(31 मार्च 1990 तक)

सत्यभूषण, निदेशक

शैक्षिक प्रशासन एकक

एम. एम. मुखोपाध्याय वरिष्ठ अध्यंता और अध्यक्ष
सी. मेहता, अध्येता (अवकाश पर विदेश में)
के. सुजाता, अध्येता
ए. मैथ्यू, सह–अेत्ता
मंजू नरूला, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक वित्त एकक

जे. बी. तिलक, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
वीरा गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक योजना एकक

श्री प्रकाश, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
रंजना श्रीवास्तव, सह–अध्येता
एस. एम. आई. ए. जैदी, सह-अध्येता
प्रभा देवी अग्रवाल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक नीति एकक

सुश्री कुसुम के. प्रेमी, अध्येता और अध्यक्ष
नलिनी जुनेजा, सह अध्येता
प्रमिला मेनन, सह–अध्येता
डां बी. दामले, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

1989-90

उच्च शिक्षा एकक

जी. डी. शर्मा, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
जयलक्ष्मी इंदिरेसन, वरिष्ठ अध्येता
के. सुधा राव, अध्येता

अंतर्राष्ट्रीय एकक

के. जी. विरमानी, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
अंजना मंगलागिरि, सह–अध्येता
कौसर विजारत, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक

आर. गोविन्द, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
सुषमा भागिया, अध्येता
वाई. पी. अग्रवाल, अध्येता
सुदेश मुखोपाध्याय, अध्येता
आरिफ हसन, अध्येता
वी. के. पांडा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
वी. पी. एस. राजू, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

प्रादेशिक प्रणाली एकक

एम. एम. कपूर, अध्येता और अध्यक्ष
आर. एस. शर्मा अध्येता
एन. वी वर्गीस, अध्येता
एस. सी. नूना अध्येता
जयश्री जलाली, सह--अध्येता
ओ. पी. पांडे, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

आंकड़ा बैंक

ए. सी. मेहता सह–अध्येता (अध्ययन अवकाश पर)

अनुसंधान परियोजना स्टाफ

डी. एन. अन्रोल, परियोजना अध्येता
आर. पी. कथूरिया, परियोजना अध्येता

1989-90

जे. सी. गोयल, परियोजना अध्येता
आर. के. सोलंकी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना)
एम. एम. रहमान, परियोजना सह–अध्येता
गुलाब झा, परियोजना सह–अध्येता
राजवीर त्यागी, परियोजना सह–अध्येता
कैलाश, परियोजना सह–अध्येता
जी. पी. सिंह, परियोजना सह–अध्येता
राज देव दीक्षित परियोजना सह–अध्येता
अलका कालरा, परियोजना सह–अध्येता
सुश्री अनिता चोपड़ा, परियोजना स्टाफ –I
मुहम्मद अहमद अंसारी, अपरियोजना स्टाफ –II
अनूप बनर्जी, परियोजना स्टाफ – III
इरफान अहमद, परियोजना सहायक
गुणशेखर, परियोजना सहायक
पुष्पा कथूरिया, परियोजना सहायक
सुमित्रा चौधरी, परियोजना सहायक
तारूज्योति बुड़ागौहेन, परियोजना सहायक
आभा गुप्ता, परियोजना सहायक
वी. एन. आलोक, परियोजना सहायक
कल्याणी बी. बिरादर, परियोजना सहायक
एन. तुलसी, परियोजना सहायक
एम. के. शर्मा, परियोजना सहायक
मधुमिता बंधोपाध्याय, परियोजना सहायक
मुहम्मद युनूस, परियोजना सहायक
अनिता नूना, परियोजना सहायक
अशोक कुमार, परियोजना सहायक
सारिका सिबु, परियोजना सहायक
जार्ज मैथ्यू, परियोजना सहायक
एस. के. सामंतरे, परियोजना सहायक
रधु राम राव, परियोजना सहायक
दीपा साही, परियोजना सहायक

परियोजना मानचित्रकार

जमालुद्दीन फरूकी
भारत भूषण

1989-90

पुस्तकालय

निर्मल मलहोत्रा, पुस्तकाध्यक्ष
दीपक मकोल, कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष

प्रलेखन केंद्र

एन. डी. कांडपाल, प्रलेखन अधिकारी

इलेक्ट्रानिक डैटा प्रोसेसिंग और रिप्रोग्राफिक एकक

बी. एच. श्रीधर, कंप्यूटर प्रोग्रामर

प्रकाशन एकक

एम. एम. अजवानी, सहायक प्रकाशन अधिकारी

हिंदी कक्ष

एस. बी. राय, हिंदी संपादक

मानचित्रण कक्ष

पी. एन. त्यागी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

समन्वयन

जुबैदा हबीब, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

कार्यालय प्रशासन

आर. पी. सक्सेना, कुलसचिव
के. एल. दुआ, प्रशासन अधिकारी
ओ. पी. शर्मा, वित्त अधिकारी
जी. एस. भारद्वाज, अनुभाग अधिकारी (अकादमिक प्रशासन)
टी. आर. ध्यानी, अनुभाग अधिकारी (कार्मिक)
एम. एल. शर्मा, अनुभाग अधिकारी (सम्पदा और कार्मिक)
एस. आर. चौधरी, अनुभाग अधिकारी (लेखा)

1989-90

परिशिष्ट-VI

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1989-90

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
वार्षिक लेखा (1989–90)
(प्राप्तियां और भुगतान लेखा) (1. 4. 89 से 31. 3. 90 तक)

प्राप्तियां		
अर्थ शेष		
हस्तगत रोकड़	1,159.00	
अग्रदाय	1,250.00	
बैंक में रोकड़	2,225,348.34	2,227.757.34
भारत सरकार से प्राप्त सहायता		
योजनेतर	8,050,000.00	
योजना	5,700,000.00	13,750,000.00
कार्यालय प्राप्तियां		
लाईसेंस शुल्क	41,772.00	
पानी, बिजली प्रभार	10,266.00	
ई. डी. पी. आर. प्राप्तियां	7,825.00	
फोटोकापी प्राप्तियां	33,772.20	
प्रकाशन रायल्टी	17,229.00	
बेकार भंडार की बिक्री से आय	4,000.00	
अन्य प्राप्तियां	1,059.00	
अवकाश वेतन और पेंशन का अंशदान	56,499.00	
कार्यक्रम प्राप्तियां	33,480.00	205,902.20
छात्रावास किराया		359,300.00
तोहफे तथा चंदे के माध्यम से (पुस्तकालय पुस्तकें)		2,063.00

1989-90

	भुगतान	
संस्थागत व्यय (योजनेतर)		
वेतन	5,220,840.00	
पेंशन और उपदान	437,813.00	
नियोक्ता अंश/अवकाश वेतन और	335,334.00	
पेंशन अंश	47,781.00	
यात्रा व्यय	119,436.00	
वेतन (योजना)	181,441.00	6,342,645.00
कार्यालय व्यय		
योजनेतर	1,500,000.00	
योजना	965,071.55	2,465,071.55
छात्रावास		
आवर्ती व्यय (योजनेतर)	183,761.20	
गैर आवर्ती व्यय– (योजना)	100,432.00	284,193.20
अकादमिक गतिविधियां (योजनेतर)		
कार्यक्रम व्यय	1,383,642.30	
कार्यक्रम व्यय (योजना)	25,400.00	
अनुसंधान अध्ययन	1,105,234.60	
सहायता योजना	127,383.00	
प्रकाशन	244,431.00	
पुनरीक्षण समिति सदस्य के लिए		
यात्रा भत्ता	38,110.00	2,924,200.90
कर्मचारी प्रशिक्षण (योजनेतर)		2,380.00
पूँजी व्यय (योजना)		
पुस्तकालय की पुस्तकें	180,522.00	
तोहफे के रूप में प्राप्त पुस्तकें	2,063.00	
प्रलेखन	303.00	182,888.00
फर्नीचर और फिकस्चर्स	243,445.50	
अन्य कार्यालय उपकरण		52,767.00
संगणक (हार्डवेयर)	288,777.00	584,989.50

1989-90

ब्याज

ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज	19,048.00	
अल्पकालिक जमा राशि पर ब्याज	179,842.96	
बचत बैंक लेखा पर ब्याज	2,661.96	
निवेश पर ब्याज	180,450.00	382,002.92
प्रतिभागियों से प्राप्त राशि		2,150.00

जमा

के. लो. नि. वि.	211,535.82	
उचंत लेखा के पास जमा राशि	24,539.00	236,074.82
सुरक्षा जमा		2,500.00

प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन

कार्यक्रम और अध्ययन प्राप्तियां		1,445,353.45

वसूली योग्य पेशगियां

साईकिल पेशगी	4,130.00	
स्कूलर पेशगी	23,465.00	
त्यौहार पेशगी	23,800.00	
भवन निर्माण पेशगी	90,741.00	
मोटरकार पेशगी	50,036.00	
पंखे पेशगी	760.00	
संगणक पेशगी	2,100.00	
विविध पेशगी	21,126.80	216,158.80
विविध पेशगी (एन.सी. टी.II)		17,692.75
प्रेषित राशि		
जी.एस.एल.आई. योजना		224.00
योग		18,847,179.28

ओ. पी. शर्मा
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1989-90

जमा

के. लो. नि. वि. के पास जमा राशि (योजना)	1,141,735.00	
उचंत लेखा	31,145.00	
सुरक्षा जमा वापसी	2,500.00	
अर्पित राशि	7,000.00	1,182,380.00
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
कार्यक्रम और अध्ययन व्यय (आवर्ती व्यय)	1,827,896.60	
पूँजीगत व्यय	67,305.00	1,895,201.60
वसूली योग्य पेशगियां		
साईकिल पेशगी	10,200.00	
स्कूटर पेशगी	67,800.00	
त्यौहार पेशगी	24,800.00	
भवन निर्माण पेशगी	11,000.00	
मोटरकार पेशगी	267,600.00	
पंखे पेशगी	1,200.00	
संगणक पेशगी	89,185.00	
		471,785.00
प्रेषित राशि		
जी. एस. एल. आई. योजना		1,904.00
रोकड़ बाकी		
हस्तगत रोकड़	1,137.00	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक में जमा	2,507,403.53	2,509,540.53
		18,847,179.28

सत्य भूषण
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1989-90

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
रोकड़ बाकी का विवरण (31 मार्च 1990)

क्रसं.	शीर्ष	रोकड़ जमा	अनुदान
1.	योजनेतर	449,910.28	8,050,000.00
2.	योजना	564,931.43	5,700,000.00
3.	प्रायोजित कार्यक्रम अध्ययन	1,173,330.46	1,445,353.45
4.	उचंत लेखा	32,809,17	–
5.	जमा	7,000.00	–
6.	प्रेषित राशि	(-)224.00	–
	योग	2,227,757.34	15,195,353.45

ओ. पी. शर्मा
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1989-90

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
रोकड़ बाकी का विवरण (31 मार्च 1990)

अन्य प्राप्तियां	योग	भुगतान	शेष
1,379,112.74	9,879,023.02	9,702,772.50	176,250.52
—	6,264,931.43	4,697,115.65	1,567,815.78
17,692.75	2,636,376.66	1,895,201.60	741175.06
24,539.00	57,348.17	31,145.00	26,203.17
2,500.00	9,500.00	9,500.00	कुछ नहीं
224.00	कुछ नहीं	1,904.00	(-)1,904.00
1,424,068.49	18,847,179.28	16,337,638.75	2,509,540.53

सत्य भूषण
निदेशष
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1989-90

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
आय–व्यय लेखा वर्ष (1989–90)

व्यय	
स्थापना व्यय	6,342,645.00
कार्यालय व्यय	2,465,071.55
कर्मचारी प्रशिक्षण	2,380.00
छात्रावास व्यय	183,761.20
अकादमिक गतिविधियां	2,924,200.90
व्यय से अधिक आय	1,912,899.97
योग	13,830,958.62

ओ. पी. शर्मा
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1989-90

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
आय–व्यय लेखा वर्ष (1989–90)

आय		
सहायता अनुदान	13,750,000.00	
सहायता अनुदान को छोड़कर पूँजीकृत आय		
कार्यालय वस्तुएं	685,421.50	
पुस्तकालयों की पुस्तकें	180,522.00	
प्रलेखन	303.00	12,883,753.50
कार्यालय प्राप्तियां		205,902.20
छात्रावास प्राप्तियां		359,300.00
ब्याज		382,002.92
योग		13,830,958.62

सत्य भूषण
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1989-90

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
शेष राशि तालिका 31 मार्च, 1990

देयताएं

पूंजीकृत अनुदान

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	20,852,093.70	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	866,246.50	
परिवर्धन समायोजन	1,333,910.95	
परिवर्धन संशोधन	10,537.00	
घटाएं पूँजी निवेश बट्टे खाते में	—	
घटाएं संशोधन 88–89	25,737.80	
के. लो. नि. वि. द्वारा वापस की गई राशि (1986–87)	58,014.51	22,979,037.84

प्रायोजित कार्यक्रम प्राप्तियां

पूंजीकृत प्राप्तियां	720,693.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	720,693.00
प्रायोजित कार्यक्रम (कोप/एम.आई.एस. पूँजीकृत)	544,295.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	67,305.00	611,600.00

व्यय से अधिक आय

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	5,140,862.99	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,912,899.97	

1989-90

परिसंपत्तियां

भूमि और भवन

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि		12,337,120.22	
परिवर्धन (समायोजन)		1,333,910.95	
वर्ष के दौरान अन्य परिवर्धन		कुछ नहीं	
घटाए : के. लो. नि. वि. द्वारा वापिस की गई राशि		58,014.51	13,613,016.66
फर्नीचर और फिक्सचर, स्टाफ कार समेत, टाइपराइटर, संगणक आदि			
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि		7,773,715.23	
वर्ष के दौरान परिवर्धन		752,726.50	
घटाएं (संशोधन 1988–89)	4,735.80	25,735.80	8,500,705.93
	5,000.00		
	16,000.00		

पुस्तकालय की पुस्तकें

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	2,019,357.56	
वर्ष के दौरान पुस्तकालय पुस्तकों में परिवर्धन	180,522.00	
वर्ष के दौरान प्रलेखन में परिवर्धन	303.00	
उपहारों के द्वारा कारण परिवर्धन	2,063.00	2,202,245.56

1989-90

देयताएं

परिवर्धन समायोजन संशोधन	58,014.51	
घटाएं (समायोजन)	1,554,295.58	
घटाएं (संशोधन)	10,537.00	5,546,944.89
निर्धारित कार्यक्रम और अध्ययन		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	1,215,784.11	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,445,353.45	
घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय	1,895,201.60	765,935.96
भविष्य निधि		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	2,622,150.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,601,708.00	
वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	1,318,970.00	2,904,888.00
उचंत लेखा		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	32,809.17	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	24,539.00	
घटाएं : वर्ष के दौरान	31,145.00	26,203.17

1989-90

परिसंपत्तियां

भविष्य निधि का निवेश

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	2,180,000.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	650,000.00	
घटाएं : निकाली गई राशि	200,000.00	2,630,000.00

जमा

पिछली तालिका की अनुसार शेष राशि	52,990.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
घटनाए : वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	–	52,990.00

के. लो. नि. वि. के पास जमा

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	3,196,637.78	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,141,735.00	
परिवर्धन संशोधन (1986–87)	58,014.51	
घटाएं : वापसी	211,535.82	
घटाएं समायोजन	1,554,295.58	2,630,555.89

1989-90

देयताएं

उपहार और दान

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	2,574.31	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,063.00	4,637.31

जमा

पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	9,500.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,500.00	
घटाएं : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	9,500.00	2,500.00
	योग	33,562,440. 17

ओ. पी. शर्मा
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1989-90

परिसंपत्तियां

वसूली योग्य पेशगियां		
मोटर कार पेशगी	391,628.00	
भवन निर्माण पेशगी	500,024.00	
त्यौहार पेशगी	17,360.00	
साइकिल पेशगी	7,070.00	
स्कूटर पेशगी	101,765.00	
संगणक पेशगी	87,085.00	
पंखा पेशगी	440.00	
विविध पेशगी (नीपा)	3,375.00	
स्थानांतरण पेशगी (टी. ए.)	7,000.00	1,115,747.00
विविध पेशगी (एन. सी. टी. II)		24,760.90
प्रेषित राशि		
जी. एस. एल. आई. योजना)		1,904.00
देनदार		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	8,235.70	
घटाएं : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-	
घटाएं : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	2,150.00	6,085.70
रोकड़ जमा		
हस्तगत रोकड़	1,137.00	
अग्रदाय	1,000.00	
चालू खाता	2,507,403.53	
सा. भा. नि./अ. भ. लेखा	274,888.00	2,784,428.53
	योग	33,562,440.17

सत्य भूषण
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
वर्ष 1989–90 के दौरान निर्धारित कार्यक्रम/अध्ययन के लिए प्रपत्र (31. 3. 1990)

क्र. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थ शेष (14.89)	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
	भारत सरकार					
	गृह मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग					
1.	अ. जा. के शैक्षिक विकास का अध्ययन एकक	(–) 116,398.25	-	(–) 116,398.25	-	(–) 116,398.25
2.	राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-II (i) केन्द्रीय तकनीकी एकक (ii) आयोग के दौरे के लिए संगठन	134,665.05	-	134,665.05	5,701.50	128,963.55
3.	अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रायोगिक परियोजना-एक मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा मंत्रालय)	24,923.36	-	24,923.36	-	24,923.36
4.	केब समिति–शिक्षकों का स्थानांतरण	65,082.00	-	65,082.00	29,524.00	35,558.00
5.	प्रबंध पर केब समिति बैठक	(-) 17,442.00	17,442.00	-	-	कुछ नहीं
6.	अनौपचारिक शिक्षा (कोप) समिति प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के लिए प्रायोगिक और नवीन कार्यक्रम	5,778.00	232,534.00	238,312.00	204,717.60	33,594.40
7.	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एम. आई. एस. (एस. दासगुप्ता)	200,380.00	110,800.00	311,180.00	337,611.10	(-) 26,431.10

क्र. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थ शेष (14.89)	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
	योजना आयोग					
8.	शिक्षा और रोजगार के बीच लाभदायक संबंधों का अध्ययन	13,372.90	-	13,372.90	-	13,372.90
9.	वर्तमान सुविधाओं का बेहतर उपयोग	-	28,000.00	28,000.00	19,884.00	8,116.00
	आई. सी. एस. एस. आर. नई दिल्ली					
10.	भारत में सामाजिक विज्ञान से संबंधित अनुसंधान के लिए वित्त व्यवस्था पर अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत एकत्रित आकंड़ों का विश्लेषणात्मक मोनोग्राफ का निर्माण भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान	9,269.60	-	9,269.60	-	9,269.60
	दिल्ली नगर निगम					
11.	शिक्षण आबंटन के प्रतिमान निर्धारित लिए अध्ययन दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण और प्रशासनिक स्टाफ के लिए	(–) 7,410.60	7,410.60	-	-	कुछ नही
	अंर्तराष्ट्रीय कार्यक्रम और अध्ययन					
12.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा	721,461.39	716,386.50	1,437,847.89	975,743.25	462,104.64

क्र. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थ शेष (1489)	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
13.	उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम : शिक्षण प्रविधि	17,579.15	-	17,579.15	-	17,579.15
14.	पर्यावरण शिक्षा पर परामर्श बैठक	10,136.75	-	10,136.75	-	10,136.75
15.	व्यष्टि स्तरीय शैक्षिक योजना पर क्षेत्रीय विकास कार्य शिविर	29,777.67	-	29,777.67	-	29,777.67
16.	ए. पी. ई. आई. डी. योजना मंडल बैठक	3,775.40	-	3,775.40	-	3,775.40
17.	उच्च शिक्षा में समता' गुणवत्ता और व्यय पर अध्ययन	20,954.13	-	20,954.13	-	20,954.13
18.	उच्च शिक्षा के लिए संसाधन की प्रविधि पर एक परियोजना	(-) 35,120.00	25,000.00	(–) 10,120.00	440.00	(–) 10,560.00
19.	संगणकों का प्रभावशाली उपयोग वि. अनु. आ. द्वारा प्रायोजित	-	40,000.00	40,000.00	8,000.00	32,000.00
20.	विकेंद्रीकरण के लिए व्यष्टि स्तरीय शैक्षिक योजना और प्रबन्ध (डा. ब्रह्म प्रकाश)	8,944.61	–	8,944.61	-	8,944.61
21.	पर्यावरण शिक्षा (यूनेस्को) पर अंतर क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (डा. आर. गोविन्द)	126,054.95	-	126,054.95	40,495.80	85,559.15
22.	मंत्रालय स्तरीय पुनरीक्षण सम्मेलन	-	73,780.35	73,780,35	73,780.35	-

क्र. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थ शेष (14.89)	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
23.	जि. शि. अ. के लिए छः सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	194,000.00	194,000.00	199,304.00	(-)5, 304.00
	योग	1,215,478.11	1,445,353.45	2,661,137.56	1,895,201.60	765,935.96

ओ. पी. शर्मा
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

सत्य भूषण
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
वर्ष 1989–90 के लिए सा. भा. नि. (अ. भ. नि.) की प्राप्ति और भुगतान का लेखा

प्राप्तियां		भुगतान		
अर्थ शेष	442,150.00	पेशागियों और निकासी		1,318,970.00
अंशदायी और पेशगियों की वापसी	1,266,178.00	जमा से व्यय	650,000.00	
		निकासी घटाएं	200,000.00	450,000.00
ब्याज, नियोक्ताओं का अंशदान इत्यादि	335,530.00	अंत शेष		274,888.00
योग	2,043,858.00			2,043,858.00

ओ. पी. शर्मा
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

सत्य भूषण
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के 31 मार्च 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे और तुलनपत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में तथा मेरी सर्वोतम जानकारी और मुझे दिए स्पष्टीकरण तथा संस्थान की बहियों में दर्शाये गए लोगों के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपर्युक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह.

(धर्मवीर)
मुख्य निदेशक, लेखापरीक्षा
केंद्रीय राजस्व

नई दिल्ली
2/1/1991

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(वर्ष 1989-90 के लिए)

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) पहले शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1980 के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया था। 31 दिसंबर 1970 को इसे शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से पंजीकृत किया गया और 31 मई 1979 को पुनः इसे वर्तमान नाम के आधार पर पंजीकृत किया गया। संस्थान का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक योजना और अनुसंधान के क्षेत्र में मार्गदर्शन कराना और प्रशिक्षण अनुसंधान की व्यवस्था करना तथा उसे आगे बढ़ाना है।

संस्थान की वित्त व्यवस्था का प्रबंध केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान पर आधारित है। वर्ष 1989-90 के दौरान नीपा ने लगभग 137.50 लाख रुपए (योजनेतर 80.50 लाख रुपए और योजना 57 लाख रुपए) प्राप्त किए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान का अंकेक्षण (कार्य, शक्ति और सेवाशर्तें) किया जाता है।

2. लेखा संबंधी टिप्पियां

2.1 परिसंपत्तियों का मूल्यांकन :

संस्थान के पास 31 मार्च 1990 में स्थायी परिसंपत्तियां 243.16 लाख रुपए थी जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

		(रु. लाख में)
(i)	भूमि और भवन	136.13
(ii)	फर्नीचर तथा वाहन आदि	85.01
(iii)	पुस्तकालय की पुस्तकें	22.02
		243.16

संस्थान ने सभी परिसंपत्तियों के ब्यौरेवार विवरण वाले संपत्ति तथा स्टाफ रजिस्टर पूरे नहीं किए हैं। फलस्वरूप दिनांक 31 मार्च 1990 को संस्थान तुलना पत्र में दिखाई गई परिसंपत्तियों का मूल्य सत्यापित नहीं किया जा सका। इस प्रकार की अनियमिता की पुष्टि पहले के लेखा परीक्षा की रिपोर्टों में भी की गई थी। संस्थान ने जनवरी 1991 में स्वीकार किया कि आगे इसका ध्यान रखा जाएगा।

2.2 बकाया विविध पेशगी

राष्ट्रीय अध्यापक आयोग-IIके संबंध में एक कार्यशिविर का आयोजन करने के लिए संस्थान ने एक योजना (अध्यापक-II के लिए राष्ट्रीय आयोग) के अनतर्गत अनुसंधान कार्य करने के लिए वर्ष 1983-84 में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा शोधकर्ताओं को 2.95 लाख रुपए बतौर पेशगी दिए। 31 मार्च 1990 तक उपर्युक्त रकम में से 0.25 लाख रुपए विभिन्न एककों के प्रति वकाया हैं। राष्ट्रीय संस्थान की ओर से यह कहा गया है कि उन्होने विभिन्न विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे रकम को समायोजित करें।

2.3 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बकाया जमा राशि (कें.लो.नि.वि.)

31 मार्च 1990 तक कें.लो.नि.वि. के पास विभिन्न भवन निर्माण कार्यों के लिए लगभग 26.31 लाख रुपए बकाया जमा राशि हैं। वर्ष 1983-84 से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है :

जमावर्ष	बकाया राशि (लाखों में)
1983-84	0.88
1984-85	0.24
1987-88	12.37
1988-89	4.29
1989-90	8.53
योग	26.31

2.4 भेंट में प्राप्त पुस्तकों के मूल्य न लगाना

विभिन्न अभिकरणों से 31 मार्च 1990 तक राष्ट्रीय संस्थान ने 146 पुस्तकें भेंट के रूप में प्राप्त की हैं। राष्ट्रीय संस्थान ने इन पुस्तकों का मूल्य अंकित नहीं किया है और तुलनपत्र में 'भेंट तथाचंदा' के अंतर्गत इसे न तो परिसंपत्तियों में दर्शाया गया और न ही इसे देय में दर्शाया गया ।

राष्ट्रीय संस्थान की ओर से दिसंबर 1990 में कहा गया कि इन पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

2.5 संभूति के आधार पर लेखा का तैयार न किया जाना

अंकेक्षण के लिए दिए गए विवरणानुसार 31 मार्च 1990 तक छात्रावास किराए के रूप में 8020/-रूपए बाकी हैं। वार्षिक खाते में यह बकाया राशि यह कहकर नहीं दिखायी गयी कि राष्ट्रीय संस्थान का खाता वास्तविक आधार पर तैयार किया गया है।

वर्ष 1988-89 के अंकेक्षण रिपोर्ट में भी इसी तरह की असमानता दिखाई गई हैं।

3. नियत कार्यक्रम/अध्ययन पर हुए 1.59 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय की अप्रतिपूर्ति

राष्ट्रीय संस्थान ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित कई अध्ययन आयोजित किए। यह संस्थान विभिन्न अभिकरणों से उनके द्वारा प्रायोजित किए जाने वाले अनुसंधान अध्ययनों के एवज में अनुदान प्राप्त करती है। वर्ष 1989-90 की रिकार्ड की जांच करने से पता चलता है कि राष्ट्रीय संस्थान ने चार कार्यक्रम/योजना पर 1.59 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय का वहन किया है जिसकी प्रतिपूर्ति की प्रतीक्षा की जा रही है। संस्थान की ओर सें दिसंबर 1990 में यह कहा गया कि वर्ष 1990-91 में तीन कार्यक्रमों के लिए 0.42 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में गृह मंत्रालय से विचार विमर्श किया जा रहा है जिनकी तरफ से बाकी बकाया निकलता है।

4. अनुदान में 7.60 लाख रूपए की रुकावट की वजह से निर्माण कार्य में विलंब

राष्ट्रीय संस्थान की सात मंजिला इमारत में अतिरिक्त वार्डन आवास तथा कार्यालय के लिए कमरे आदि बनाने के उद्देश्य से के.लो.नि.वि. ने मार्च 1983 में योजना सहित 1.62 लाख रुपए की लागत बतायी थी।

वास्तुकार द्वारा तैयार किया गए डिज़ाइन और राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर के.लो.नि.वि. ने फरवरी 1984 में 7.60 लाख रूपयों का पूर्व निर्माण योजना तैयार किया।

राष्ट्रीय संस्थान ने के.लो.नि.वि. के पास क्रमशः मार्च 1983 (1 लाख रूपया), मार्च 1984 (2.15 लाख रुपया), मार्च 1985 (4.45 लाख रुपया) में कुल 7.60 लाख रुपए जमा किए। मार्च 1986 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस नक्शे की नगर कला आयोग के पास अनुमोदन और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया।

के.लो.नि.वि. ने जनवरी 1986 में निर्धारित योजना की लागत का संशोधन करके इसे 9.37 लाख रुपए बताया और राष्ट्रीय संस्थान ने इसे मई 1989 में अनुमोदित करके लौटा दिया। के.लो.नि.वि. द्वारा इसे अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया (सितंबर 1990)। इसी बीच निर्माण पुनरीक्षण समिति ने मार्च 1986 सें छात्रावास की सुविधाओं के स्तर को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कार्यकारी समिति की फरवरी 1990 को हुई 30 वीं बैठक का विचार था कि वार्डन आवास तथा डाईनिंग हाल आदि पूर्व निर्धारित प्रस्ताव के अनुसार दीर्घावधि संबंधी आवश्यकताओं जैसे विस्तृत जगह आदि की पूर्ति नहीं कर पाएंगी। अतः उन्होंने पुनः इसका संशोधन करने का निर्णय ले लिया।

इस संशोधन कार्य को सथगित रखे जाने की वजह से राष्ट्रीय संस्थान वे के.लो.नि.वि. को यह सलाह दी कि वे इन पैसों का उपयोग अन्य निर्माण कार्य जैसे : प्रशासन के लिए तीसरी मंजिल का निर्माण आदि के लिए करें। कार्यकारी समिति ने फरवरी 1990 को अनुदान के व्यय, संशोधित योजना और छात्रावास के लिए पूर्वनिर्धारित 67.89 लाख रुपए आदि को अनुमोदित किया। राष्ट्रीय संस्थान ने मार्च 1990 में के.लो.नि.वि. के पास 6 लाख रुपए और जमा किए। इस पर कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

योजना को ठीक तरह से न बना पाने और इसे अंतिम रूप में देने में विलंब होने के कारण पांच से भी अधिक सालों तक के लिए 7.60 लाख रूपयों को व्यर्थ में रोका गया। मंत्रालय के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय संस्थान ने अन्य योजनाओं के लिए इस राशि का उपयोग किया। राष्ट्रीय संस्थान की ओर से दिसंबर 1990 को कहा गया कि अनुदान का उपयोग बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थगित प्रस्ताव के अनुसार तीसरी मंजिल के निर्माण के लिए उपयोग किया गया।

ह.

(धर्मवीर)
मुख्य निदेशक लेखा परीक्षा
केंद्रीय राजस्व

वर्ष 1989-90 की अंकेक्षण रिपोर्ट का अनुच्छेदवार टिप्पणी

अनुच्छेद 1: प्रस्तावना : कोई टिप्पणी नहीं

अनुच्छेद 2.1 परिसंपत्तियों का मूल्यांकन : संपत्ति रजिस्टर तथा स्टाक रजिस्टर सें संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया। अगले अंकेक्षण में इस रिकार्ड का सत्यापन किया जाएगा।

अनुच्छेद 2.2 बकाया विविध पेशगी : 31 मार्च 1990 तक 24,760 रुपए (चौबीस हजार सात सौ साठ रुपए) बकाया है। इसमें से चालू वर्ष (31/10/90) के दौरान 297 रुपए/- समायोजित किए गए हैं। जिन विश्वविद्यालयों ने अपना लेखा प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें उनके नाम से बकाया शेष राशि का समायोजन या रुपए वापस लौटाने की इत्तला दी जा रही है। इसी बीच बरखतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के कुलसचिव ने एस.बी.आई. विश्वविद्यालय शाखा, भोपाल को यह सलाह दी है कि वे डिमांड ड्राफ्ट की अतिरिक्त प्रति या विश्वविद्यालय के नाम बकाया 10, 446.46 रुपए दें और आशा की जाती है कि यह राशि शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति डा. भास्कर राय चौधरी जो यहां नई शिक्षा नीति के पुनरीक्षण बैठक में भाग लेने के लिए आए हुए थे उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे इस मामले की व्यक्तिगत जांच करेंगे और बैंक को सलाह देंगे कि विश्वविद्यालय के नाम बकाया 10,241.94 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट प्रेषित कर दें। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आशा की जाती है कि चालू वर्ष के दौरान इस पेशगी को समायोजित कर ली जाएगी।

अनुच्छेद 2.3 : केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के पास बकाया राशि: बकाया पेशगी के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित सिविल तथा इलेक्ट्रिकल निर्माण और संचालन प्रभाग विशेषकर के.लो.नि.वि. के जारी कार्य और संपन्न कार्यों से संबंधित व्यय के विवरण को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान के निर्माण पुनरीक्षण समिति की बैठक हर पखवाड़े होती है जिसमें के.लो.नि.वि. के अधीक्षक/कार्यपालक और सहायक अभियंता शामिल होते हैं। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया है कि हमारे कार्यों पर हुए खर्च को पूरा लेखा विवरण शीघ्र प्रस्तुत करेंगे।

अनुच्छेद 2.4 : भेंट स्वरुप प्राप्त पुस्तकों का मूल्य न लगाना : संस्थान ने भेंट में प्राप्त हुई मूल्य रहित पुस्तकों के मूल्य के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय उपयुक्तता के आधार पर इन पुस्तकों का मूल्य निरूपण किया जा रहा है।

अनुच्छेद 2.5 : संभूति के आधार पर लेखा का तैयार न किया जाना : वर्ष 1990-91 के लिए ई.सी./एफ.सी.ने संभूति के आधार पर लेखा तैयार करने की स्वीकृति दे दी है और इसको उसी आधार पर तैयार किया जाएगा लेकिन लेखा के प्रारूप की स्वीकृति प्रति डी.ए.सी.आर. को जरूरी संसोधन के लिए दे दी गई।

अनुच्छेद 3 : निर्धारित कार्यक्रम/अध्ययन में 159 लाख रुपए के अतिरिक्त खर्चे का बकाया: कल्याण मंत्रालय के प्रति 1.16 लाख रुपए की बकाया राशि बनती है। इस संबंध में संबंधित मंत्रालय से उच्च स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है।

अनुच्छेद 4 7.60 लाख रूपयों की अनुदान में रुकावट की वजह से निर्माण कार्य में विलंब :7.60 लाख रुपयों में से (मार्च 1983 में 1लाख रुपए), (मार्च 1984 में 2.15 लाख रुपए) और मार्च 1985 में 4.45 लाख रुपए) कें.लो.नि.वि. के निर्माण विभाग I के पास जमा किया गया ताकि वार्डन आवास, कार्यालय के लिए कमरे, भंडार कक्ष बाहर से आए हुए संकाय सदस्य के लिए आराम कक्ष सूट और रसोईघर की सुविधाओं का विस्तार और इसके स्तर को बढ़ाने आदि से संबंधित कार्य किया जा सके। कें.लो.नि.वि. की आवश्यकता और मांग को ध्यान में रखते हुए यह राशि जमा की गई। आरंभ में निर्धारित 7.60 लाख रुपयों के अनुमोदन के आधार पर ऐसा किया गया। किंतु कें.लो.नि.वि. के आरकिटेक्ट द्वारा तैयार किए गए चित्र और डिज़ाइनों का अध्ययन करने के बाद यह नतीजा निकाला गया कि प्रस्तावित निर्माण कार्य में परिवर्तन आदि लंबी अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होगा। इस संपूर्ण निर्माण कार्य को स्थगित रखने की वजह से के.लो.नि.वि. के पास जमा राशि में से 7.50 लाख रुपयों को प्रशासन खंड के लिए तीसरी मंजिल के जारी निर्माण कार्य में लगा दिया गया। केवल .10 लाख रुपए के.लो.नि.वि. के पास रहने दिया ताकि संस्थान में से विविध कार्यों पर हुए व्यय की भरपाई हो सके। तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और पूरे 7.50 लाख रुपयों का उपयोग इस कार्य के लिए किया गया। गहन पुनरीक्षण कार्य के बाद संस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, छात्रावास के स्तर को संशोधित योजना और डिज़ाइन के अनुरूप बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिए 6/2/90 को हुई तीसवीं बैठक में एफ.सी./ई/सी. द्वारा 67.85 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई। के.लो.नि.वि. की मांग के अनुसार मार्च 1990 में 6 लाख रूपए उनके पास जमा किए गए हैं

दिल्ली नगर निगम और नगर विकास विभाग के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। संबंधित अधिकारियों से मामले पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

अत: यह देखते हुए कि उपर्युक्त कार्य में अनुदान में कोई रूकावट नहीं आई अत्यंत प्रशंनीय है किंतु छात्रावास के स्तर में वृद्धि करने की योजना को स्थगित रखे जाने की वजह से संस्थान की विस्तृत मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक खंड की तीसरी मंजिल के निर्माण कार्य के लिए अनुदान को उपयोग में लाया गया।

LIBRARY & DOCUMENTATION C
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D 9370
Date 5.12.96

NIEPA DC
D09370